हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 23 मार्च, 1995

पृष्ठ संख्या

शहीद–ए–आजम सरदार भगत सिह तथा उनके सहयोगियों को श्रद्धांजलि	(12)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर –	(12)1
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनायें –	(12)26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
थर्मल पावर प्लांट पानीपत के गन्दे पानी तथा राख के कारण प्रदूषण से बीमारियां फैलने सम्बन्धी	(12)28
वक्तव्य–	
वन मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(12)28
समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना–	
(1) लोक–रेखा समिति	(12)35
(2) आश्वासन समिति	(12)36

(3) अनुसूचित जातियों तथा जनजाति कल्याण समिति	(12)36
(4) प्राक्कलन समिति	(12)38
वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान –	(12)36
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
चौधरी बंसी लाल द्वारा	12(62)
वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12) 64
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
चौधरी बंसी लाल द्वारा	(12)67
वर्ष 1996–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)68
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
चौधरी बंसी लाल द्वारा	(12)71
वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)71
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	

चौधरी बंसी लाल द्वारा	(12)72
वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)73
वाक आउट	(12)77
वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)78
बैठक का समय बढ़ाना	(12)81
वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों कीं मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)81
बैठक का समय बढ़ाना	(12)88
वर्ष 1995–96 के– बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)89
बैठक का समय बढ़ाना	(12)92
वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)92
बिल्ज–	
(1) पण्डित भगवत दयाल शर्मा आयुविज्ञान महाविद्यालय,	(12)100

रोहतक (अध्यापक सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1995	
(2) हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैंशन) संशोधन विधेयक, 1995	(12) 101
बैठक का समय बढ़ाना	(12)103
बिल्ज (पुनरारम्भ)	
(3) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1995	(12)103
(4) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1995	(12)105
(5) पंजाब भू–दान यज्ञ (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1995	(12)106
बैठक का समय बढ़ाना	(12)108
बिल्ज (पूनरारम्भ)	
(6) हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1995	(12)108

हरियाणा विधान सभा

वीरवार 23 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाण विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

शहीद–एर–आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों को श्रद्धांजलि

Mr. Speaker : Hon'ble Members now the Chief Minister will move a resolution.

मुख्य मंत्री (चौ० भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आज सारा देश ऐसे तीन महान सपूतों, शहिद–ए–आजम भगत सिंह , राजगुरू और सुखदेव का शहीदी दिवस बना रहा है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आज ही के दिन 23 मार्च, 1931 को लाहौर सैन्ट्रल जेल में हंसते–हंसते फांसी के फन्दे को चूमा था।

इन तीनों महान् देश–भक्तों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने वीरतापूर्ण कार्यों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिलाकर रख दी थी।

अग्रेज सरकार इन युवा देश–भक्तों एवं क्रांतिकारियों से इतना अधिक खौफ खाती थी कि जन–आक्रोश के डर से, उसने भारत माता के इन तीनों महान सपूतों भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को निश्चित तिथि से पूर्व ही, चुप–चाप 23 मार्च, 1931 की शाम को फांसी दे दी। ऐसा करके अंग्रेज सरकार ने न केवल अपनी कायरता का परिचय दिया, बल्कि देश के लाखों नर–नारियों को इन महान युवा देश–भक्तों के अंतिम दर्शनों से भी वंचित कर दिया था।

इन क्रांतिकारी देश–भक्तों तथा अन्य लाखों देश–प्रेमी सपूतों की कुर्बानियों का ही यह नतीजा है कि आज हम स्वतन्त्र भारत में सुख की सांस ले रहे हैं।

यह सदन भारत माता के इन तीनों महान सपूतों, भगत सिह, राजगुरू और सुख–देव और उन सारे शहीदों को जिन्होंने देश की स्वतंन्त्रता के लिए अफने प्राणों की आहुति दी, को आज शहीदी दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

देश प्रेम के लिए इन महान सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान की कहानी हमें हमेशा राष्ट्र–प्रेम तथा देश के नव–निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। इसी संकल्प के साथ हम एक बार फिर इन महान सपूतों को याद करते हुए नतमस्तक होकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते है 1

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, सरदार भगत सिह, सुखदेव और राजगुरू ने देश के लिए शहादत दो है। उस वक्त हुक नरम दल था और हुक गरम दल था। गरम दल में लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल आदि नेता थे जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे इसके अलावा हमारे कुछ नौजवान भी जैसे चन्द्र शेखर आजाद वगैरह ने भी अपनी शहादत दी। ये लोग अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देना चाहते थे ताकि उनके कानो तक यह आवाज जाए कि देश में अग्रेज जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक नहीं है और वे देश के हितों के खिलाफ चल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी शहादत दी। वे बहुत ही बहादुर थे और उनमें किसी भी किस्म का डर नही था, वे देश प्रेम से ओत प्रोत थे। अंग्रेज सरकार ने उनका फांसी देकर रातों रात सतलुज नदी के किनारे उनकी लाशें जलायी। इनके सारे अश हैं। लाशें जलाने के बाद उनको उन्हेंने दरिया में बहा दिया लेकिन फिर भी रातों रात ही बहुत से लोंग वहां पर इकट्ठे हो गए क्योंकि उनको इस बात का पता लग गया था तो डस तरह से ये लोग शहीद हो गए और इस तरह उन्होंने देश प्रेम की एक मशाल जलायी। उन्हें ऐसा करते देखते हुए देश के और नौजवानों में भी एक हौंसला पैदा हुआ और उसी के फलस्वस्वरुप यह देश आजाद हआ, जिसकी वजह से आज यह तरक्की हमारे सामने हुई है।

अब मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप दो मिनट का मौन धारण करे।

(इस समय सदन ने दो मिनट का मौन धारण दिया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Construction of New Roads

***1102. @Shri Dhir Pal Singh:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the total amount spent on the construction of new roads/repair of roads in Jhajjar and Bahadurgarh Sub-Divisions during the period from June, 1991 to December, 1994 yearwise separately ?

Public Works Minister (Shri Amar Singh) : The expenditure details are as under :—

Sr. No.	Particulars	Jure 91 to March, 92 (Rs. Lacs)	Year 92-93 (Rs. Lacs)	Year 93-94 (Rs. Lacs)	April, 1994 to Dec., 94 (Rs. Lacs)
1.	On construction of new roads	45.92	22.34	17.61	20.86
2.	On repair of roads	188.13	94.05	149 18	110.31

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मती से जी जानना चाहता हूं कि 1991– 92 के बाद से

लगातार बजट में यह घटौती क्यों आई। जैसे नए रोड बनाने पर 1991– 92 में 45.92 लाख है और 1993– 94 में 17.61 लाख है, इसी तरह रिपेयर पर 1991– 92 मे 188.13 लाख है और 1994 मैं 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार रुपया है। सारी सडके टूटी पड़ी हैं, आप रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मन्त्री जी यह समझते हैं कि सारी सड़कें बड़ी सुन्दर हैं। मैं जानना चाहूगा कि क्या इनमें और पैसा वढ़ाने का प्रावधान करेंगे? इसके साथ साथ मै यह भी जानना चाहूंगा कि क्या करगा है? इनके तहत कम बजट खर्च किया गया?

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रान्त ही ऐसा प्रान्त है जिसमें टोटल गांव रोड्स से जुड़े हुए हैं। हरियाणा में टोटल रोड्ज 21579 किलोमीटर है जिसमें से 3135 किलोमीटर स्टेट हाइवे हैं और मेजर रोड्ज 1587 किलोमीटर हैं और रुरल रोड्ज 16857 किलोमीटर है। जहां तक नयी रोड्ज की कंस्ट्रक्शन और रिपेयर पर कम पैसा खर्च करने की बात है, उसके बारे में हें बताना चाहूंगा कि जब हम. नई रोड कंस्ट्रक्ट करते है उसमें पहले साल में अर्थ वर्क, सोलिग वगैरह होता है, उसमें खर्च अधिक आता है। वर्ष 1991– 92 में रोड्ज की रिपेयर पर 1 करोड़ 88 लाख 13 हजार रुपया खर्च किया। उसके बाद साल दो साल रोड चलती रही। उसके बाद इस बार हमने रिपेयर पर 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार रुपया खर्च किया है। सारे हरियाणा में सड्कों का पैचवर्क हुआ है जो 313, किलोमीटर रोड हैवी रेन्ज और फ्लड

से टूटी थी, उनको ठीक कर दिया गया है। अव ऐसी कोई रोड नही है जो बननी हो।

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, जैसाकि कल माननी व सदस्य श्री सूरज मल जी ने बताया था कि उनका हल्का दिल्ली के साथ जाता है और दिल्ली के मुकाबले हरियाणा की सड़क देखें तो हमे शर्म आती है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, आखिर रोहतक जिले के साथ यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वर्ष 1991–92 का बजट हमारी सरकार ने पास किया था, उसके बाद इनका सरकार आ गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भेदभाव की नीति की वजह से रोहतक जिले में सडको की रिपेयर और बनाने पर कम खर्च नही कर रहे है?

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, अगर यह बात कोई और भाई बोले तो जच सकती है। इन्हेंने तो अपने पौने चार साल के शासन काल में एक ईंट भी नहीं लगाई। कोई रोड बता दें जो इन्होने बनवाई हो। जो फलडिड एरियाज है उनमें रोड टूट जाती हैं जिनकी वजह से काफी नुक्सान होता है। स्पीकर साहब, शायद इन्होंने हमारे जवाब को पढ़ा नही है। हमने हर साल रिपेयरिंग पर ज्यादा खर्चा दिखलाया है। वह 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार है, जोकि अप्रैल, 1994 से दिसम्बर 1994 तक का है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने झज्जर और बहादुरगढ़ सब–डिवीजन्ज में रोडज की रिपेयर का

और नई सडकें बनाने का इकट्ठा ही जवाब दे दिया है। इसलिये वे बताएं कि झज्जर सब डिवी जन में रोडज की रिपेयरिंग व नई रोडज बनाने के लिये और बहादुरगढ़ सब–डिवीजन में रोडज की रिपेयरिंग व नई रोडज बनाने के लिये सरकार ने कितना–कितना पैसा खर्च किया है। यह अलग से बताए। इमके साथ साथ मैं इनके झज्जर सब–डिवीजन की कुछ सड़को के नाम बताता हूं जो बिलकुल टूटी हुई हैं, जैसे झज्जर से बेरी, झज्जर से गुडियानी, झज्जर मे साहलावास, झज्जर से सापलां वगैरह, और भी कई सड़कें इस तरह की हैं जोकि बिल्कुल चलने कें काबिल नहीं हैं। कहीं यह बात तो नही है कि सड़को की रिपेयरिंग केवल काजो में ही कर ली गई दिखाई हो और ऐंक्चूअल वर्क कोई न किया गया हो। मन्त्री महोदय बेशक मौके पर मेरे साथ चल कर देख लें कि कहीं रिपेयर वर्क हुआ भी है या नही। मैं इनके जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिये पुनः बताएं कि बहादुरगढ़ सब डिवीजन व झज्जर सब–डिवीजन में सड्कों की रिपेयर की व नई सड़कों की अब क्या हालत है?

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सब सें पहले मेरे आदरणीय सदस्य ने जो नई सड़को के निर्माण पर जो खर्चा हुआ है, उसके बारे में पूछा है, वह मैं बता देता हूं। 1991– 92 में झज्जर सब डिवीजन में नई सड्कों का निर्माण हुआ 3.55 किलोमीटर, सोलिग की गई 8.85 किलोमीटर, मैटलिंग की गई 6. 56 किलोमीटर 1 बहादुरगढ़ सब–डिवीजन मे 1991– 92 मे 2.49

किलोमीटर अर्थ वर्क, 7.69 किलोमीटर सोलिंग और मैर्टालग की गई 6.77 किलोमीटर। टोटल इन पर खर्चा आया 45.92 लाख रुपये। इसी तरह से वर्ष 4/92 से 3/93 तक बहादुरगढ़ सब–डिवीजन में 0.17 किलोमीटर अर्थ वर्क, 1.83 किलोमीटर सोलिग और मैटलिग की गई 3.58 किलोमीटर। झज्जर सब–डिवीजन में केवल मैटलिग वर्क हुआ 2.12 किलोमीटर इस पर खर्चा आया 23 34 लाख रुपये। इसी तरह से 4/93 से 3794 तक झज्जर सब–डिवीजन में अर्थ वर्क और सोलिग 0.20 किलोमीटर की गई। मैटलिग हुई 0.20 किलोमीटर और बहादुरगढ़ सब–डिवीजन में 0.11 किलोमीटर में अर्थ वर्क, 0.36 किलोमीटर में सोलिग और 0.36 किलोमीटर में मैटलिग का कार्य हुआ जिसका खर्चा आया 1.61 लाख रुपये। इससे आगे मैं 4794 से 12794 तक की पोजीशन बताता हूं। झज्जर सब–डिवीजन में 0.65 किलोमीटर अर्थ–वर्क, 0.25 किलो मीटर सोलिग और 0.25 किलो मीटर मैटलिग वर्क हुआ और बहादुरगढ़ सब–डिवीजन में 1.75 किलोमीटर अर्थ–वर्क हुआ इस काम पर 20.86 लाख रुपये खर्चा बैठता है।

इसी तरह से मैन्टीनैन्स/रिपेयर वर्क की ईयर–वाईज फिग्गर्ज इस प्रकार है:–

जून 1991 से मार्च, 1992 तक पैच वर्क पर 18.22 लाख रुपए, रिन्यूअल नोट और सरफेसिग पर 27.02 लाख रुपए, स्पैशल रिपेयर पर 86.70 लाख रुपए, मिसलेनियस पर 55.69 लाख रुपए,

टोटल 1 करोड़ 88 लाख 13 हजार रुपये खर्च आया। 1992– 93 में पैच वर्क पर 33.26 लाख रुपए रिन्यूअल कोट और सरफेसिंग पर 36.13 लाख रुपए, स्पैशल रिपेयर पर 21.92 लाख रुपए, मिसले– नियस 2.74 लाख रुपये, टोटल 94.05 लाख रुपये खर्च हुए। 1993– 94 में पैच वर्क पर 40.94 लाख रुपए, रिन्यूअल कोट पर 28.08 लाख रुपए स्पैशल रिपेयर पर 10.78 लाख रुपए और मिसलेनियस पर 69.38 लाख रुपए टोटल 149.18 लाख रुपये खर्च हुए। इसी तरह से अप्रैल 1994 से दिसम्बर, 1994 तक पैच वर्क पर 27.17 लाख रुपए, रिन्यूअल कोट पर 37.47 लाख रुपए, स्पैशल रिपेयर पर 27.03 लाख रुपए, मिसलेनियस पर 18.64 लाख रुपए इस पर टोटल 1 करोड़ 10 लाख 31 हजार रुपये खर्च हुए। इस तरह से यह अलग–अलग पोजीशन झज्जर सब–डिवीजन व बहादुरगढ़ सब–डिवीजन कि जो नई सड़के की थी और दूसरी मुरम्मत की थी, वह मैंने बता दी है। जहां तक बादली, छारा व बेरी की सड़कों का सवाल है, आनरेबल मैम्बर ने गांव दुबलधन के बारे में बताया बै कि वे वहां पर कच्ची नाली है, उस पर बन्द लग। दिया गया है आनरेबल मैम्बर उसको खुलवा दें तो रोडज ठीक हो जाएगी। इसी' तरह से छारा में इन्होंने पांच सी मीटर नाली वन्द कर दी और गांव के लोगों ने उसे खोलने नही दिया। वहां पर हमारे एस० ई० कल गए ने। उन्होंने कहा कि यह रोड टूट रही है, आप पानी को निकलने दे लेकिन वे लोग लट्ठ ले कर खड़े हो गए। इसी तरह सै हमारे भाई धीर पाल सिंह जी के

बादली हल्के में 15 मीटर नाली पर कलवर्ट लगा रखा है। तो ये खुद तों रौड कौ तोड़ने की बात करते हैं।

चौधरी सुरज मलः स्पीकर साहब, यहां पर बादली की रोडज का जिक्र आया है। चौधरी अमर सिंह ने बताया कि बहादुरगढ हल्के के अन्दर सडकों का काम शुरू कर दिया है। लूनामाजरा से कसार ने–शनल हाई–वे पर एक सड़क बनी थी। उस पर केवल तीन इंच रोड़ी पड़ी है और दो सौ मीटर के अन्दर तो थोड़ा सा बुरादे के तौर पर ही तारकोल डाला है और बाकी सारा वैसे ही पड़ा है। ठेकेदार और एस० डी० ओ० को कहा गया कि यह रोड कितने दिन चलेगी, इसमें तो केवल तीन इंच सोलिग है। आप खुद जा कर चौक कर लें। उस पर केवल तीन इंच सोलिग है और उसके०पर ही प्रिमिक्स कर दी है। तो जितनी धांधली और क्रप्शन इस महकमें में है और कहीं नही है। अगर आप इसके सुधार सके तो देख लें वरना इसमें बहुत मिसयूज हो रहा है। इसके अलावा कसार रोड पर जो रोड़ी बिछाई थी वह अब इकट्ठी करने लग रहे हैं। पता नहा क्या कारण है। वह रोड़ी डेढ़ किलोमीटर के अन्दर बिछा रखी थी तो मैं जानना चाहता हूं कि उसको इकट्ठी करने का क्या कारण है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आने–बल मैम्बर ने जो सवाल उठाया एं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी धर्म पाल सिंह मलिक, आनरेबल मैम्बर और मैं कहा गए थे। उन रोडज पर बाकायदा काम शुरू

है। जहां तक ये रोड़ी उठाने की बात कह रहे है, हमने उसकी स्ट्रैन्थनिग करने। है। तो जब तक रोड। नही उठाई जाएगा तो रेजिन कैसे होगा। वहां पर बाकायदा काम शुरू हो रहा है। जिन रोडज का इन्होने जिक्र किया है उनके अगस्त, 1995 तक बाकायदा बेहतर बना दिया जाएगा। और इनकी तसल्ली करवा दी जाएगी। रोड़ी और तारकोल, मोटी रोडी और जीरा रोडी के जितने भी प्रावधान है वे बाकायदा मेनटेन हो रहे हैं। अगर इनके कोई शिकायत है तो मुझे बता दें।

श्री अध्यक्षः आप इनके साथ विजिट कर ले।

श्री अमर सिंहः ठीक है जी, मैं सैशन के बाद मैम्बर साहब को साथ लेकर जाऊंगा और बाकायदा इनकी तसल्ली करवाऊंगा।

Opening of Veterinary Hospital at Village Singhwal

***1050. Shri Bharath Singh :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Veterinary Hospital in village Singhwal of District Kaithal ; and

(b) if so, the Lime by which the aforesaid Hospital is likely to be be opened ?

पशुपालन राज्य मंत्री (राव धर्मपाल):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Bus Stand at Julana

***1058. @Shri Suraj Bhan Kajal :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Julana during the year 1995 ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह): जी हां।

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जुलाना का बस स्टैण्ड कब मंजूर हुआ था, उसके लिए कितना पैना रखा गया था, उस पर भाव काम शुरू करवाएंगे और उसको कब तक कम्पलीट करवा देंगे?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, उस बस स्टैण्ड की भूमिं 7– 10– 90 को एक एकड़ एक्वायर की गई थी और दो एकड़ भूमि 1792 को एक्वायर की गई थी यानि तीन एकड भूमि एक्वायर की गई है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उस बस स्टैण्ड को इसी वित्तीय वर्ष में कम्पलीट करवा दिया जाएगा।

श्री अजमत खांः स्पीकर साहब, हथीन और हसनपुर में बस स्टैण्ड बनाने के लिए चार पाच साल से जमीन एक्वायर हो

चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर बस स्टैण्ड बनाने का काम कब तक शुरू करवा दिया जाएगा और कब तक उनको कम्पलीट करवा दिया जाएगा?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, हथीन में बस स्टैण्ड के लिए जमीन एक्वायर हो चुकी है और उसको बनाने का काम हम जल्दी ही शुरू करवा देंगे। जहां तक हसनपुर का सवाल है वहां पर अभी तक बस स्टैण्ड के लिए जमीन एक्वायर नही हुई है।

श्री अजमत खांः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी हथीन में बस स्टैण्ड बनानेत का काम इसी वित्तिय वर्ष में शुरू करवा देंगे?

श्री बलबीर पाल शाहः जी हां।

श्री पीर चन्दः स्पीकर साहब, रतिया में बस स्टैण्ड बनाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पत्थर रखा था लेकिन वे यहां पर बस स्टैण्ड नहीं बना सके। हमारे मुख्य नली जी रतिया गए थे, उस समय इन्होंने कहा था कि वह सरकार तो यह बस स्टैण्ड नहीं बना सकी, हम इस बस स्टैण्ड को जल्दी से जल्दी बना देंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या वह बस स्टैण्ड इसी वर्ष 1994– 95 में कम्पलीट करा दिया जाएगा?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, वर्ष 1994– 95 तो खत्म होने वाला है लेकिन उस बस स्टैण्ड को बनाने का काम

1995– 96 में शुरू करवा देंगे। उस बस स्टैण्ड का कांटेदार तार लगवाने का काम कर दिया गया धै।

श्री मनी राम केहरवालाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री थे। से जानना चाहता है कि इस समय कितने बस स्टैण्डज का काम शुरू शै और रानिया बस स्टैण्ड बनाने का काम जो शुरु है, उसको कब तक कम्पलीट करवा दिया जाएगा?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है कि रानिया बस स्टैण्ड 6 महीने के अन्दर बन कर तैयार हो जाएगा।

चौधरी सूरज मलः स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ बस–स्टैण्ड के अन्दर बारिश के दिनों में तीन–तीन फुट पानी खड़ा रहता है, क्या यह बात मंत्री जी के नोटिस में है, अगर उनके नोटिस में है तो उस समस्या का समाधान कब तक करवा दिया जाएगा? उस बस स्टैण्ड को०पर उठाना बहुत जरूरी है ताकि उसमें पानी न खड़ा रहे।

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, बहुत से बस स्टैण्ड ऐसे है जो बहुत पुराने बने हुए हैं, उनमें पानी की निकासी की समस्या आ रही है। लोग चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन करते है, वह अपनी जमीन मे मिट्टी भर कर०ंचा कर लेते हैं, उसके कारण पानी की निकासी की समस्या आती है। मैं बहादुरगढ़ के बस स्टैण्ड को दिखवा लूंगा। अगर वहां पर यह समस्या है तो उसको इसी वित्तीय वर्ष मे दूर करवा देंगे।

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, जिन बेरोजगार लोगों को बसों के प्राइवेट परमिट दिए गत है, वे नेशनल हाई–खे पर वस स्टैण्ड से 10–10 किलो– मीटर दूर सवारियों को उतार देते हैं और उन सवारियों को हरियाणा रोडवेज की बसें बिठाती नही हैं। जैसे मतलोडा है ओर नौलथा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन जगहों पर सरकार वस स्टैण्ड बनाने के बारे में विचार करगी ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो?

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर साहब, इसराना में इसी साल में बस–स्टैण्ड का निर्माण करा देंगे और नौलथा में बस स्टैण्ड नही बनाया जा सकता क्योंकि नोलथा इसराना के बिल्कुल साथ लगता हुआ है। जहां तक वहां पर क्यू शैल्टर बनाने की बात है, वह वनवा दिया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा हो।

'Apni Beti Apna Phan' Scheme

***1075. Shri Karan Singh Data :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

(a) the numbar of families provided the benefits under `Apni Beti Apna Dhan' scheme in the State at present, together with the criteria adopted thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the benefits of the scheme as referred to in part (a) above to each family of the State ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिह यादव):

(क) एवं (ख) विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) अपनी बेटी अपना धन योजना के अन्तर्गत दिनांक 28– 2– 95 तक राज्य में 16339 परिवारों को लाभ दिया जा चुका है पात्रता कई शर्तें निम्न प्रकार से हैं:–

(1) गरीबी रेखा से नीचे के गैर अनुसूचित जाति के परिवार जिनमें लड़की का जन्म 2– 10– 94 को या उसके बाद ददुआ हो।

(2) अनुसूचित जाति के परिवार जिनमें बेटी का जन्म 2– 10–94 या उसके बाद हुआ हो, बशर्ते कि माता–पिता श्रेणी 1 अथवा 2 के राजपत्रित अधिकारी न हों अथवा आयकर दाता न हो,

उपरोक्त 1 एवं 11 के लिए यह भी शर्त है कि –

नवजात शिशु कन्या परिवार का पहला, दूसरा या तीसरा बच्चा ही हो। तीन से अधिक बच्चों वाले परिवार इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं।

परन्तु, यदि तीसरी और चौथी बच्ची जुड़वां है तो चौथी बच्ची का भी लाभ दिया जायेगा।

(3) बच्चे के माना–पिता हरियाणा राज्य के अधिवासी हों।

(ख) नही श्रीमान।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि जो 16339 बैनिफिशरीज की संख्या इन्होंने बताई है, इसमें जिलावाईज संख्या क्या–क्या है? दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्लौड्च्ल्ड कास्टस के जो अधिकारी श्रेणी – 1 व 2 में आते हैं, क्या उनको भी यह सुविधा दी जाएगी? तीसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुड़गांव जिले में और फरींदाबाद जिले में जो लोग खेती करते हैं, उनको पानी की सुविधा न होने के कारण उनकी खेती भी ठीक प्रकार से नही होती और सरकारी हिदायतों के अनुसार वे गरीबी रेखा से०पर आते हैं, जबकि असलियत में उनकी हालत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों से भी बदतर है। क्या उनको भी इस श्रेणी में सुविधा दी जाएगी?

10.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो 16339 बैनिफिशरीज है उनमे ग्रामीण क्षेत्र में 14089 व शहरी क्षेत्र मैं 2250 हैं। ग्रामीण क्षेत्र में

बैनिफिशराज की संख्या जिला वाईज इस प्रकार है:– अम्बाला में 809, जिसमें से 620 एस० सी० कैटेगिरीज के 189 जनरल कैटेगिरी के है, यमुनानगर में 852, कुरुक्षेत्र मे 466, कैथल में 800, करनाल में 547, सिरसा मे 865, सोनीपत में 576, रोहतक में 1314, फरीदाबाद मे 561, जीन्द मे 1179, रिवाडी में 590, भिवानी में 1395, महेन्द्रगढ में 429, हिसार में 2305, गुड़गांव में 853, पानीपत में 530, शहरी क्षेत्र में बैनिफिशरीज की संख्या है – अम्बाला 881, यमुनानगर 897, कुरुक्षेत्र 548 कैथल 889, करनाल 711, सिरसा 1018, तयो सोनीपत 1522, फरीदाबाद 68, जीन्द 1345, रिवाड़ी 640, भिवानी 1499, महेन्द्रगढ़ 491, हिसार 2834, गुड़गांव 1047, पानीपत 811, और इसके बाद शहरों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारो का विवरण इस प्रकार हैं अम्बाला के अन्दर 72, यमुनानगर 45, कुरुक्षेत्र 82, कैथल 89, करनाल 164, सिरसा 153, सोनीपत 120, रोहतक 238, फरीदाबाद 1191, जीन्द 148, रिवाडी 50, भिवानी 104, महेन्द्रगढ़ 62, हिसार 529, गुड़गांव 194, पानीपत 81 यह शहरों का टोटल 20250 बनता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्राईटेरिया के बारे में पूछा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि गरीबी रेखा के नीचे 8.381 प्रतिशत फैमिलीज हैं। यह फिग्गर डी० आर० डी० ने 1991– 92 की जनसंख्या निर्धारित की थीं, उसके मुताबिक हैं। यह स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि गरीबी. रेखा से नीचे हैं। इस स्कीम से बैनिफिटिड होने वालों मे 40 प्रतिशत एस० सीज० 21 प्रतिशत बी० सीज० हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि खासतौर पर

बेटी को बोझ समझा जाता है, इससे लोगों की सोच को बदला जाए और लड़की को पूरा मान–सम्मान मिल सके। इस स्कीम के तहत 500 रुपये जच्चा की खुराक के लिए दिए जाते हैं ताकि गरीबों को कोई दिक्कत न हो। अमीर आदमी तो खुराक दे सकता है लेकिन गरीब आदमी को दिक्कत होती है। इसके साथ ही बेटी पैदा होने मे जो हीन भावना होती है, उसको दूर करने के लिये 500 रुपये खुराक के अतिरिक्त 2500 रुपये पैदा होने वाली लड़की के खाते में जमा करवाए जाते हैं जो कि लड़कियों की शादी के समय निकलवाए जा सकते हैं। उस वक्त तक यह राशि 25,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से यह स्कीम जनसंख्या रोकने के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकेगी। इस स्कीम का एक दूसरा उद्देश्य यह है कि पुरुष स्त्री का अनुपात 1000 के पीछे 865 है और उस रेशो को भी पूरा किया जा सके ताकि लड़को के बराबर लड़कियां पैदा हों तथा लोगों में यह भावना पैदा न हो कि उसके लड़की ने जन्म लिया है, लोगों की इस सोच को बदलना है। जहां तक लड़कियों की मृत्यु दर का ताल्लुक है, वह पहले ही काफी कम है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे लगता है कि वे लड़कियों की संख्या बढ़ाना चाहते है, इस लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्द्र। महोदय से जानना चाहूंगा कि क्लास–1 तथा क्लास 2 के जो अधिकारी हैं, उनको तनख्वाह

इतनी नही मिलती कि वे बच्चों का सहे, पालन पोषण कर सके, क्या उनके लिए भी यह स्कीम लागू की गई है या नही? मेरे सवाल का जवाब मन्त्री जी ने नही दिया। इसके अलावा जो मेरा सवाल था, वह यह था कि रिकार्ड के आधार पर जो लोग गरीबी रेखा से०पर माने गए हैं लेकिन जिनकी हालत ऐसी है कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नही है, क्या उन लोगों के भी इसमे शामिल करेंगे? अध्यक्ष महोदय फरीदाबाद बाद तथा गुड़गांव के लोग बहुत गरीब हैं। वहां धरती में पानी नही लगता, नौकर लोगों को मिलती नहीं, इसलिए आपके माध्यम से मन्त्री जी से मेरा यह सवाल है कि क्या उन लोगों को भी इस स्कीम में शामिल करेगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इनको बता दिया है कि यह स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जो गरीब। रेखा सै नीचे जीवन गुजार रहे हैं। इसका और कोई क्राईटेरिया नहीं है।

Road Accidents in the State

"**1095. Prof. Sampat Singh :** Will the Chief Minister be period to state—

(a) the total number of motor vehicles and other accidents occurred in the State during the years 1993-94 and 1994-95 ;

(b) the total number of persons died and injured in the above said accidents during the said period, separately ; and

(c) the amount of compensation, if any, given by the Government in each case to the persons injured and the families of deceased involved in the accidents as referred to in part (a) above 9

Mr. Speaker : Extension for giving reply to this question has been requested by the Govt. which has been granted. Interim reply is as girder'.

Interim Reply

"BHAJAN LAL D.O. No. 52/8/95-7HG-II

Chief Minister, Haryana,

Chandigarh.

March 1995.

Subject : Reply to starred question No. 1095— Extension/Deletion of Part (c).

My Dear Speaker Sahib.

Starred question No. 1095 relating to read accidents in the State has not so far been listed for reply. The part (C) of the question relates to the information with regard to the amount of compensation. if any, given by Govt. in each case to the persons injured and the families of deceased involved in the accidents. The compensation is awarded by the following agencies

(i) Courts in MACT eases.

(ii) Deputy Commissioners from Red Cross.

(iii) State Govt. from Govt. fund.

(iv) Ministers out of their discretionary fund.

(v) Chief Minister cut of Govt. fund or discretionary fund.

(vi) Various courts out of fine imposed.

(vii) Insurance companies, Workmen-compensation Act.

(viii) E.S.I.

(ix) Insurance companies against claim filed.

This collection of the requisite information from the above mentioned authorities will be a colossal task and may take 6 months. It is felt that the significance of collection of such figures may not be commensurate with the efforts and labour involved. I am, therefore, to request that either a period of 6 months may be granted for collection of figures or part (c) of the question may be deleted.

With regards,

Yours sincerely, Sd/-

(BHAJAN LAL)

Ch. Ishwar Singh, Speaker,

Haryana Vidhan Sabha."

Repair/Construction of Roads in the State

***1010. Prof. Cnhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state-

(a) the districtwise total amount spent on the repair of roads, in the State during the period from July 1991 to date ;

(b) the total amount spent on the construction of new reads in the State during the period from July, 1992 to date ;

(c) whether all the villages have been connected with the medalled road in the State, if not, the names of such villages which have not been connected solar together with the time by which these are likely to be connected with the metalled road ?

Public Works Minister (Shri Amar Singh) :

(a), (b) & (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) District-wise amount spent on the repair of roads during the year July, 1991 to date is as under :—

Sr. No.	Name of District	Amount spent (Rs. in Lacs)
1.	Ambala	715
2.	Bhiwani	752

3.	Faridabad	690
4.	Gurgaon	915
5.	Hisar	1440
6.	Jind	579
7.	Kaithal	410
8.	Karnal	680
9.	Kurukshetra	652
10.	Mohindergarh	389
11.	Panipat	447
12.	Rewari	360
13.	Rohtak	1044
14.	Sirsa	646
15.	Sonepat	566
16.	Yamuna Nagar	508

(b) Amount spent on the construction of roads during the period July, 1992 to date is Rs. 1417 Lacs.

(c)(i) Out of 6745 villages only 7 villages covered under the policy remain to be connected with metalled road. The details are as under :—

Sr.	No. Name of Village	District

1.	Prem Pura	Ambala
2.	Khol Fateh Singh	,,
3.	Khol Mola	,,
4.	Bhoj Khudana	,,
5.	Bhoj Rajpura	,,
6.	Dakrog	,,
7.	Khoi	,,

(ii) Besides this the following villages with population less than 250 in plain & 150 in hills and which are not covered under existing policy have also not been connected by medalled roads :—

Sr.	No Name of Village
	Ambala District
8.	Sangoli
9.	Peerwali
10.	Pamiwala
11.	Udhamgarh
12.	Rampur Gainda
13.	Kurewala
14.	Belgarh

15.	Kamiawala
16.	Khan Puri
17.	Khol Albela
18.	Banoi Sanwalia
19.	Tibbi
20.	Gawahi
21.	Gumthala
22.	Bhagrani
23.	Dhamso
24.	Jaithal
25.	Nalah Dakrog
	Karnal District
26.	Nabiabad
27.	Sadiqpur
28.	Sherpur Viran
	Kurukshetra District
29.	Kohli Khera
30.	Theh Mujibulah
31.	Teokran

	Rohtak District
32.	Bir Dadri
33.	Bir Sumariwala
	Sonepat District
34.	Munirpur
35.	Dhiki
	Faridabad District
36.	Akbarpur
37.	Shekhpur
38.	Mauzmabad
39.	Latifpur
40.	Dulapur
41.	Masudpur
42.	Benrampur
43.	Naglia
44.	Jhuppa
45.	Dalepur
46.	Tajpur
47.	Dostpur

48.	Qureshipur
49.	Sherpur Khadder
	Gurgaon District
50.	Ranika Notab
51.	Rehaka
52.	Hamirpur
53.	Zakopur
54.	Dholi
55.	Jakh
56.	Kharli Ter
57.	Kharak Sohna
58.	Bidhuwas
59.	Nahrepur
60.	Siyanika
	Bhiwani District
61.	Rehrodi Khurd
	Hisar District
62.	Saladheri
	Sirsa District

63.	Kasankhera
64.	Sawaipur
65.	Bukhara Khera
66.	Moranwali
	Mohindergarh District
67.	Muradpuri

Villages at Sr No. 1 to 7 will be connected with metaled read, as soon as possible, depending upon availability of funds. There is at present no proposal under consideration to provide link roads to villages at Sr. No. 8 to 67 above.

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने चौधरी धीरपाल सिंह जी के सवाल के जवाब में वनाया है कि जो फल्ड फैक्टिड एरियाज है, जहां पर वर्षा के दौरान सड़कें टूट जाती हैं, उनकी रिपेयर हो गई है, यह अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जो आकड़े प्रस्तुत किए हैं इन के मुताबिक इन्होंने पिछले सालो में जो पैसा खर्च किया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री महोदय और इनकी सरकार लोगों की आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि पोलिटिकल आधार पर पैसा खर्च करती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि जुलाई 1991 मे आज तक जो खर्चा हुआ है उसमें से हिसार में 1440 लाख, कैथल मे 460 लाख, करनाल मे 680 लाख और कुरुक्षेत्र में 652 लाख रुपए खर्च किए है। भिवानी जिला ऐसा जिला है

जहां पर करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र से ज्यादा बाढ़ आने लगी है, क्या वहां पर पैसों की ज्यादा व्यवस्था करेंगे? (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न के 'बी' पाट के जवाब में माना है कि––

"Amount spent on the construction. of Reads during the period July, 1992 to date is Rs. 1417 Lacs."

तो यह जो 1417 लाख खर्च किया है उसमें से हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़ में डिस्ट्रिक्ट– वाईज कितना–कितना खर्च किया है? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने जो लिस्ट दी है उस बारे मे मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि 1994 में मिठी गांव में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, क्या उसकी पूर्ति भी ये करेगे और जो गांव सड़क मे नही जोड़े है, उनको कब तक जोड़ने का ये इरादा रखते हैं?

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और ये प्रोफेसर हैं, गोल्ड मैडलिप्ट भी हैं। मैंने तो इनके सवालो का जवाब डिटेल मे दिया हुआ है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 237 किलोमीटर स्टेट हाई–बे, 50 किलोमीटर अदर और डिस्ट्रिक्ट विलेज रोड 1313 किलोमीटर हैं, यह टोटल 1600 किलोमीटर बनता है, इस पर 718 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। भिवानी में 442 किलोमीटर स्टेट हाई–वे 239 किलोमीटर मेजर रोडज और 1328 किलोमीटर रूरल रोडज है, यह टोटल 2009 किलोमीटर बनता है और इम पर 7

करोड़ 92 लाख रुपए खर्चा आया है। इसी तरह से हिसार सबसे बड़ा जिला शै और इसमें सबसे ज्यादा लम्बी रोडज हैं। 391 किलोमीटर स्टेट हाई–वे, 211 किलोमीटर मेजर रोडज और अन्दर रोडज 2222 किलोमीटर हैं। यह टोटल 2824 किलोमीटर बनती हैं। इस पर टोटल खर्चा 14.40 करोड़ आया है। यह सब फिगर्ज 1– 7– 91 से लेकर 31– 1– 1995 तक की है। हमने सारी डिस्ट्रिक्टस की तो इंफर्मेशन दी हुई है, फिर ये हाउस का समय क्यों खराब कर रहे है? इसलिए मैं इनमें कहना चाहूंगा कि इनको' सवाल के जवाब को देखकर ही अपनी सप्लीमैन्ट्री करना चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौ० भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी से जानना चाहिए लेकिन मैं छत्तर सिंह जी से जानना चाहता हूं क्योंकि ये अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। भिवानी जिले की आबादी हिसार जिले से आधे से भी कम होगी लेकिन फिर भी हमने आधे से भी ज्यादा पैसा आपको दे रखा है। परन्तु इनको तो हिसार जिले के नाम से फोबिया हो गया है। द्रुमने 7 करोड़ 52 लाख रुपया भिवानी जिले के और 14 करोड़ रुपया हिसार जिने को दिया है जबकि रोहतक को दस करोड़ रुपये दिए हैं, यानि किसी भी इलाके के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है इसलिए आपको देखना चाहिए कि भिवानी जिले की आबादी किटनी है? इसी तरह मे फरीदाबाद जिले को 6 करोड़ 90

लाख रुपयें दिए गए है। (विघ्न) 'हिसार तो. सबसे घड़ा जिला है और इसके याद रोहतक का नम्बर आता हू। (विघ्न)

तारांकित प्रश्न सं० 1139

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल इस समय सदन मैं उपस्थित नहीं थे।

Amount spent on the Repair of Roads of District Kaithal

***1118. Shri Amar Singh Dhandey :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) ba pleased to state the constituency-wise total amount incurred by the Government on the repair of roads in district Kaithal during the years 1991-92, 1992-93, 1993-94 and 1994-95 separately ?

Public Works Minister (Shri Amar Singh) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

Constituency-wise total amount incurred on-repair of roads in Kaithal District.

Sr. No.	Name of Constituency	Year-wise expenditure (Rs. in lacs)				Total expendi-nture from April. 1991 to January.
		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 upto	

					1/95	1995 (Rs. in lacs)
1.	Guhla	20.56	19.62	11.11	17.15	68.44
2.	Kaithal	28.23	17.57	28.11	13.60	87.51
3.	Pundri	39.-67	24.28	22.06	16.41	102.42
4.	Pai	43.95	23.62	12.83	17.46	97.86
5.	Rajound (in Kaithal District)	0.72	0.66	3.80	7.59	12.77
6.	Kalayat	24.55	11.12	10 86	20.20	66.73
	Total	157.68	96.87	88.77	92.41	435.73

श्री अमर सिंह ढांडेः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैथल जिले में इन्होंने जो पैसा खर्च किया है, उसमें से सबसे कम पैसा गुहला में ही क्यों खर्च किया गया है? गुहला हल्का तो पूरी तरह से फलडिड एरिया है वहां पर कई बार लगातार बाढ़ आयी थी इसलिए वहां पर सड्कों की बुरी हालत है। मैं जानना चाहूंगा कि गुहला हल्के के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैंने इस बारे मैं कई बार पहले भी कहा था कि पैसा सड़कों पर खर्च न होकर कहीं और खर्च होता है। स्पीकर सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके लिए

एक स्पेशल कमेटी बनाए जो जांच करे कि क्या वहां पर एक्चुअल मे पैसा खर्च हुआ है या नहीं ?

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, गुहला में ईयरबाईज जौ पैसा खर्च किक गया है, उसके बारे में मैं इनको बता देता हूं। वर्ष 1991– 92 में 20.56 लाख रुपये और 1992– 93 में 19. 62 लाख रुपये 1993– 94 में 11.11 लाख रुपये 1994–95 में जनवरी 1995 तक 17.15 लाख रुपये खर्च किए गए हैं यानि गुहला में टोटल 68.44 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसी तरह से कैथल में 87. 51 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

श्री अमर सिंह ढांडेः लेकिन गुहला में सबसे कम पैसा क्यों खर्च किया गया है?

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, इसी तरह मे राजौंद में टोटल 12.77 लाख रुपये खर्च किए गए है। किसी भी हल्के के साथ पक्षपात की बात नहीं है। हर गांव में बढ़के भेजी हुई है, हर गांव मे पीने के पानी या इन्तजाम है। आप ऐसा एक भी गांव बता दें जिसमें वाटर सप्लाई स्कीम के द्वारा पीने का पानी न पहुचता हो। (विघ्न) मैं भी सड्कों की ही बात कर रहा हू। कोई भी गांव ऐसा नही छोड़ा गया जहां सड़क न पहुंची हो, सारे गांव सड़कों से मिले हुए है। जहां तक पैसे की बात है, बाकायदा गुहला मे अलग–अलग साल मे अलग–अलग पैसा खर्च किया गया है। 1991– 92 में सरफेसिंग पर 12 लाख रुपये खर्च हुए। इसी तरह

से 1991– 92 में रिपेयर पर 35.35 लाख रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा 1992– 93 में रिपेयर पर, सरफेसिंग पर और स्ट्रैगथिग पर 13 लाख रुपये खर्च हुए है। 1994– 95 में जनवरी तक गुहला में 17 15 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसी तरह से 1993– 94 में 11.11 लाख रुपये, 1992– 93 में 19.62 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी बहुत ढोल पीटते है कि हमने अपने टाइम में हरियाणा के हर गांव को मैटल रोड से जोड़ दिया। यह बात सत्य नहीं थी। बहुत से गांवों को चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने जोड़ा है। विशेषकर हमारा जिला फरीदाबाद खदर मे पडता है।

चौधरी अमर सिंह जी वहां पर थे इनकी विशेष कृपा है लेकिन इन्होंने एक सूचना सदन के पटल पर दी है कि 250 की पापुलेशन से नीचे के ये गांव हैं। मै आपके माध्यम से मती जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन सब गांवों में जैसे अकबरपुर, शेखपुर, लतीफपुर, दुलेपुर, मसूदपुर, बहरामपुर, नगलिया, झुप्पा दहेनलपुर, दोस्तपुर और कुरैशीपुर इत्यादि गांव हैं, 250 से ज्यादा पापुलेशन है। क्या मती जी सैशन के बाद वहां चलेगे, मैं इनके सारे गांव दिखा दूगा। अगर इन गांवो की पापुलेशन ज्यादा मिली तो क्या ये मौके पर आदेश देंगे कि वहां पर सड़क फौरन बना दी जाए?

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक फरीदाबाद जिले मे 14 ऐसे गांव है जिनकी आबादी 250 से कम है। यह हमारी पौलिसी मे नही आता। अगर माननीय सदस्य बता देंगे कि 250 से०पर आबादी है तो हम प्रावधान करेगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः हम आपको हाथ' खड़े करके गिनवा देंगे।

श्री अमर सिंहः अगर हाथ खड़े करवा कर गिनवा देगे तो हम उन गांवों को सड्कों से जोड़ देगे।

श्री अजमत खांः अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने जो बात कही है वह एरिया मेंरे हल्के के साथ है। मेरे हठके में कुम्हेड़ा, टौंक और साढ–चिल्ली, ये तीन ऐसे गये हैं जिनमें से दो गांव की आबादी 800 से एक हजार के बी च है और एक गाव हैं जिनमें से आबादी 400 के लगभग है। मंत्री जीं हमें टाइम दे दें, हम इन्हें मौके पर दिखा देगे। में मंत्री मे जानना चाहूंगा कि नब तक इन गांवों को सड़को से जुडवा देंगे?

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी। नये बजट के मुताबिक जो गांव, जो ढाणिया है, जिनकी आबादी 250 से०पर हो गई होगी, उनको 1995– 96 में जरूर रोड से मिला देंगे।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गांव गूढ़ी डायरैक्टरी विलेज है, वड़ा गांव है जिसकी एक हजार आबादी है, वह आज तक सड़क से नहीं जुड़ा। इसमें सिर्फ छह सड्कों का ब्यौरा दिया है। यह गूढ़ी गांव किसी भी तरफ से सड़क से नही जुड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कब तक उस गांव को सडक से जोड़ देंगे? मैंने लिख कर भी भेजा है।

श्री अमर सिंहः उस गांव की आबादी 250 से ज्यादा है तो उसको भी सड़क से जोड़ देंगे।

Sprinkler Sets

***1179. Shri Om Parkash Beni :** Will the Minister for Co-operation be pleased to stale whether any case of payment made by the Land Development Bank in Bhiwani and Mohindergarh districts to unapproved sprinklers supplying film has come into the notice of the Government during the year 994: if so, the action taken thereon ?

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): वर्ष 1994 में भिवानी एवं महेन्द्रगढ जिलो में भूमि विकास बैको द्वारा अमान्य स्प्रिंकलर सैट सप्लाई करने वाली किसी भी फर्म को किसी स्प्रिंकलर सैट के लिये वित्त उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही है।

श्री ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, जैसा बहिन जी ने बताया कि किसी को लोन नही दिया जया। जिसको लोन दिया

गया है उसका मैं आपको चौक नम्बर भी बता सकता हूं और डेट भी बता सकता हूं। मै मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा स्टेट भूमि विकास बैक ने, अपने पत्र नंबर 2350 दिनांक 18–4–94 के द्वारा हरियाण राज्य में जो भूमि–विकास बैक हैं, उनके मैनेजर्ज को चिट्ठी लिखी थी कि रुंगटा इरीगेशन कंपनी को जिंदल इरीगेशन कम्पनी मानकर, उसको नयी कम्पनी न माना जाए और इसके जरिए किसानो को स्प्रिंकलर सैट का कर्जा दे दिया जाए?

दूसरी बात यह है कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी इस प्रदेश के अन्दर बनी हुई है जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते है और स्प्रिकलर सैट्स खरीदने का मामला इसी परचेज कमेटी के मातहत आता है। 27– 7– 94 को इसी हाई–पावर्ड परचेज कमेटी की माटिंग हुई। इस मामले से संबंधित मेरे पास एक लैटर है। इस मीटिंग मैं यह निर्णय इस पर लिया गया कि रूंगटा इरीगेशन लिमिटेड को जिन्दल इरीगेशन लिमिटेड न माना जाए और नई कम्पनियों की तरह हरियाणा में माल बेचने के लिये नये तरीके से कम्पनी के प्रोडक्ट का इवैलूऐशन टैस्ट देना होगा। उसका लिखित आदेश कृषि विभाग द्वारा पत्र संख्या 659/74टी –ए 11 एस –ई, दिनांक चण्डीगढ 4– 10– 94 को सूचित किया गया कि वह टैस्ट निजी कम्पनी के साथ दिनांक 7– 11– 94 से 10– 11– 94 को भिवानी शिक्षा बोर्ड में होगा और 8– 11– 94 का वह टैस्ट हुआ। उससे पहले यह कम्पनी कतई तौर पर अन–ऐप्रूवड कम्पनी थी।

प्रबन्धक निदेशक ने जो चिट्ठी लिखी वह इस अन–ऐप्रूवड कम्पनी को किसानो को लोन बांटने की बात लिखी गई थी। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि क्या उस एम० डी० ने हरियाणा प्रदेश के सभी भूमि विकास बेन्को के मैनेजर्ज को यह चिट्ठी त्रिकी है कि रूंग्टा इरीगेशन लिमिटेड को जिंदल इरीगेशन लिमिटेड मान कर इसके जरिये किसानों को स्प्रिंक्लर सैट्स के लिये लोन दे दिया जाये? इनके साथ क्या यह भी सही है कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी का जो फैसला है उसके अनुसार इसको जिंदल इरीगेशन लिमिटेड न माना जाए, क्या यह बात मन्त्री महोदया के नोटिस में है।

इसके साथ–साथ स्पीकर साहब, जैसाकि इन्होंने यह भी कह दिया कि लोहारू या महेन्द्रगढ़ के बैके से किसी किस्म का कोई लोन किसानों को स्प्रिंकलर सैट्स खरीदने के लिये नही दिया गया है। स्पीकर साहब, इस बारे मे मेरे पास कुछ चौकस के नम्बर उपलब्ध हैं कि किस–किस को कितना–कितना पैसा दिया गया है?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर सर, मेरे पाम यह 32 कंपनियों के नाम हैं इनमें रूंग्टा कंपनी भी शामिल है। वह ऐप्रूवड कंपनी है और उसमें किसी अकेले एम० डी० का हाथ. नही होता। उसमे हाई–पावर्ड परचेज कमेटी ही सारा निर्णय करती है और इस बारे में 27–7–94 को रूंग्टा कंपनी से हमारी बातचीत 16 स्प्रिकलर सैट्स खरीदने के बारे में हुई। बेरी साहब के पास

जो लैटर है, यह हमारे पास नहीं है। अगर इस तरह का पत्र इनके पास था तो वह कंपनी के हित में होता किसानों के हित में ही होता तो इस बारे में आप हमें वैले ही सूचित कर देते, हम मान लेते। ऐसी कोई बात नही है। बेरी साहब मैं तो वैसे भी आपका मान करती हूं।

Construction of Bye-Pass at Pehowa

***1172. @Shri Jaswinder Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye-pass on Ambala-Hisar road in Pehowa ; and

(b) if so, the time by which the bye-pass as referred to in part (a) above is likely to be constructed ?

Public Works Minister (Shri Amar Singh) :

(a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

श्री अमर सिंह ढांडे: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि अम्बाला–हिसार सड़क पर बाई–पास का निर्माण करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहूंगा कि यह सड़क स्टेट हाई–वे पेहवा के बीच से गुजरती है और अध्यक्ष महोदय, यह आपके पड़ोस में ही है। इस सड़क पर काफी

ऐक्सीडैन्ट्स होते हैं। क्या मन्त्री महोदय अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगे और बाई–पास बनाने फो कृपा करेगे क्योंकि यह बाई–पास हर लिहाज से बडा ही जरूरी है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी ठीक है कि – अम्बाला– हिसार सड़क पेहोवा मे से गुजरती है और इस सक की फोरलेनिंग का प्रावधान 47,69,200 रुपया लगाकर कर रहे हैं। 1995–96 में जब यह फोर लेन बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो बाई–पास बनाने की बात की जा सकती है। फिलहाल बाई–पास बनाने का कोई सवाल नही है।

श्री अध्यक्षः आप पेहवा के पास कोई साइड रोड बनाने की सोचें ताकि कैथल से आते हुए वह बाहर–बाहर से ही' निकल जाए। ऐसा सोचें तो ठीक है।

Opening of Ayurvedic and Unani Colleges

***1181. Shri Azmat Khan:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to open Ayurvedic and Unani Colleges in the State ; if so. the places at which the said Colleges are likely to be opened?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): नहीं।

श्री अजमत खांः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि अगर आयुर्वेदिक और यूनानी

कालेज खोल दें तो जो बच्चे वहां से पढ़ कर आएंगे उनको लाइसैसं मिल जाएगा। ऐसा होने सै उनको रोजगार भी मिल जाएगा और सरकार का भी नौकरियां देने का बोझ घट जाएगा। ऐसा करने से एक तरफ तो बेरोजगारी खत्म होगी और दूसरी तरफ लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो क्या मन्त्री जी मेरे सुझाव पर दोबारा विचार करेगे?

बहिन करतार देवीः स्पीकर साहब, इस वक्त राज्य में एक सरकारी और तीन प्राइवेट आयुर्वेदिक कालेज कार्य कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि श्री मस्त नाश आयुवैंदिक कालेज बोहर में, श्री माडू सिह मैमोरियल महिला डिग्री आयुवैंदिक कालेज खानपुर कलां में और श्री गौड़ व्राहमण आयुवैंदिक कालेज रोहतक में चल रहे है। सरकार दारा श्री. कृष्णा आयुवैदिक कालेज कुरूक्षेत्र में कार्यरत है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, कई प्रश्नों के उत्तर में मैंने सदन में बताया है कि इनफरास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, हरियाणा देश की गिनी चुनी स्टेट्स में है जिसमें कि राष्ट्रीय पालिसी के मुताबिक हमने तीन तरफ से, हैल्थ साइड से भी हर पांच हजार की आबादी पर सब सेटर, बीस हजार की आबादी पर पी० एच० सी० और एक लाख की आबादी पर सी० एच० सी० बनाने का प्रोग्राम है। इसमें से पी० एच० सी० का प्रोग्राम तो हमने पूरा कर लिया है बल्कि चार ज्यादा बना चुके है। जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पैसरियों का सवाल है, स्पीकर साहब, इस वक्त स्टेट मे 401 आयुर्वेदिक, 20 होम्योपैथिक

और 20 यूरानी डिस्पैंसरी व काम कर रही है और इनसे जनता को स्वास्थ्य की पूरी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मैंने माननीय सदस्य को जवाब दिया है किं इस समय कोई नया कालेज तो विचाराधीन नही है लेकिन श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कालेज के ढांचे को उत्तम और देश की अच्छी संस्थाओं में से एक बनाने का प्रयास सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्षः क्या आप यह भी कंसिडर करेंगे कि आयुवैंदिक पी० एच० सी० भी खोलेगे? डिस्पैसरीज तो आपकी पहले है ही।

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे तीन आयुवैंदिक पी० एच० सीज० पहले है। दो और खोलने के लिए मामला सरकार के विचाराधीन है। यह केस फाइनैस डिपार्टमैंट में पड़ा है। इन दो में तुक आपका फरल गांव भी है।

श्री अध्यक्षः क्या फाइनैसं मिनिस्टर इसको कं सिडर करेगे?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर साहब, जरूर करेगे।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, झूठे सर्टिफिकेट्स के बारे में मेरो एक सवाल था जिसको आगने पोस्टपोन कर दिया

था, वह कब लगेगा? आप उसे कल लगा दें क्योंकि कल हाउस खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्षः क्वैश्चन प्रायरिटी के हिसाब सै लगता है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, वह आपने पोस्टपोन किया था तो आप उसको कल लगवा दें क्योंकि सैशन का कल लास्ट डे है।

श्री अध्यक्षः यह कंसिडर का लेगे।

Relief to the Amputated Persons

***1186. Sathi Lehri Singh :** Will the Minster for Agriculture be pleased to state the total number of applications received by the Haryana. a State Agricultural Marketing Board for the grant of relief on account of amputation of limbs while operating Agricultural Machines during the years 1987 to 1990 and 1991 to 1994; togetherwith the amount of relief paid to each applicant during the said period ?

Mr. Speaker : Extension for giving reply to this question has been requested by the Govt. which has been granted. Interim reply is as under : —

Interim Reply

"**HARPAL SINGH**

D.O. NO. AS-IIJ-95/

Agriculture Minister, Haryana, Chandigarh

Dated 22-3-1995.

Subject : Starred Assembly Question No. 1186 raised by Sh. Lehri Singh, M.L.A. EX

Dear Shri Ishwar Singh Ji,

Starred Assembly Question No. 1186 regarding relief to the amputated persons, raised by Shri Lehri Singh, M.L.A. has been listed for 23-3-1995. The question relates to financial assistance given by the Agricultural Marketing Board/Market Committees to each of the victims of agricultural operations during the eight years period from 1987 to 1994. Shri Lehri Singh has asked the total nos. of applications received for the grant of relief during the year 1987 to 1990 and 1991 to 1994. He has also asked the amount of relief paid to each applicant.

The collection of information will take a lot of time because the figures/information relates to several thousand persons and is spread over 100 market committees. In order to frame proper reply and furnish correct information, a period of 2 months is required.

It is, therefore, requested that a time of 2 months may be given to enable us to submit reply to you.

Yours sincerely,

Sd/-

(HARPAL SINGH)

Shri Ishwar Singh. Her 'ble Speaker.

Haryana Vidhan Sabha."

Mr. Speaker : Question Hour is over.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों कीं सूचनायें

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैशन मोशन दिया था कि मेरे हल्के के गांवों में जिनके नाम मैंने अपने मोशन मैं लिखे हुए हैं, जोहड़ों मे पानी नहीं पहुंच रहा है। इस बारे में मेरी सिंचाई मंत्री जी से बात भी हुई थी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अधिकारियों को कहा भी है लेकिन उन्हके बावजूद भी उनमें पानी नही पहुंचा है। अधिकारी कहते है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनमें पानी पहुंच जाएगा। स्पीकर साहब, अप्रैल तक तो बेचारे पशु बिना पानी के मर जाएगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी सै यह आश्वासन चाहता हूं कि जिन गांवों के नाम मैंने अपने मोशन में लिखे है क्या उन गांवो के जोहड़ों में दो चार दिन मैं पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा मेरा एक काल अटैशन मोशन था कि पलवल में एक आदमी की 'एडस' से मौत हुई है उस कारण से सारे पलवल शहर में दहशत फैली हुई है।

श्री अध्यक्षः ये दोनों प्रस्ताव कोमैंटस के लिए गवर्नमैंट को भेजे हुए हैं। आप बैठ जाइए।

श्री ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने चार पांच दिन पहले एस० वाई० एनफ नहर के बारे में, मोशन दिया था और दूसरा यमुना वाटर एग्रीमैंट के बारे मे दिया था। ये दोनो इशू बहुत अहम है और इनके बारे में पूरा हरियाणा प्रदेश चिन्तित है। आप इनके बारे में दो घंटे की बहस करवाने की इजाजत दें ताकि सारी बात क्लीयर हो जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज और कल दो दिन का सैशन रह गया है और प्रो० छतर पाल सिंह बहुत अर्से से सैशन से निलम्बित किए हुए हैं, उनको सदन में आने की इजाजत मिलना चाहिए। वे अब बिलकुल चुपचाप हैं। अब न उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है और न ही धरने पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूं कि सरकार उनके खिलाफ सस्पैशन का प्रस्ताव ले कर आई और वह पास भी हो गया लेकिन आप उस पर पुनः विचार करे। अब तो केवल दो दिन का ही सैशन रह गया है, यदि उनको सैशन में आने की इजाजत नहीं मिलती तो घिराय हल्का अनरीप्रैजैटिड रह जाएगा।

प्रो० राम विलास शर्मा: स्पीकर साहब, आपके चौम्बर में सरकार के संसदीय मंत्री महोदय ने प्रो० छतर पाल सिंह का मौन व्रत तुड़वाया था। आपके सामने चौधरी जगदीश नेहरा जी ने आश्वासन दिया है। आपके आश्वासन के बाद तो उनके सदन मे आने की इजाजत मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैने तो कोई अश्ववासन नही दिया।

प्रो० राम विलास शर्मा स्पीकर साहब, आपने तो आश्वासन नहीं दिया लेकिन आपकी उपस्थिति में आपके चौम्बर में अगर कोई बात हुई हो तो वह बहुत अह– मियत रखती है। विपक्ष के नेता की मौजूदगी में नेहरा जी ने उनका मौन देत तुड़वाया था। इसलिए स्पीकर साहब मैं कहता हूं कि बेरी साहब की बात को मान लिया जाए। अब एक दिन का तो सैशन रह गया है। उस बात को खत्म करके उनको सदन में आने की इजाजत दें। सीकर साहब, कल मैंने यहां पर क्योड़क गांव के हरिजनों के पलायन की बात उठाई थी और मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा था कि कुछ हर्रिजन परिवारों ने अन्य के कारण गांव से पलायन कर लिया था।

श्री अध्यक्षः आप यह बात किर लिए कहना चाहते हैं?

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, यह हरिजनों का गांव से पलायन का सवाल है, जब किसी को अपना घर छोड़ कर चलना पड़ता है तो यह एक बहुत ही गम्भीर बात है। आज मैं उनकी लेटैस्ट लिस्ट ले कर आया हूं। हरिजनों के 25 परिवार आज भी कैथल में हैं। सदन के किसी भी मैम्बर को भेजकर आप पता करवा लें कि उन 25 परिवारों के घरों पर ताले लगे हुए हैं या नहीं। (शोर)

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैशन मोशन सीड की मैक्सिमम लिमिट फिक्स करने के बारे मे दिया था। उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। वह 24 तारीख के लिए लगा दिया गया है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं पहले कल की कुक आनरेबल मैम्बर्ज की स्पीच देखना चाहता हू क्योकि मेरे पर कुछ आक्षेप लगाए गए। दूसरी बात यह है कि जिस रोज मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो मैंने उस वक्त इन्टरवीन किया था तो आप कहने लगे कि पहले मुख्य मंत्री को बोल लेने दो, बाद में आप बोल लेना। लेकिन उस वक्त मुझे समय नहीं मिला। कृपया मुझे पर्सनल एक्स– प्लेनेशन के लिए आप समय दे दें।

श्री अध्यक्षः आज भी बोलने का टाईम है, कल भी है। उस वक्त आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें।

श्री बंसी लालः मैने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी है और कुछ मुख्य मंत्री से कलैरिफिकेशन लेनी है।

श्री अध्यक्षः जिस समय आपको बोलने का मौका देंगे, उस समय आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, प्रो० कपाल सिंह जी को गलत तरीके से हाउस से निकाला गया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, आप उनको बुलाईएं।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, बार–बार उसी बात को रिपीट करने का क्या फायदा। कृपया आप बैठिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

थर्मल पावर प्लांट, पानीपत के गन्दे पनी तथा राख के कारण प्रदूषण मे बीमारियां फैलने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, **I** have received a notice of Calling Attenton Motion No. 27, given notice of by Shri Satbir Singh, M.L.A. regarding pollution due to waste and dirty water of Thermal Power Plant, Panipat and spreading of diseases in the nearby villages. **I** admit it. Shri Satbir Singh Kadian may please read out his notice and the concerned Minister may make a statement, thereafter.

Shri Satbir Singh Kadian : Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that the waste ash of Thermal Power Plant, Pan ipat showers en villages Khukhrana, Sutana, Asan Kalan, Asan Khurd and Bohai etc. and dirty water remains accumulated in the streets of said villages due to which various kinds of diseases are breaking out there. The water table has gone up on account of not having proper out-Ietting of dirty water which has caused water logging. On account of

it crops are not sown in time. The Government does not pay attention towards the proper maintenance of the said plant and controlling of pollution caused by therefrom. A great resentment and worry is prevailing amongst the people over this issue. I. is a matter of urgent public importance. Therefore, **I** request the Government to clarify its position by making a statement in this regard on the floor of the House.

वक्तव्य

वन मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वन मंत्री (श्री राम पाल सिंह कंवर): 650 मैंगावाट क्षमता का पानीपत थर्मल पावर प्लांट, पानीपत–असंध रोड पर पानीपत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी पांच इकाईयां हैं जिनमें से चार इकाईयों की क्षमता 110 मैगावाट प्रति इकाई है और पांचवी इकाई की क्षमता 210 मैगावाट है। वायु और जल– प्रदूषण सम्बन्धित इकाई का प्रदूषण ब्यौरा निम्नलिखित है:–

वायु प्रदूषण

थर्मल पॉवर प्लांट को पूरी क्षमता पर चलाने के लिए 8,600 मिट्रिक टन कोयला और 125 किलोलीटर तैल प्रतिदिन ईधन के रूप में जरूरत है। थर्मल पॉवर प्लांट की इकाई नम्बर एक और दो मैं मकैनिकल प्रैसिपिटेटर लगाए हुए हैं जोकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त नही हैं ओर इसकी जगह इलैक्ट्रो– स्टेटिक प्रैसिपिटेटर लगाने के लिए प्लांट के

अधिकारियों को कहा गया है जिसके लगाने के लिए उन्होंने कुछ सामान खरीद लिया है। थर्मल पावर प्लाट की इकाई नम्बर तीन में जो इ० एस० पी० लगाए हुए हैं उनकी मुरम्मत की जा रही है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उनकी मुरम्मत शीघ्र ही पूरी कराने के लिए कह दिया है।

थर्मल पावर प्लांट की इकाई नम्बर चार और पांच में पहले से ही इ० एस० पी० लगे हुए हैं परन्तु क्योंकि उनके आस–पास की हवा के नमूनों की टैस्ट रिपोर्ट में एस० पी० एम० निर्धारित सीमा से ज्यादा पाए गए थे। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लांट के अधिकारियो को इन सयंत्रो को सुधारने के लिए निर्देश दिए हैं।

थर्मल पॉवर प्लांट में कोयला तोड़ने के लिए दो अनुभाग है जो एक तो इकाई नम्बर एक से चार और दूसरा इकाई नम्बर पांच के साथ लगे हुए हैं। कोयले की धूल को नियंत्रित करने के लिए प्लांट अधिकारियों द्वारा dust containment system (धूल कौ रोकने के लिए संयंत्र) और water spray arrangement (पानी का छिड़काव) संयत्र लगाये जा रहे है।

जल प्रदूषण

जहां तक खुखराना, सुनाना, आसनकलां, आसन–खुर्द और भादडु आदि गांव की गलियों में गंदा पानी इकट्ठा होने का प्रश्न है इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पानीपत थर्मल

प्लांट के अधिकारियों द्वारा जले हुए कोयले की राख की शलरी (गाद) लम्बी पाईपों द्वारा ऐश पोंड में डाली जाती है। राख तो ऐश पोंड में मैटल हो जाती है और उससे पानी नितर कर ड्रेन नम्बर 3 में चला जाता है। कुछ राख भी पानी के साथ बह कर ड्रेन नम्बर 3 में जमा होती जाती है। इसके इलावा पानीपत थर्मल प्लांट से प्रतिदिन 12,000 किलोमीटर गंदा पानी जिसमे कूलिंग टावरर्ज के ओवर फलो का पानी ब्वायलर और रिहायशी कलोनियो का गन्दा पानी भी शामिल है देतला ड्रेन में डाला जाता है। कोयले की शलरी के इकट्ठा होने के कारण लिंक ड्रेन, उतला ड्रेन में chekting से ध्यानाकर्षण नोटिस में वर्णित चार गांवों में पानी फैल जाता है और सिंचाई विभाग इनूडेंस की डिसिल्टिंग का काम बिजली बोर्ड के खर्च पर करता है जो कि प्रगति पर है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने खुखराना गांव की ओर Ash Dykes के बाहरो बाहर वृक्ष लगाकर 15 मीटर से 20 मीटर चौड़ी एक हरी पट्टी बना दी है। वहां पर खड़े सरकण्डों को, जो पहते नीलामी द्वारा बेचा जाता था वह भी पिछले दो साल से नहीं काटा गया धै जिससे कोयले की धूल को हवा में उडने मे बहुत राहत मिली है।

खुखराना, आसनखुर्द, आसनकला गांवो में रुके हुए पानी की जो समस्या ध्यान में आई है वह कुछ तो अधिक वर्षा के कारण और कुछ उन्तला ड्रेन में राख जमा होने से रुकने के कारण से भी है। यहां यह कहना भी उचित होगा कि इस क्षेत्र के गांवों में पानी खड़ा होने की जो समस्या है वह पानीपत थर्मल

प्लांट शुरु होने से पहते भी थी और इस समस्या को हल करने के लिए सिंचाई विभाग के अधि– कारियों द्वारा खुखराना गांव मे खड़े पानी को निकालने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। हरियाणा लघु सिचाई एव नलकूप निगम भी खुखराना गांव के आसपास चार गहरे (डीप) नलकूप लगायेगी जिससे वहां जो वर्षा के कारण पानी का स्तर०पर आ जाता है वह समस्या भी हल हो जायेगी।

कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ध्यानाकर्षण नोटिस में वणिंत गांवो मे थर्मल प्लांट से निष्कासित पानी के कारण फसल की बिजाई में कोई देरी नही हुई है। इन गांवो में जो भूमिगत पानी का स्तर 60 फुट से 50 फुट तक आ गया है वह केवल थर्मल पावर प्लांट से निष्कासित पानी के कारण ही नही बल्कि वर्ष 1993 और 1994 के जुलाई के महीनों में हुई भारी वर्षा के कारण से भी हुआ है। इन गांवों में वर्ष 1993 के जुलाई के महीने में 320.2 मिलीमीटर और जुलाई, 1994 में 354.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थीं जबकि वर्ष 1992 के जुलाई द्वे महीने में यह केवल 110.5 मिलीमीटर हुई थी।

स्वास्थ्य विभाग से प्रप्ति रिपोर्ट के अनुसार न तो इन गांवों में कोई बिमारी फैली है और न ही बिमारिया बढी हैं।

वर्ष 1993 में ग्राम सुधार समिति खुखराना ने बतौर पब्लिक इंटरैस्ट लिटिनेशन एक सिविल रिट पैटीशन नं० 4729 आफ 1993, पानीपत थर्मल प्लांट के विरुद्ध दायर की हुई है और

इस केस में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायलय ने राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को पॉवर प्लांट द्वारा प्रदूषण नियत्रंण संयंत्र लगाने के कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए है। राज्य प्र दूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कार्य को मॉनिटर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया है और उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार यह कमेटी थर्मल पॉवर प्लांट में समय–समय पर प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने के कार्य का निरीक्षण भी करती है।

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट के लिए अपनी बात कहूंगा कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैकी जी ने जो जवाब दिया है, वह तथ्यों से बहुत दूर है। अध्यक्ष महोदय, खुखराना, सुताना, आसन कलां और आसन–खुर्द गांव के पास जिस पौंड में लम्बी पाइपों द्वारा कोयले की राख की गाद डालते हैं, वह पौड बार–बार टूट जाता हँ और जो राख होती है वह किसानों के खेतों में दो– दो फुट तक जम जति।– है। आज खुखराना गांव में ऐसे हालात हैं कि अगर वहां पर पशुओं को बांधने के लिए खूंटा गाड़ें तो वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। दूसरे इन्होंने जो बताया है कि वहां पर हरी. पट्टी बना रखी है तो मुझे वह पट्टी कहीं पर भी नजर नही आई। हो सकता है कि राख की वजह से वह ढक गई होगा इसलिए मुझे नजर नहीं आई होगी। इसी. साल फ्लड की वजह से राख खुखरान ड्रेन में चली. गई है जिसके कारण उस ड्रेन में आज भी पानी नही जा

रहा है। अध्यक्ष महोदय, फ्लड की वजह से हुए नुकसान के नाम पर कुछ प्रभावशाली भागों को नौकरियां तो दै दी गई लेकिन ऐक्चुअल में जिनका नुक्सान हुआ है और जो लोग नौकरियों से वंचित है, क्या उनको भी नौकरियां देंगे? कहीं ऐसा न हो कि वे रह जाएं। अध्यक्ष महोदय, उनको नौकरिया दी जाएं। दूसरे आस–पास के गांवो में जो प्रदूषण फैल रहा है, क्या उनको इमसे बचने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ? उन गांवों को विजली भी गहों मिल रही है। इसके लिए प्रदुषण बौर्ड और बिजली बोर्ड ने क्या कदम उठाए है? इसके सार्थ ही इस वजह से जिन लोगों के फेफड़े गल गए है और दूसरी बिमारियां लग गई हैं, क्या उनके यह सरकार मुआवजा देने जा रही है?

श्री रामपाल सिंह कंवरः स्पीकर सर, इनको केवल सवाल करना चाहिए था लेकिन इन्होंने तो अच्छा खासा भाषण दे डाला। इन्होंने अपने भाषण मे दो–तीन बातें कही है। एक तो यह कि उन्तला ड्रेन कोयले की राख से अट गयी है और लसकी सफाई नही हुई है। स्पीकर सर, इनकी यह बात सत्य नही है। इन ड्रेनों में जब जब भी राख गयी है, जैसा मैंने अपने जबाव में भी बताया है कि इनमें कोयले की राख पानी के साथ जरूर चली जाती है लेकिन हम पानी टूट करके आगे भेजते हैं। मैंने अपने जबाव में यह भी कहा है कि इस पानी के साथ' दुख राख जरूर ड्रेन में चली जाती है लेकिन उसकी सफाई करने के लिए बिजली बोर्ड ने ड्रेनेज डिपार्टमैंट के पास पैसा जमा करवा दिया है। सर,

इस साल भी अगर कादियान साहब वहां पर जाकर देखेगे तो मालूम होगा कि वहां पर हमारी ड्रैग लाइन सफाई करने के लिए लगी हुई है। इस साल में तीनों ड्रेनों की सफाई करने के लिए 3. 70 लाख रुपया बिजली बोर्ड ने ड्रेनेज डिपार्टमैंट के पास जमा करा दिया है। लेकिन स्पीकर सर, ज्यों ही वहां पर काम शुरु किया गया तो किसानों ने रिक्वेस्ट की कि आप 15 दिनों तक इस काम को रोक दें क्योंकि तब तक हमारी सारी. फसलें कट जाएंगी। इमलिए स्पीकर सर, मैं इनको विश्वास दिलाता हू कि उसके बाद इस संबंध मे तेजी से काम करेगें। हम जून के अंत तक तीनों ड्रेनो की सफाई करवा देंगे। इसके अलावा, इन्हेंने यहं भी कहा कि किसानों की खेती भी नही हो पायी है। मैं इनके इस बारे में ईयरवाइज बता देता है। (विघ्न) आपने कहा है कि बिजाई में बहुत देरी हो गयीं है। मैं आपको बता देता हूं कि 1994–95 में पैडी में खुखराना में तीन हैक्टेयर, आना में सिर्फ 0.21 हैक्टेयर, आसनकला में 13 हैक्टेयर, जाटल में चार हैक्टेयर और आसनखुर्द में दो हैक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर खेती नही हो पायी है। इसी तरह से 1994–95 में खुखराना में पांच हैक्टेयर, सुताना में भी दस हैक्टेयर, आसनकला में दो हैक्टेयर, आसनखुर्द में पांच हैक्टेयर और जाटल में नौ हैक्टेयर जमीन ऐसी द्वे है जिस पर धुगरकेन की फसल नट्टी हो पायी है। इसी प्रकार से 1994–95 में खुखराना में तीन हैक्टेयर, सुताना में भी तीन हैक्टेयर, आसनकलां में चार हैक्टेयर, प्रासन खुर्द में दो हैक्टेयर और जाटल में चार हैक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर गेहूं की

फसल नही हो पायी है। जबकि मेरे साथी कादियान साहब ने कहा है कि सारी जमीन बेकार हो गया है और कोई खेती नही हो रही है। यह फिगर्ज मैने दी है जिससे पता चलता है कि कितनी जमीन ऐसा है जिसमें फसल नहीं हो पायी है। अगर इससे अधिक रकबा जिसमें फमल नही हुआ है, रह गया है और वह इनके नालेज में है तो यह हमें बता दें। स्पीकर सर एक बात तो हो सकती है कि किसी कारण मै किसी फसल की बिजाई में देरी हो सकती है यह बात तो मै मान सकता हूं लेकिन यह कहना कि बिजाई बिल्कुल नहीं हो रही है, बह मैं नही मान सकता क्योंकि मैंने आपके सामने फिगर्ज दी हैं कि इतना इतना रकबा है जिसमें बिजाई नहीं हो सकी है। इसके अलावा, इन्होंने दूसरा सवाल किया कि पानी का लैवल नीचा होना चाहिए। स्पीकर सर, एम० आई० टी० सी० ने वहां पर चार ट्यूबवैल्ज लगाने का प्रावधान किया हुआ है जब वह ट्यूबवैल्ज लगेगे और पानी को०पर खीचेंगे तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। जो पानी०पर आ रहा है, ऐसा होने से लाजिमी तौर पर पानी०पर आने से शक जाएगा।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आप पर्सनली. वहां पर विजिट करें क्योंकि खुखराना में वास्तव में यह प्राब्लम है। नह एक छोटा गांव है, अगर उस गांव को कहीं दूसरी जगह पर जमीन ऐक्वायर करके बसाया जा सक्ता हो तो ऐसा अवश्य करे क्योंकि केवल तीन चार एकड जमीन में ही काम चल जाएगा और फिर उस गांव के लोग दूसरी जगह पर बसने के लिए तैयार भी हैं।

श्री रामपाल सिंह कवरः स्पीकर सर, मैंने अपने जबाव मे खूद माना है कि वहां पर प्राब्लम है लेकिन मैंने अपने जबाव में इस प्राब्लम को हल करने के लिए भी बताया है कि थर्मल प्लांट का जो पानी जा रहा है, उसके बारे में उनसे क्हा गया है कि आप इस पानी को ट्रीट कीजिए और अन ट्रीटेड पानी को न चलाईये।

स्पीकर सर, इस साल भी हमें बिजली बोर्ड ने इसके लिए आश्वासन दिया है कि जो सिवरेज वगैरह का गंदा पानी जा रहा है, उसके लिए उन्होंने बीस सोख रुपयें इस साल रखे हैं और कहा है कि बे पानी को ट्रीट करके ही चलाएंगे। इसी तरहं से जो थर्मल प्लांट की यूनिट नम्बर एक और दो हैं, उसके लिंए भी बीत लाख रुपये खर्च किए गए हैं ताकि जो वहां पर पानी का ट्रीटमैंट करने कें लिए मशीन लगी हुई हैं, उनमें कुछ कमी आ गयी है, कुछ पुरानी हो गयी हैं, उनको री–कंडीशन किया जा सके। इसी प्रकार से यूनिट नम्बर 2 के लिए अब तीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रोजैक्ट हमने पॉवर फाइनैस कार्पोरेशन से क्लीयर करवा लिया है, उन्होंने केस वर्ल्ड बैंक को भेज दिया है। उम्मीद है कि 2–3 महीने में वर्ल्ड बैक से क्लीयर हो जाएगा। क्लीयर होने के बाद इस पर काम शुरु करा दिया जाएगा। इसी प्रकार से सीवर कंस्ट्रक्शन वर्क तकरीबन कंपलीट हो चुका है। इसी प्रकार से ई० एस० पी० के लिए बी० एच० ई० एल० से 10.2 करोड़ का सामान थर्मल पॉवर प्लांट में आ चुका है, यह प्रौसेस जारी है, ज्यों–ज्यों सामान आता जायेगा, काम करवाते

रहेंगे ताकि प्रदूषण न फैल सके। यूनिट–3 का ई० एस० पी० का काम कम्पलीट हो चुका है, यूनिट–4 के ई० एस० पी० को सुधारने का काम हो जाएगा। चौथी यूनिट की ओवरहालिंग... (विध्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः उस गांव में सफाई कैसे कराएंगे, इस बारे में बोलिए? बिजली के वारे में मत बोलिए।

श्री अध्यक्षः बहिन जी, ये समाधान की बात ही कह रहे 'हैं।

श्री रामपाल सिंह कवरः स्पीकर सर, जब तक मैं यह नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या स्टैप्स लिए जा रहे हैं तो प्रदूषण कैसे रुकेगा। (विध्न) जून के एंड तक सफाई करा दी जाएगी। स्पीकर सर, इसी प्रकार से कोयले के क्रॉसिंग सैक्शन के अंदर स्प्रे सिस्टम इंस्टाल हो चुका है। टैलीस्कोप एक महीने के अंदर लगा दिया जाएगा, इस टैलीस्कोप से यह होगा कि जहां कोयला टूटता है, उसकी राख उड़ती है, वह राख कम सै कम उड़े, जितनी०ंचाई पर उसकी जरूरत है, उतनी०ंचाई पर सैट हो सकता है, उसको सैट करने के बाद कोयले की राख को आराम से कंट्रोल क्या जा सकता है।

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)ः स्पीकर सर, सतबीर सिंह कादियान जी की जो दो–तीन शंकाएं थी, उनके बारे में मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया। जो थोडी बहुत शंकाएं हैं, उनका' मैं निवारण कर देता हूं। एक तो ऐश डाइक है, उसकी

सतह कच्ची है, इस वजह से सारा पानी बह जाता है। हमने नयी ऐश डाइक्स की कंस्ट्रक्शन दो अढ़ाई महीने से शुरु कर दी है। जब वह पूरी बन जाएगीं तो उसके चारों ओर ग्रीन बैल्ट बना दी जाएगा. ताकि आस पड़ोस के गांवों मे जो नुकसान हो रहा है, फिर वह न हो। दूसरे, फर्स्ट और सैकैण्ड यूनिट के लिए 10 करोड़ रुपए का सामान हम खरीद चुके हैं। इसके अलावा, 20 करोड़ रुपया बहुत जल्दी ही पॉवर फाइनैसं कार्पोरेशन से मंजूर होने वाला है। पूरे 30 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं। यह जो राख इनवौग्रनमैंट को खराब कर रही है, हुसके लिए 30 करोड़ रुपया फर्स्ट एण्ड सैकिण्ड यूनिट पर इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। 20 से 3०0 लाख रुपये के मैकेनिकल प्रैसिपिटेटर होते हैं, वे उन पर लगाएंगे ताकि जब भी उनको रिप्लेस करे तो आसपास के एरिया का वातावरण खराब न हो। तीसरी बात मैं कादियान साहब को बताना चाहूंगा कि यह जो पानी बहकर चला जाता है, हर साल सफाई के लिए हम इरीगेशन डिपार्टमैट के पास पैसा डिपोजिट करते हैं, अब भी पैसा डिपोजिट किया हुआ है, काम चालू है और इसके लिए बिजली बोर्ड बाकायदा जागरूक है। प्रदूषण से जो गंदगी फैल रही है, इसकी रोकथाम के लिए हम पूरी तरह से जागरुक है और बहुत जल्दी समाधान होगा।

श्री अध्यक्षः खुखराना गांव में थोड़ी सी आबादी है, वहां के लोग कह रहे हैं कि जमीन ऐक्यायर करके हमें थोड़ी–सी दूरी

पर बसा दो। क्या आप इस बारे में सोचेंगे क्योंकि वह सस्ता भी पड़ेगा।

11.00 बजे

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि खुखराना गांव के लोग कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी दूरी पर जमीन एक्यायर करके बसा दें। अगर वे लोग चाहते हैं कि उनको दूसरी जगह बसा दिया जाए तो हम उन भाईयों से बातचीत करके डी० सी० के जिम्मे यह काम लगाएंगे ताकि वे खुद भी उन लोगों से पूछ ले और उनसे जगह का भी पूछ लें कि कौन सी जगह पर उनको बसाया जाए। अगर यह छोटा सा सारा गांव सहमत हो गया तो हम उन लोगों को दूसरी जगह पर बसा देंगे।

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, 'प्रदूषण मन्त्री' ने यह माना है और चौ० वीरेन्द्र सिह जी ने भी यह माना है कि वे प्रैसिपिटेटर को मकैनिकल की जगह इलैक्ट्रोस्टेटिक कर रहे हैं। इसके इलावा उन्होंने यह भी वताया है कि 10 कंटेनर्ज हैं, फव्वारे है, स्प्रेयर्ज हैं, वे लगातार रेगुलरली चल रहे हैं लेकिन मेरे नोटिस में यह बात है कि नहीं चल रहे, काम नही करते, इसलिये राखी जाती है उसके कारण से प्रदूषण है। इसके इलावा, एक और कलैरीफिकेशन मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा। जैसाकि आपके अनुरोध पर उन्होंने मान लिया है कि पांच एकड़ जमीन देकर उन

लोगों को कहीं दूसरी जगह पर बसाया जाएगा तो मैं सरकार से कहूंगा कि जो लोग उजड़ेंगे, क्या उनको उनकी कंस्ट्रक्शन के लिये सरकार कुछ मदद करेगी? जिस तरह से कही जमीन एक्वायर सरकार करती है तो उन लोगों को मुआवजा भी दिया जाता है। इसके साथ–साथ मैंने जो नौकरियों के बारे पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया, स्पीकर साहब क्या नौकरियां भी उनको देंगे या नहीं देंगे? इस तरह का आश्वासन इनसे लेना चाहिये।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, जो नौकरी लगे हुए हैं उनको हटाएंगे नही।

श्री रामपाल सिंह कंवरः अध्यक्ष महोदय, अभी कादियान साहब ने 'प्रदूषण मन्त्री' का जिकर किया। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हम तो प्रदूषण रोकसे हैं और इन्हेंने तो सियासी प्रदूषण फैला दिया है। इसको हम कैसे हटाएंगे? (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हमारी जो पिछली सरकार थी, उसमें चौ० वीरेन्द्र सिह जी भी मन्त्री थे। उस समय आसन कलां और आसन खुर्द गांव के बिजली के कनैक्शंज डायरेक्ट हुआ करते थे और इस सरकार ने आकर वह कनैक्शन काट दिये। क्या इन गांवों को जोकि बिजली की चमक दमक हर वक्त देखते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलता है, कम से कम बिजली तो सरकार दे दे, और कुछ नहीं दे सकती तो इतना तो सरकार कर दे, क्योकि उन हरिजन बस्तियों में बुरी तरह से

प्रदूषण फैल रहा है। पानी खड़ा हुआ है और बीमारियां फैल रही हैं। इसलिये इन गांवों के लोगों को सरकार कुछ तो राहत दे। इस तक का आश्वासन सरकार की तरफ से आना चाहिये।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अगर ऐसी कोई बात है और कनैक्शंज काट लिये गये हैं तो इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे। ऐसी कोई बात कादियान साहब नही है। आप मुझे मिल लेना, बात कर लेंगे।

समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(1) लोक लेखा समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members as you know, the leave of absence has been granted by the House to Shri Hari Singh Nalwa, Chairman, Committee on Public Accounts and therefore, he is not present in the House. Under Rule 223 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, T, therefore permit Shri Ram Bilas Sharma, a member of the Committee to present the Thirty Ninth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1994-95, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1989-90.

प्रो० राम विलास शर्मा (सदस्य, लोक लेखा समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1989–90 के लिये हरियाणा के विनियोग लेखों, वित्तीय लेबों पर लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(2) आश्वासन समिति

Mr. Speaker : Honble Members, Shri Dhir Pal Singh, Chairman, Committee on Government Assurances is not present. Therefore, I permit Mohd. Aslant Khan, a member of the Commttee to present Twenty Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1994-95.

Mohd. Aslam Khan (Member, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Twenty Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1994-95.

(3) अनुसूचित जातियों तथा जनजाति कल्याण समिति

Mr Speaker : Now Shri Lehri Singh. Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes will present the Twentieth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1994-95.

Sathi Lehri Singh (Chairman, Committee on the Welfare of **Scheduled** Castes and Scheduled Tribes) : Sir. I beg to present the Twentieth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1994-95.

(4) प्राक्कलन समिति

Mr. Speaker : Now Shri Suraj Mal, Chairman, Committee **on** Estimates will present the Twenty Seventh Report of the Committee on Estimates for the year 1994-95.

Ch. Suraj Mal (Chairman, Committee on Estimates) : Sir, **I** present the Twenty Seventh Report of the Committee on

Estimates for the year 1994-95.

वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the demands for grants on Budget for the year 1995-96 will take place. As per past practice and to save the time of the House, all the demands on the order paper (1 to 25) on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon. Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding Rs. 2,94,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995.-96 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha .

That a sum not exceeding Rs. 61,94,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 1,87,44,12,000 for revenue expenditure and Rs. 4,95,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 26,24,83,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 16,81,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No 5—Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 1,57.85,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No 6—Finance

That a sum not exceeding Rs. 16,68,78,70,000 for revenue expenditure and Rs 6,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 7— Other Administrative service.

That a sum not exceeding Rs 97,85,59,000 for revenue expenditure and Rs. 92,96,33,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 5,45,56,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a suns not exceeding Rs. 2,53,96,31,000 for

revenue expenditure and Rs 76,05;75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 10—Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 17,39,91,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 35,47,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 12—Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 2,36,83.85,000 for revenue expenditure and Rs 2,57,27,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 8,76,38,000 for revenue expenditure and Rs 3,67,00,16,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 14—Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 4,55,82,20,000 for revenue expenditure and Rs. 1,81,27,00,000 for capital

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 15— Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 33,31,49,000 for revenue expenditure and Rs. 36,29,57,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 1,41,39,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 17—Agr culture.

That a sum not exceeding Rs. 42,61,19,000 for revenue expenditure and Rs. 11,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course 01 payment tor the year 1995-96 in respeet of charges under Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 10,68,50,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 19— Fisheries.

That a Sum not exceeding Rs. 56,39,52,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 69,35,16,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 18,63,29,000 for revenue expenditure and Rs. 14,50,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the Year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 2,93,89,56,000 for revenue expenditure and Rs. 42,33,70,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the Year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 27,00,000 for revenue expenditure and Rs. 3,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 3,63,53,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.

I have also received notices of cut motions to the various demands from some M.L.As. These will also be deemed to have been read and moved. However, I will put the various

cut motions to the vote of the House when the respective demands are put to the vote of the House. Such -members may , however, participate in the discussion.

Demand No. 2

1. **Shri Bansi Lal and Shri Chhattar Singh and Chauhan, M.L.As. :**

That Demand No. 2 of Rs. 61,94,94,000 on account of General Administration be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 3

2. **Shri Bansi Lal and Shri Om Parkash Beri, M.L.As. :**

That Demand No. 3 of Rs. 1,92,39,12,000 on account of Home be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 5

3. **Shri Ram Bhajan and Shri Om Parkash Beni, M.L.As. :**

That Demand No. 5 of Rs. 16,81,11,000 on account of Excise & Taxation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 6

4. **Shri Chhattar Singh and Chauhan, M.L.A.** :

That Demand No. 6 of Rs. 1,57,85 85,000 on account of Finance he reduced by Re. 1/;.

Demand No. 8

5. **Shri Bansi Lal and Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.As.:**

That Demand No. 8 of Rs. 1,90,81,92,003 on account of Buildings & Roads be reduced by Re. 1/,

Demand No. 9

6. **Shri Chhattar Singh Chuahan and Shri Om Parkash Beri, M.L.As.**

That Demand No. 9 of Rs. 5,45,56,03,000 on account of Education be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 10

7. **Shri Bansi Lal and Shri Om Parkash Beri, M.L.As. :**

That Demand No. 10 of Rs. 3,30,02,06,000 on account of Medical and Public Health be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 11

8. **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. :**

That Demand No 11 of Rs. 17,39,91,000 on account of Urban Development be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 13

9. **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A :**

That Demand No. 13 of Rs. 2,39,41,12,000 on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 14

10. **Shri Bansi Lal, M.L.A.**

That Demand No. 14 of Rs. 3,75,76,54,000 on account of Food & Supplies be reduced by Re. 1/-.

Demand No 15

11. **Shri Bansi Lal,**

Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. :

That Demand No. 15 of Rs. 6,37,09,20,000 on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 16

12. **Shri Bansi Lai, M.L.A. :**

That Demand No. 16 of Rs. 69,61,06,000 on account of Industries be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 17

13. **Shri Bansi Lal and Shri Chhattar Singh Chuahan and Shri Om Parkash Beri, M.L.As. :**

That Demand No. 17 of Rs. 1,41,39,11,000 on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 18

14. **Shri Om Parkash Beri, M.L.A. :**

That Demand No. 18 of Rs. 42,61,30,000 on account of Animal Bus bandry be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 22

15. **Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A.**

That Demand No. 22 of Rs. 33,13,38,000 on account of Cooperation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 23

16. **Shri Bansi Lal and Shri Om Parkash Beni, M.L.As. :**

That Demand No. 23 of Rs. 3,36,23,26,000 on account of Transport be reduced by Re 1/-.

Demand No. 24

17. **Shri Bansi Lal, M.L.A. :**

That Demand No. 24 of Rs. 3,79,00,000 on account of Tourism be reduced by Re. 1/-.

मोहम्मद असलम खां (छछरौली): स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं सब से पहले अपने हल्के मत्तलिक कुछ बातें कहना चाहता हूं। इससे पहले हमारे बहुत साथी गवर्नर ऐड्रैस पर भी बोले लेकिन आज विपक्ष के ज्यादा साथी मौजूद नही हैं। वे यहां पर हथनी 'कुंड बैराज के०पर काफी बोले। वह मेरी कांस्टीच्यूएंसी में बनने जा रहा है। इन्होंने एतराज उठाया कि यह समझौता केरके मख्यमुन्त्री जी ने हमारा पानी कम कर दिया है। लेकिन इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि पिछले चार या साढ़े चार

साल इनकी सरकार रही और मैं हर सैशन के अन्दर हथनी कुंड बैराज को बनाने के बारे में बोलता रहा। वह बहुत ही अहमियत रखता है। यह तीन प्रदेशों के लिए बहुत जरूरी था जिसमें यू० पी० ,हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं। ताजे वाला हैड वर्कस 1870 का बना हुआ है। वह इतना पुराना हो चुका है कि किसी वक्त भी टूट सकता है। वर्ष 1978 में और 1988 में इनकी सरकार थी और दोनों सालों में बहुत बड़ा फ्लड आया था जिससे बहुत नुकसान हो सकता था। उससे यू० पी० और हरियाणा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी। तो हथनी कुंड बैराज का जो समझौता हमारे मख्य मन्द्री जी ने किया है यह बहुत मेहनत और कोशिश से किया है। यह कोई छोटा काम नहीं था। इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। इससे केवल मेरे इलाके को ही फायदा नहीं मिलेगा बल्कि पूरे प्रदेश को मिलेगा। इसके बनने से 14 हजार क्यूसिकृ की बजाए हम 28000 क्यूसिक तक पानी इकट्ठा कर सकते हैं जिससे बहुत लाभ होगा। पहले हमें जो फ्लड का खतरा रहता था वह इसके बनने से खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा किं 1978 में ऐसे हालात हो गए थे कि हमें बहुत खतरा हो गया था। वह तो सौभाग्य से यू० पी० की तरप। एक बीच हो गई थी जिस वजह से पानी उधर चला गया था और हमारा बचाव हो गया था। इसलिए मैं मुख्य मन्की जी को बधाई देता हूं। दूसरे मैं वाटर सप्लाई के बारे में कहना चाहता हूं। ज्यों ही हमारी यह सरकार आई, मेरी कांस्टीच्यूएंसी के गांव पहाड़ के साथ लगते है उनमें पीने के पानी कीं बहुत दिक्कत

थी। हमारी सरकार बनी और मैंने सरकार से बार–बार अनुरोध किया कि फलां गांव के लिए फलां जगह वाटर सप्लाई के लिए ट्यूबवैल लगाया जाना चाहिए और फलां जगह लगाया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरे हल्के के सभी गांवों को पीने के पानी की सुविधा मिल गई है लेकिन अब सिर्फ एक गांव ऐसा रह गया है जिसमें पीने के पानी की सुविधा नही है। उसके लिए मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उथ गांव में बहुत जल्दी ही वाटर सप्लाई स्कीम पहुंचा देंगे। स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने जो पहाड़ी की तलहटी में कंडी प्रोजैक्ट बनाया है वह बहुत ही अच्छा काम किया है। उस प्रोजैक्ट का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की देखरेख में चल रहा है। हमारे कृषि मंत्री श्री हरपाल सिह जी वहां जाते रहते है। उस प्रोजैक्ट की काफी अच्छी प्रोग्रैस है। एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस प्रोजैक्ट में कुछ गांव और शामिल कर लिए जाए जोकि उस प्रोजैक्ट में आते है। हम उन गांवों की लिस्ट बना कर मंत्री महोदय को भेज देंगे। उन गांवों को उस प्रोजैक्ट का फायदा पहुंच सकता है। यदि उन गांवों को उस प्रोजैक्ट में शामिल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर बात होगी। स्पीकर साहब, यहां पर शिवालिक डिवैल्प– मैट बोर्ड के बारे में चर्चा की गई और कहा गया कि वह बोर्ड कालका हल्के की डिवैल्पमैंट के लिए बनाया गया है। लेकिन वह बोर्ड केवल कालका की डिवैल्पमैंट के लिए नहीं बनाया गया है उसमें मेरी कांस्टीच्यूएंसी छछरौली भी शामिल है। शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड की तरफ से डिवैल्पमैंट के

लिए जितना पैसा गया है वह छछरौली ब्लौक में ज्यादा गया है। मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी का काफी मशकूर हूं कि मेरे हल्के में उस बोर्ड की तरफ से काफी पैसा दिया जा रहा है। केवल यह बात नहीं है कि शिवालिक डिवैल्पमैंट बोर्ड कालका की डिवैल्पमैंट के लिए ही बनाया गया है उसमें बिलासपुर ब्लौक, सिढोरा ब्लोक और छाछरौली ब्लोक भी शामिल है। उन सभी ब्लोकस को उस बोर्ड का फायदा पहुंच रहा है। एक चीज की तरफ मैं सरकार की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि डाइट प्रोग्राम के अन्तर्गत यह कहा गया था कि हर जिले में एक जे० बी० टी० सैटर खोला जाएगा। जिस समय यह प्रोग्राम बनाया गया था उस समय 12 जिले थे और उसके बाद चार नार जिले और बना दिए गए। यमुनानगर जिला भी उन नए जिलों में शामिल है। यमुना–नगर जिले के हम पांच एम० एल० एज० ने सरकार को यह लिख कर दिया है कि वह सैटर उस गांव में खोल दिया जाए और वह गांव मेरी कांस्टीच्यूएंसी का आखिरी गांव है जहां पर यह जे० बी० टी० सैटर खोला जाएगा। उसके लिए उस गांव की पंचायत ने जितनी जमीन चाहिए थी उसका रैजोल्यूशन पास करके दे दिया है। हमारी सरकार ने उसकी मंजूरी के लिए केस भारत सरकार को भेज रखा है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि सरकार उसको परसू करे ताकि वह सैंटर जल्दी से जल्दी खोला जा सके। स्पीकर साहब, मार्किट कमेटीज हर जगह बनी हुई हैं और उनका अपना बजट होता है। यदि कोई मार्किट कमेटी यह रैजोल्यूशन पास करके एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के पास भेजती. है कि फलां

जगह सड़क बनाई जाए या फलां सड़क की रिपेयर की जाए तो यहां से उस रैजोल्यूशन का कोई जवाब नही जाता है जिसके कारण मार्किट कमेटी न कोई नई सड़क बना पानी है और न किसी सड़क की रिपेयर कर पाती है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी मार्किट कमेटी की तरफ से ऐसा कोई रैजोल्यूशन पास हो करके आए कम से कम एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड उसका जवाब तो अवश्य दे दे कि वह सड़क बननी है या नहीं और किसी सड़क की रिपेयर करवानी है या नहीं। लेकिन मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से उसकी ओर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी मार्किट कमेटी ने वहां पर एक डेढ़ किलो– मीटर सड़क का टुकड़ा बनाने के बारे में रैजोल्यूशन पास करके चार साल पहले एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड कों भेजा हुआ है लेकिन उसके बारे में यहां से कोई जवाब नहीं गया है। जबकि उस मार्किट कमेटी के पास फालतू बजट पड़ा है। बिजली बोर्ड को पैसे दे रहे हैं लेकिन सड़कें बनाने के लिए नहीं दे रहे है। सजराबाद से बिलासपुर के लिए जो सड़क है वह केवल आधा किलोमीटर का टुकडा बनना है। बिलासपुर एक बड़ा कस्बा है और वहां की अनाज मंडी में बहुत अनाज ' आता है। वह आधा किलोमीटर सड़क बननी है उसके बारे में चार साल से लिख कर भेजा हुआ है लेकिन एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इसी तरह से डीन से कलावाला सड़क बनाने के लिए तीन साल पहले का वहां की मार्किट कमेटी ने रैजोल्यूशन पास करके

यहां पर एग्रीकल्चरल माकिंटिंग बोर्ड के पास भेजा हुआ है, उसका भी कोई जवाब नहीं गया है। मैं सरकार से अर्ज करना चाहूंगा कि उन सड्कों को पूरा करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहिन करतार देवी जी बैठी हैं। इनके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में बहुत से सब सेंटर बनाये हुए हैं लेकिन वहां पर मेल या फी मेल डाक्टर कोई भी नहीं लगा हुआ। मेरी आपके माध्यम से इनसे प्रार्थना है कि वहां पर जिसको वे भेजना चाहें, भेज दें, ताकि जो अच्छी बिल्डिंगें वहां पर बनी हुई हैं, जो पूरी कम्पलीट हैं उनका फायदा उठाया जा सके और लोगों को चिकित्सा की सुविधा हो सके। अन्त मे आपका बहुत– बहुत धन्यवाद।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, हाउस का एक प्रोसिजर है। हाउस रूल्ज के तहत चलता है। माननीय सदस्य जनरल बजट पर स्पीच कर चुके हैं। आज डिमांडज भी हैं और उसके बाद लैजिस्लेटीव बिजनैस भी है। कायदे कानून में कन्वैशंन है कि पहले उनको टाईम मिलना चाहिए जिन मैम्बर्ज की तरफ से कट मोशंज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन मैम्बर्ज ने कट मोशज दी हुई है, क्या उनको बोलने का टाईम मिलेगा?

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये, टाईम मिलेगा।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांडज पर बोलना चाहती हूं सरकार जो डिवैल्पमैंट के काम

करती है, उसके लिए पैसा मांगा है, मैं इसके हक में बोलना चाहती हू और कुछ सुझाव भी दूंगा। जो कमियां हैं, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमैंट के बारे मे बोलना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि जो मैम्बर्ज के पैड हमें पैसे लेकर दिए जाते हैं, इन पर आधे पैडज पर नाम हैं, आधे पर नही हैं। हमने इस बारे में कई बार कमेटी में भी जिक्र किया है। हमें अबकी बार दो पैन पैसिल प्रेजैट किए गए। जो कागज इन लिफाफों का है, उस पर लिखते समय स्याही फैलती है।

हमारे द्वारा बार बार कहने पर भी इस तरफ ध्यान नही दिया जा रहा। इसके अलावा मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहती हूं कि कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल, की जो हिन्दी की रिपोर्ट है, वह मैं लाना भूल गई, उस बारे में मैं बताना चाहूंगी किं उसकी पेजिंग भी ठीक ढंग से नही है। उसमें 60 के बाद 168 पेज लगा हुआ है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इसमें सरकार का कोई खर्चा भीं नही है क्योंकि हम ये पैड पैसे देकर खरीद रहे हैं। ये पैड मैं लेकर आई हूं, यह सैम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहती हूं। डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं शिक्षा के विषय पर बोलते हुए कहना चाहती हूं कि मेरे इलाके में स्कूल अपग्रेड किए हैं, उनके लिए सरकार का धन्यवाद। मैं इक्के साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे इलाके में कुछ स्कूल, कालेज

या आई० टी० आईज० और भी बनाने की जरूरत है। लोहारू एक छोटी जगह है। शिक्षा के०पर पैसा लगता है यह जायज बात है, इसलिए मैं इस डिमाण्ड के हक में हू। शिक्षा के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। इसके साथ मैं' यह अर्ज करना चाहती हूं कि लोहारू में आई० टी० आई० की बिल्डिंग बननी चाहिए। लोहारू एक छोटी जगह है इसलिए वहां पर स्टाफ के रहने के लिए. उचित व्यवस्था होनी चाहिएं। जिनको वहां पर लगाया जाता है वे वहां पर रहते नही हैं। जिस प्रिंसिपल को लगाया जाता है वह वहां पर रहता नहीं अभी पीछे एक प्रिंसिपल ने यह लिख दिया कि वहां पर आई० टी० आई० की जरूरत ही नहीं है। वह मामला शायद अभी– चल रहा है। मैं चाहती हूं कि वहां पर आई० टी० आई० की बिल्डिंग बनवा दी जाए तो मेहरबानी होगी।। आई० टी० आई० में व्यावसायिक सब्जैक्टस को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्कूल अपग्रेड किए हैं, उनके अलावा पत्थरवा, भाखड़ा, मण्डौलीखुर्द बड़े–बड़े गांव हैं इनमें प्राइमरी स्कूलज है, इन गांवों में कम से कम एक हाई स्कूल जरूर होना चाहिए। भाखरा में हाई स्कूल होना चाहिए, पत्थरवा मैं मिडल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी हमारे यहां एक गुरूकुल है, जिसकी चारदीवारी के लिए मुख्य मन्त्री जी कह कर आए थे लेकिन वह पैसा अभी तक मिला नहीं है, वह गुरूकुल बाढड़ा में है इसका पैसा भी आना चाहिए। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक०न का मिल है, वह मिल चलता है या नहीं चलता, इसके बारे

में तो मुझे समझ में नही आता है। किसी दिन जाएं तो वहां पर 2–4 कर्मचारी काम करते हुए मिल जाएंगे और किसी दिन जाएं तो वह मिल बन्द मिलता है। इस बारे में मेरी सरकार से तथा मन्त्री जी तथा मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त है कि इस मिल को अच्छी तरह से चलाएं उससे लोगों को कुछ रोजगार मिल जाएगा। इस इलाके में कोई और फैक्टरी वगैरा तो है नही इसलिए इस मिल को अच्छी तरह से चलाएं तो मेहरबानी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पीने के पानी के बारे में कहना चाहती' हूं। मैंने इस बारे पहले भी बहुत बार कहा है उसको दोहराने की कोई जरुरत नही है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है। कुछ गांवों में पानी नहीं पहुंचता है। इस बारे में मेरा एक सवाल भी था। मिट्ठी गांव में 10 अक्तुबर को पानी गया था और वह 18 अक्तूबर तक चला उसके बाद पानी नही आया। 26 से 30 तारीख तक वहां पर पानी नही था। मैंने पानी न होने के बारे जब काफी' रोला मचाया तो पानी अब शायद वहां कुछ गया है। अमरवास, सैणावास, सालवां, ढाणा भाखरा में पीने के पानी का बुरा हाल है। अब गर्मियां आ रही हैं इसलिए आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से मेरी अर्ज है कि मण्डौली, सुरपुरा, बदवाना, मोरका आदि गांवो में पानी की सप्लाई बारे ध्यान दें। पहले तो इन गांवों में बहुत पानी आता था यहां तक कि राजस्थान के लोग भी यहां से पानी ले जाते थे। सुधिवास गांव में भी पानी का बहुत बुरा हाल है। शान्ति राठी जी ने भी इस बारे में कहा था। नहर पीछे से आती है और नहर का पानी काट लिया जाता है जिससे आगे पानी पहुंचता नही है औंर

लोगों को दिक्कत होती है। नहर काटने वालों कौ चौक किया जाना चाहिए और उन पर जुर्माना भी होना चाहिए। इन नहरों मे पानी. तब तक पूरा नही हो सकता जब तक कि थीन डैम का पानी न मिले। गाद का जिक्र भी बार–बार यहां पर आया है, मैं तो यह भी कहती हूं कि यदि हम सारे कांग्रेस वाले मिल कर वालंटरी तौर पर नहरों की गाद निकालना शुरु कर दें तो उनकी गाद निकल जाए। उपाध्यक्ष महोदय, दुख की बात है कि गाद निकालने के लिए जो पैसा था, उसमें से पैसा खा लिया गया। मैं उसका यहां पर जिक्र नही करना चाहूंगी लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूं कि 10 साल से नहरों की गाद नही निकालीं गई है, इसीलिए पंजाब से पानी कम आता है। बेरला पम्प हाउस के बारे में भी मेरा एक सवाल था, मैंने इस बारे में कालिंग अटैशन मोशन दिया था। कही पानी ज्यादा आता है और कहीं पानी की कमी होती है। उस पानी की कमी को दूर कर दें। अगर आप इसके प्रति थोडे सै विजिलैट रहें तो यह कमी दूर हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो छुट्टियां इतनी हो जाती हैं कि अगर घण्टों का हिसाब लगाया जाए तो 365 दिन में 7 दिन भी नहीं बैठते हैं। अब दोनों मियां–बीबी अफसर हैं और उनमें से एक के साथ भी नाराजगी हो जाए तो दूसरा भी काम नहीं करता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनमें से एक को दूसरी स्टेट में लगाएं तो उनको पता चलेगा कि काम कैसे होता है। उपाध्यक्ष महोदय, बात करते समय एक ये सर जी, मैडम जी, का प्रयोग करते हैं, पता नही यह

क्या बोलते हैं। सर अंग्रेजी में है और जी हिन्दी में है, अगर इन्हें अंग्रेजी ही बोलनी है तो कम से कम पूरी बोलें।

इसी के साथ मैं आपके माध्यम से इनकी नौलेज में सड़कों की बात भी लाना चाहती हूं कि सड्कों में सुधार हुआ है। जिन गांवों में सड़कें नहीं बनी थी लेकिन अब वे बनी हैं। लेकिन ढिगावा गांव को जो सड़क जाती है, उसका बहुत ही बुरा हाल है। जो सड़कें कस्बो में जाती हैं, उनके साथ–साथ नाली बननी चाहिए। जब हम कोई सड़क बनाने को कहते हैं तो कोई कहता है कि पंचायत बनाएगी और कोई कहता है कि मार्किट कमेटी बनाएगी। मैं तो यह कहती हूं कि सबको मिलकर यह काम करना चाहिए। भिवानी और लोहारू की सड़कें है, वह बहुत ही. लम्बी हैं। जब हम दिल्ली को जाते है तो झज्जर से हो कर जाते हैं और बहकला गांव रास्ते में पड़ता है। वहां पर सड़क का बहुत ही. बुरा हाल है। ये अफसर तो वहां जाते नहीं हैं, अगर जाते भी हैं तो इनकी अपनी गाड़ियां नही होती है और ये सरकारी गाड़ियों में होते हैं जिससे इनको कोई असर नही पड़ता है। वहां पर पानी आने की वजह से सड्कों का बहुत ही बुरा हाल है।

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ वार्डर है जो भी मैम्बर बोलें वह डिमांड नं० बोल कर बोलें ताकि हमें यह पता चले कि वे किस डिमांड पर बोल रहे हैं। इसमें लैक्चर का तो कोई काम नहीं है, ये पहले बजट पर भी बोल चुके है, गवर्नर एड्रैस पर भी बोल चुके हैं। अब ये सिर्फ

डिमांड पर ही बोलें ताकि हमें भी बात समझ आए और कन्सर्नड मन्त्री जवाब भी दें सके। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है। मैं नेहरा जी. को यह कहना चाहूंगा कि माननीय चन्द्रावती जी सबसे सीनियर मैम्बर हैं। नेहरा जी आप हमें तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन यह क्यों भूल जाते हैं कि बहन जी हमारे में से नही है, यह आप में से ही हैं। वित्त मन्दी जी को तो यह नोट करना चाहिए, जो मैम्बर साहिबान बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने श्री असलम खां जी. से डिस्कशन शुरू करवायी, इसमे अपोजीशन और रूलिंग पार्टी का सवाल नही है। ये बार बार डिमांड का नाम लेकर हैकल कर रहे हैं।

Mr. Deputy Speaker : There is no question of hackling. He 1 3 only making a suggestion.

प्रो० छतर सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कट मोशन दी गई है, यह हमारी तरफ से दी गई है और इन पर हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिये जबकि हमें मौका नही दिया गया है, हम इस बारे में आपकी रूलिंग चाहेंगे।

Mr. Deputy Speaker : Discussion on Demands and discussion **on** cut motions will take place simultaneously. Members may speak either on demands or cut motions. It is their option.

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर सर, मैने पहले ही कहा है कि कुछ बातें तो मैं जरूर दोहराऊंगी क्योंकि प्यासे आदमी को जब तक पानी नही मिलेगा तब तक वह पानी पानी ही कहेगा। मैं कहना चाहती हूं कि आज जो जीपें चलती हैं, जुगाडू चलते हैं, उनको पुलिस वाले या आर० टी० ओ० मन मानी करके खडे कर लेते है। इसलिये मेरा कहना यह है कि या तो आप उनको रैगुलराईज कर दीजिए या फिर इनको बंद कर दीजिए। मैं आपको इस बारें मे एक केस बताना चाहूंगी कि होली से एक दिन पहले नारनौल की एक जीप जा रही थी लेकिन उसको आदमपुर ढाणी के एक ए० एस० आई० ने रोक लिया और उसको लेकर अपने घर चला गया। उसने ड्राईवर से कहा कि मैं यह जीप परसों लाकर तुझे वापस कर दूंगा। जीप वाला मेर पास आया तब मैंने एस० पी० को फोन करके वह जीप छुडवायी लेकिन उस बेचारे की जीप तनि दिन तक उसके पास ही रही। इस तरह से या तो इन जीपों को और इन जुगाड़ों को रैगुलराईज कीजिए या फिर इनको करवा दीजिए। ये सब पब्लिक की दिक्कत की चीजें हैं। आप इन बातों को को ट्रांसपोर्ट की डिमांड में ले सकते हैं या होम की डिमांड में ले सकते हैं, किसी भी डिमांड में इन बातों को आप ले सकते हैं। पुलिस वाले इनकी जीपों को या जुगाडू को पैसे लेकर छोड़ते हैं। अगर मैं एस० पी० को टेलीफोन नहीं करती तो शायद वह पुलिस वाला उसको जीप नहीं देता। मै बेकार के लिए टैलीफोन नहीं करती बल्कि लोगो के कामों के लिये ही टेलीफोन करती हूं। इसलिये ही मेरे टैलीफोन का बिल काफी आ जाता है। आज

सरकार के पास पैसे की क्यों कमी रहती है? डिप्टी स्पीकर सर, सेल्ज टैक्स का एक वकील है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती वह अफसरों के पास जाता हैं और उनसे मिलता है लेकिन अफसर भी क्या करें क्योंकि उनको भी अपने परिवार का पेट पालना होता है। ट्रांसपोर्ट तो कमाई का धंधा है, इसलिये अगर सरकार सेल्ज टैक्स और इन्कम टैक्स को पूरा वसूल करे तो फिर पैसे की कमी नही रहेगी।

इसी तरह से जहां तक बिजली की बात है 1 मेरे हल्के में 1987 से लेकर 1991 तक कोई भी बिजली का नया कनैक्शन नही मिला। यह बात ठीक है कि सरकार ने कुछ कनैक्शन्ज दिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी. कमी बनी रहतरू है। बिजली की कमी तब तक पूरी नही हो सकती जब तक आप नये थर्मल पावर प्लान्टस नहीं लगाएंगे क्योंकि बिजली की खपत तो दिन प्रतिदिन वढ़ती जा रही है। आबादी भी बढ़ रही है और लोगो की जरुरतों भी बढ़ रही हैं। आज बिजली से ही दूध बिलौया जाता है। आज आपका बिजली मोल ले ने से काम नही चलेगा बल्कि थर्मल पावर प्लांट लगाने कीं वेहद जरुरत है। मैं जब गांवों में जाती हूं तो देखती हूं कि गांवों में लोगो को बिजली ही नही मिलती। अगर हमें स्वयं को बिजली न मिले तो हम। री क्या हालत हो जाती है? जब गांवों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पढ्ने के लिये भी बिजली नही मिलती.। एक तरफ तो उनको मास्टर नही पढ़ाते हैं और

दूसरी तरफ उनको बिजली भी पढ्ने के लिये नही मिलती। उनको तो बिजली मिलनी ही चाहिए।

इसी तरह से नकल रोकने का काफी इंतजाम हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी नकल चली है। मेरे गांव में भी नकल चली। लौगों ने मुझसे कहा कि लड़कियां पढ़ती है इसलिये थोड़ी बहुत तो नकल होनी चाहिये लेकिन मैंने उनसे कहा कि नही मैं तो नकल के खिलाफ हूं। नकल नहीं होनी चाहिये। मैं श्री देवेन्द्र सिह और गक्खड जी को नकल रोकने के लिये बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने जो नकल रोकने के लिये काम किए हैं उसके कारण इसमें काफी सुधार हुआ है। मैंनै अपना एक सवाल दिया था वह अभी तक तो आया नही है हो सकता है कि कल आ जाए। डिप्टी स्पीकर सर, आज लोग बिहार से और हरिद्वार से नकली सर्टिफिकेट ले आते हैं जिसके कारण हमारे अपने मेहनत करके पत्रने वाले बच्चे तो रह जाते हैं और वे ऐडमिशन ले लेते हैं। जे० बी० टी० में दाखिला करने का दफ्तर वगैरह तो गुडगांव में है लेकिन वे कभी तो मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। मुलाना जी ने काफी कोशिश की लेकिन इसके बावजूद भी काफी गलत गलत काम हो जाते है। उसके लिए चाहिए कि या तो वह औफिस चन्डीगढ़ में हो या किसी बीच की जगह हो। गुड़गांव में सारा सारा दिन टैलीफोन नहीं मिलता है अगर टैलीफोन मिल जाता है तो कोई उठाता नही है सुओ–मोटो तो जो काम होते हैं वह आपको भी पता हैं हमको भी पता है कि किस तरह से होते हैं

यह सारी चीजें बड़ी– जरूरी है। बिजली की चोरी बहुत ज्यादा होती है। एक उद्योगपति दस हजार रुपए की बिजली की चोरी करता है तो किसान दस रुपये की क्र लेता है। उसके बारे में कोई इलाज तो हो। ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं थोडी सी बात कहना चाहती हूं। मेरे हल्के में इंटीटियर के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बसें कम जाती हैं। दादरी डिपो का कुछ हिस्सा भिवानी में चरना जाता है, कुछ दादरी में चला जाता है। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। चहड हमारा बहुत बड़ा गांव है, 10 जमा 2 का स्कूल है, बसें कम जाती हैं। वहां बस तो जानी चाहिए। वैसे भी मेरा हल्का कुछ महेन्द्रगढ़ में है, कुछ हिसार में है, कुछ भिवानी में है, इसलिये भी मुझे लोगो को काम कहने में मुश्किल आती है मैं मुख्य मन्त्री जी से चाहती हूं कि यह एक जिले में नहीं तो दो जिलों में तो हो ही जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को काम देने के लिये कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। अव्वल तो इंडस्ट्रीज कम हैं जो हैं, वह घाटे में चल रही है। जो आफीसर काम नही करना चाहते, जिनका इमेज अच्छी नहीं है, वे अगर किसी जरुरी महकमे पर लगे हुए हैं तो उनके वहां से हटाना चाहिए। 'लोग कहते हैं कि हम पोलिटिशियन करप्ट है मै तो यह कहती हूं कि अगर हम क्रप्ट हैं तो व्योक्रेटस भी हमारे बराबर क्रप्ट हैं। हमसे कम नही है तभी देश का बेडा बैठा हुआ है। मैं डिमांड के हक में ही कहना चाहती हूं, डिमांड पास होनी चाहिए। आपका शुक्रिया।

श्री अमर सिंह दौडे (गुहला, एस० सी०): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड पर बोलने का टाईम दिया इसके लिये आपका बहुत–वहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर – 8 पर कहना चाहूंगा। सड़को के बारे में जो भी मैम्बर बोलता है वह यही बात कहता है कि हरियाणा में सड्कों का बुरा हाल है, सड़कें टुटी पड़ी है। सर्वे रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि मन्त्री जी ने सड़कें बढ़ाने की बजाए कम कर दी हैं। यह पैसा कहां खर्च होता है। सड़कों की रिपेयर के बारे में मैंने आज सवाल उठाया था और कहा था कि मेरे हल्के में सड़कों की रिपेयर के लिये जो पैसा मंजूर हुआ है वह सड्कों पर खर्च न होकर पता नही कहां खर्च हो गया। सड्कों का इतना बुरा हाल है कि व्हीकल लेकर चलना तो दूर की बात है पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे हल्के में जहां तक पुलों की बात है। घग्घर नदी पर एक पुल बनाने की बात थी। ढढोता गांव है वहां घग्घर नदी पर पुल बनने की बात मैंने, जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था, तब भी कही थी। मेरे हल्के के 15–20 गांव उस पुल की वजह से कटे रहते है। बरसात के दिनों मे 15–20 गांव ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं आ जा सकते। उन गांवों का कोई आदमी चीका मंडी में नही जा सकता। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने शुरू में आश्वासन दिया था कि हमने पुल मंजूर कर दिया है और जल्दी ही. पैसा मिलने पर काम चालू कर देंगे परन्तु अफसोस की बात है कि चार साल हो गये हैं, अब तक कोई काम नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस पुल का काम एक

सार्वजनिक हित का काम है, भलाई का काम है। इस पुल को जल्दी बना दिया जाए क्योंकि इस पुल के बनने से लगभग 15–20 गांवों को फायदा होगा।

दूसरी बात मैं शिक्षा से संबंधित कहना चाहता हूं। हमने तो यह सोचा था कि हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय, बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा ही काम करे गे लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि मेरे हल्के में जितने भी प्राईमरी, मिडल, हाई व जमा दो प्रणाली के जितने भी स्कूल्ज है उनमें अध्यापकों की संख्या पूरी नही है। कोई भी प्राईमरी स्कूल ऐसा नही है जहां अध्यापक पूरे हों। बच्चों को चार पांच किलोमीटर पैदल चलकर स्कूलों में जाना पड़ता है। मेरे अपने हल्के के गांव मछरेडी मे एक स्कूल है, जहां पर कोई मास्टर नही है। मेरे हल्के में कई बड़े–बड़े गांव है जिनमें प्राईमरी स्कूल्ज है, उनमे एक ही. मास्टर है। मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से यह कहना चाडूगा कि अगर वे शिक्षा को सुधारना चाहते हो तो सब से पहले जो शिक्षा की बुनियाद प्राईमरी स्कूल्ज हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। वहां पर टीचर्ज की स्ट्रैन्थ को पूरा करना होगा ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें। हमारे प्रिय नेता ओम प्रकाश चौटाला जी की लोकप्रिय सरकार जब इस प्रदेश में थी, उस वक्त बहुत से स्कूल्ज अप–ग्रेड किये गये थे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अब इस सरकार के बनने के बाद, भागल व चीका के स्कूल क् 2 के लिये अपग्रेड हुए थे, बेसारे के सारे

डि–ग्रेड कर दिये गये। मैं यह चाहूंगा कि चाहे हम अपोजिशन के मैम्बर हैं, सरकार को किसी भी हल्के के साथ इस तन की भेदभाव की नीति नही बरतनी चाहिये जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो, बच्चे अच्छी शिक्षा न ले सके। जिस तरह से दूसरे मैम्बर्ज के हल्के में स्कूल्ज अप–ग्रेड किये जाते है उसी तरह से अपोजीशन के मैम्बर्ज के हल्कों में भी स्कूल्ज अप ग्रेड होने चाहियें। किसी के साथ भेदभाव की नीति. नहीं बरती जानी चाहिए

अब मैं मैडीकल की बात भी कहना चाहूंगा कि आज सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है। कोई डाक्टर मांके पर नहीं मिलता। समय पर मरीजों को दवाईयां नही मिलती। मैं हैल्थ मिनिस्टर जी को कहूंगा कि गुहला हल्का में जो अस्पताल है, वहां पर दो डाक्टर्ज हैं, एक मिस्टर डोगरा और दूसरी मिसेज डोगरा। वहां पर इनको पता नहीं किसलिये बैठा रखा है? वहां के लोगों की यह शिकायत है कि ये दोनों डाक्टर्ज अस्पताल में मिलते नहीं हैं और न ही कोई काम करते है जिससे लोगों को बड़ी भारी असुविधा है। इसलिये लोग बार बार मांग करते रहते हैं कि उन को वहां से बदला जाए लेकिन पता नही वे लोग कोई न कोई पोलिटीकल ऐप्रोच करके फिर वहीं पर आ जाते हैं। हर साल उनकी बदली रोकी जाती है। उन डाक्टर्ज ने उस एरिया का बुरा हाल कर रखा है। वे सरेआम लोगों से पसे लेते अब मैं कर्मचारियों से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हू। कर्मचारियों की रिजर्वेशन से मुताल्लिक कहना चाहूंगा। इस बारे में मेरा क्वैश्चन

भी था कि हरिजनों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। जितने भी सरकारी विभाग हैं उन में कहीं पर भी बी० सी० व हरिजन कर्मचारियों को रिजर्वेशन का कोटा नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया है और न ही सरकार कोई कदम उठा रही. है। आज हरियाणा के अन्दर नौकरियों का बुरा हाल है आज हरियाणा के सरकारी विभागों में रिजवेंशन से संबंधित मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त हरियाणा में क्लास वन की 2106 पोस्टें हैं, जिनमें से केवल 122 हरिजन ही लगे हुए हैं और हुस हिसाब से यह 5.30 परसैन्ट का ही कोटा बनता है क्लास टू में 8688 टोटल पोस्टें हैं जिनमें से 492 हरिजन आफिसर काम कर रहे हैं इसकी परसैन्टेज केवल 5 64 ही बनती है जबकि भारत सरकार में संविधान के अनुसार हमारा सरकारी नौकरियों में कोटा 20 परसैन्ट होना चाहिये। इस तरह से यह सरकार हरिजनों के साथ मजाक कर रही है और रिजर्वेशन के कोटे को नौकरियों में लागू नहीं कर रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, क्लास थी की पोस्टें हरियाणा के अन्दर कुल 1,83,577 हैं। इनमें हरिजन 18855 हैं। यह कोटा सिर्फ 10.3 परसैन्ट बनता है। क्लास फोर में तो आपको पता है कि हमारे स्वीपर भाई ज्यादा होते है इसलिये वह कोटा तो पूरा है लेकिन बाकी तीनों क्लासों में हमारा कोटा कम है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस सरकार बड़े बलन्द दावे करती है कि हम हरिजनों की भलाई के काम करते हैं और उनको अच्छी नौकरियां दे रहे हैं। तो जो बातें मैने आपके सामने कही आप उनसे

अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार हरिजनो का कितना भला करना चाहती है। पिछले सैशन में भी बात आई थी कि जो सरकार में जाट अफसर हैं, इस सरकार ने उनकी फाईलों पर '''जे'' शब्द लिख दिया। यह ठीक है कि जाट कांग्रेस को वोट नही देते लेकिन काग्रेस आज हरिजन और बैक्वर्ड भाइयो की वोट से ही सत्ता में बैठी सिचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह जो माननीय सदस्य कह रहे है यह बात दुरुस्त नहीं है। इनको यह कहना शोभा नही देता कि जाट कांग्रेस को वोट नही देते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जाट जीत कर भी बहुत आए है और उन्होने कांग्रेस को वोट भी दिया है। इसलिये इनको ऐसी बात नही कहनी चाहिए।

श्री अमर सिंह ढांडे: डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली विधान सभा में कांग्रेस के एक एम० एल० ए० ने बात उठाई थी कि इन्होने खुद उसकी फाइल पर ''जे'' शब्द लिख दिया। यह सरकार कहती है कि हम हरिजनों का भला करना चाहते है। ये लोग जो ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हैं, ये हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की दया से बैठे हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारा 20 परसैन्ट का कोटा बनता है वह पूरा किया जाए। वह चाहे हरिजन का हो या बैकवर्ड का हो। सरकार इसको टाईम बाऊंड करे कि कब तक बैक लौग को पूरा कर देंगे और कब तक हमारी रिजर्वेशन को पूरा करेगे। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह से

चौधरी देवी लाल ने हरिजनों की भलाई का काम किया था कि उन्होंने क्लास बन और टू में परमोशन में भी रिजर्वेशन दी थी उसी तरह से मैं इस सरकार से चाहता हूं कि यह भी उसको लागू करे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार हरिजनों का भला करना चाहती है तो जो हमारे भाई सरकारी नौकरियों में बैठे है उनका रोस्टर सिस्टम ठीक किया जाए ताकि उनको समय पर परमोशन मिल सके। भारत सरकार ने संविधान के तहत जो सुविधा हरिजनों को दी हुई है उसको पूरा किया जाए। यह सरकार कोई ऐसा बिल पास करे कि जो सरकारी अधिकारी रिजर्वेशन पूरा नहीं करता उसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही कर सके जिससे उसको दंड दिया जा सके। जो अधिकारी अपने विभाग में 20 परसेंट या और जितनी भी रिजर्वेशन बनती है उसको पूरी नही करता उसके बारे में सरकार विधान सभा में बिल ले कर आए कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगा।

लोक सम्पर्क राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र कुमार मदान): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। मेरे साथी रिजर्वेशन के बारे में बोल रहे थे। जब इनकी सरकार थी और चौधरी. ओम प्रकाश चौटाला मुख्य मन्त्री थे उस समय चौधरी टेक चन्द मार्किटिग बोर्ड के चेयरमैन थे वहां पर 100 से क्लर्की की भर्ती हुई थी उसमें रिजर्व' कोटे की सी टे थी लेकिन इन लोगों ने रिजर्व कोटे के अगेन्स्ट जनरल कैटेगरी के कंडाडेटस रख लिए। फिर आज ये रिजर्वेशन की क्या बात करते है? उस के

अन्दर ढांडे साहब के हल्के के सीवन गांव का एक जनरल कैटेगरी का लड़का था वह लड़का मेरे एक दोस्त का दोस्त है– उसको इन्होंने हरिजन कोटे में सिलैक्ट कर दिया। जब उसको ज्वायन करवाने गए तो उस समय कहा गया कि आप सर्टिफिकेट लाओ कि आप हरिजन हैं। किस मुह से रिजर्वेशन की बात करते है? कमाल की बात है। इन्होंने हरिजनों के साथ जो सलूक किया है, वह मैं बताता हूं। मेरे हल्के के गांव गूणा के हरिजनों को उजाड़' कर इन्होने बरवाला में बसा दिया। श्री किरपा राम पूनिया उस वक्त कैबिनेट में मन्त्री थे, उनको उस समय उचाना गांव में लोगों ने घुसने नहीं दिया।

श्री सतबीर सिंह कादियानः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। मदान साहब अब तो मन्त्री है। ये चौधरी देवी लाल जी की सरकार में रूलिंग पार्टी के एम० एल० ए० थे, मिनिस्टर थे लेकिन आखिरी दिन ये चोर दरवाजे से भाग गए। कोई बात नही यह इनकी मर्जी है, ये भगौड़ा हो सकते है। लेकिन चौधरी देबी लाल जी ने हरिजनों के लिए सीट रिजर्व की, उनकी परमोशन के लिये रोस्टर बनाया। उस समय हरिजनों के साथ किसी तरह की ज्यादती नही की गई, चाहे कोई भर्ती की गई और चाहे कोई परमोशन की गई। उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई।

श्री सुरेश कुमार मदानः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं चोर दरवाजे से नही भागा। मैंने उस

समय एम०एल०ए० और मन्त्री पद से अपना इस्तीफा दिया था। यह रिकार्ड की बात है। मैं चोर दरवाजे से नही भागा। इनके नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मझे हराने के लिये कोई कमी नहीं छोड़ा, फिर भी मैं इनकी छाती पर मूंग दल कर जीत कर आया हूं।

श्री सतबीर सिंह कादियानः यह मदान अब भी भागेगा। कांग्रेस का सत्यानाश हो लिया। अब भी भागना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र कुमारः महान में इस पार्टी को छोड़ कर कभी नहीं भागूंगा। आपके चुनाव जीत कर दिखाऊंगा।

श्री अमर सिंह ढांडेः डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजनों के नौकरियों में रिजवशन देने की बात चल रही थी, उस समय मुख्य मंत्री सदन में नही थे, अब आ गए हैं, इस लिये मैं वह बात दोबारा कह देता हूं। अगर आप हरिजन भाईयों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयो की भलाई करना चाहते हैं तो विधान सभा में एक ऐसा बिल पास करे कि जो सरकारी अधिकारी रिजर्व कोटे को पूरा नही करता, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसा बिल विधान सभा में पास करें ताकि हरिजन भाईयों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयो की भलाई हो सके। हर रोज अखबारों में यह खबर छपती है कि हरिजनो के साथ बैकवर्ड क्लासिज के भाइयो के साथ गांवो के अन्दर और शहरों के अन्दर बहुत बदसलूकी की जाती है। क्योड़क गांव यहां पर कई बार चची का विषय बना है।

मैं मुख्य मन्त्री जी को एक बात कहना चाहता हूं, पता नही सरकारी अधिकारी इनकी पूरी रिपोर्ट देते है या नही या उसमे कोई लाकूना रह जाता है। शर्मा जी ने जो बात कही वह सत्य थी। उपाध्यक्ष महोदय, क्योड़क गांव के 100 हरिजन परिवार गांव छोड़ कर चले गए थे। कहां पर बाद मैं हरिजनों ने पंचायत की जिसमें 1000 के करीब हरिजन इकट्ठे हुए थे, बाद में फैसला होने पर उनके वापस गांव में छोड़ कर आए थे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब भी 25 परिवार गांव छोड़ कर जा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जिन अफसरो ने उन हरिजनों का मुंह काला करके और गले में जूतों की माला डालकर घुमाया था, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये। जितनी बेइज्जती उनकी हुई है, कोई भी उस गांव में अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता। बगैर किसी कसूर के, उनका काला मुंह किया गया और गले में जूतों की माला डाली गई। मदान जी भी जो मंत्री हैं, उस फैसले में शामिल थे, इन्होंने भी माना था कि उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी पता नहीं अभी तक इस्तिफा क्यों नही दिया? उपाध्यक्ष महोदय, जो परिवार अब भी गांव से बाहर है, मैं उनके नाम पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है कि मैंने इस्तिफा क्यों नही दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर दो हरिजन गुटों का आपस में झगड़ा था। दोनों ही हरिजन गुटों को समझाया गया था। डी० आई०जी०

कमीशनर, एस०पी०, डी० सी० ने भी उनको समझाया। वे दो दिन तक डी० सी० साहब की कोठी के बाहर धरने पर बैठे रहे। वे एक पूर्ण नामक नम्बरदार के यहां पर रुके थे, जिनकी अर्बन स्टेट में कोठी है। हरिजनों का आपस में झगड़ा हो गया और उनका आपस में फैसला करा दिया गया हो जिसमें ये भी मौजूद थे, तो फिर इस्तिफा देने वाली बात कहां से आ गई? आज कोई परिवार ऐसा नही है जो उस गांव से बाहर है, बेशक आप इसका पता करवा लें। सभी लोग बड़े प्यार अ और मोहब्बत से रह रहे हैं। जातिवाद का नारा फैलाकर, झगड़ा करवा कर राजनैतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए।

श्री अमर सिंह ढांडेः मंत्री जी कह रहे हैं कि वे दो दिन धरने पर रहे। मैं बताना चाहता हूं कि वे 5– 1– 95 से 5–2– 95 तक धरने पर बैठे रहे। पता नहीं इनको गलत बात कहने की क्यों आदत है? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको बसाने का काम करना चाहिये। अखबारों कीं कटिंग भी मेरे पास है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप जल्दी खत्म करें।

श्री अमर सिंह ढांडेः उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे मे कहना चाहता हूं। बसों की हालत बहुत खराब है। मेरे गुह ला हल्के में 1 फ 3– 95 को एक बस दुर्घटना हुई जिसमें 8, लोग मारे गए। मरने वाले में गुह ला हल्के के दौ आदमी एक

औरत, एक ड्राईवर और दूसरे पांच व्यक्ति मारे गए थे। मैं चाहता हूं कि उनको सरकार उचित मुआवजा दे।

12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, गुहला क्षेत्र पूरी तरह से उपजाऊ क्षेत्र है। आज बिजली. किसानों के लिये जरूरतमंद चीज हो चुकी है। मेरे हल्के में जितने भी पावर हाउस हैं सब अन्डर लोड हैं। सरकार जो 4– 5 घंटे बिजली देती है, वह भी इन पावर हा उस के अन्डर लोड होने के कारण पूरा लोड नहीं उठा पाते। मैं चाहूंगा कि उनको अपग्रेड करें। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक हमारे हल्के में नये पावर हाउस बनाने की बात है बलबेड़ा एक बहुत बड़ा गांव है, उसके 33 के० वी० के ऐस्टिमेट्स पहुंच चुके हैं। मैंनै इस बारे में कवारतन गांव का एक क्वैश्चन भइ। किया था और मंत्री जी ने जवाब भी दिया था कि वहां पर 33 के० वी० का पावर हाउस बनाएंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि गांव कवारतन व बलबेड़ा पर जल्दी ही काम शुरू करवाएं ताकि लौगों को उससे फायदा मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने डिमाण्ड के अन्दर जो पैसा रखा है, हम सरकार से चाहते है कि जो पैसा जिस मद के लिये रखा गया है, वह पैसा उसी मद पर खर्च किया जाना चाहिये चाहे वह पैसा हरिजनों के कल्याण के लिये हो, चाहे कोई सड्कों या पुलों आदि के बनाने के लिये हो, वह उसी काम पर खर्च होना चाहिये जिसके लिए पैसा लिया गया है। इसके साथ ही मैं गुहला हल्के की एक और जरूरी बात कहना चाहता हूं। गुहला

हल्के में एक बांध बना हुआ है जो कि काफी दिन पहले बना था। पंजाब से फलड का पानी आता था और उस पानी से गुहला और ची का को बचाने के लिये यह बांध बनाया गया था। वह बांध बहुत पुराना हो गया है। 20–25 गांव हरियाणा के इसके पीछे पड़ते हैं जो कि बरसात के दिनों में फ्लड के पानी से श्री तरह से डूब जाते हैं और उनकी फसलें भी पानी में डूब जाती हैं। पानी का प्रैशर बढ़ जाने पर बांध टुट जाता है जो गांव बांध से आगे हैं उनमें बहुत तबाही होती है और नुकसान होता है। पिछले फलड में गुहला हल्के के 40–45 गांव बिल्कुल तबाह हो गए थे। गांवों में 8– 10 फुट तक पानी खड़ा हो गया था। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस बांध का कोई समुचित प्रबन्ध करें और स्पैशल इन्जीनियर्ज की कोई टीम भेज कर वहां का सर्वे करवाएं कि उस बांध से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो बाढ हर साल तबाही मचाती है उससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा तथा फसलों और जानमाल की जो हानि होती है वह भी रुकेगी। उस बांध के बारे में सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से जिस तरह से यह सरकार काम कर रही है, अगर उसी तरह से आगे भी काम करती रही तो ये पलट कर जाने वाले नही हैं इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि ये जनता को सुविधा देने तथा राहत पहुंचाने के कामों की तरफ पूरा ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम): उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मुख्य मंत्री जी ने बोलते हुए इन्टरवीन किया था। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, आप डिमांड नम्बर बता कर बोलें।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा हूं। क्या यह केवल मेरे लिये ही जरूरी है अभी तक तो आपने अपनी जो रूलिंग दी थी कि कोई किसी प्रकार बोले। जब असलम खां जी बोल रहे थे तब आपकी यह रूलिंग थी लेकिन अब आपकी दूसरी रूलिंग आ गई है। मैं इस पर भी स्टिक करूंगा।

श्री उपाध्यक्षः जैसे आपकी मर्जी है वैसे बोलें। मैंने जो कहा है वह जनरल प्रैक्टिस है।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, जनरल प्रैक्टिस मुझ पर ही क्यों लागू की जा रही है? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि इस सरकार के आने के बाद कुल सरकारी नौकरियों की संख्या क्या थी और उनमें हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासिज का कितना कोटा बनता था। जो कोटा हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज का बनता था, क्या उस को पूरा किया गया या नही, अगर पूरा नहीं किया गया तो उसका क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों और बैकवर्ड के नाम को मुख्य मन्त्री जी एक्सप्लायट करते हैं लेकिन उनके कोटे की जो

नौकरियां हैं, वे दूसरी जगहों पर चले। जाती हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज का नौकरियों में जो कोटा है, वह कितने परसैट पूरा हुआ है, अगर पूरा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं किया गया? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी से एक और सवाल पूछा था कि वर्ल्ड बैंक से सरकार कितना लोन ले रही है, किस–किस डिपार्टमैंट के लिये कितना–कितना लोन लिया गया है? मेरे क्यूने का मतलब है कि इरीगेशन के लिये, एजूकेशन के लिये, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये या हरियाणा सरकार की किसी भी कारपोरेशन के लिए कितना–कितना लोन लिया गया है? उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के कान्स्टीच्यूशन के आर्टिकल 293 (3) मे दिया हुआ है कि जब स्टेट गवर्नमैंट लोन लेगी तो उसकी गारन्टी भारत सरकार देगी। मैं यह इसलिये जानना चाहता हूं कि कही ऐसा न हो कि हरियाणा सरकार इतना ज्यादा लोन ले ले कि बाद में हरियाणा उसका ब्याज भी न चुका सके। यह एक वहुत ही अहम सवाल है, मैं इसका जवाब मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा। अब मुख्यमंत्री जी की मर्जी है कि ये जवाब दें या न दें। यह लोन का मसला छोटा मसला नहीं है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अजमत खां जी रूलिंग पार्टी के एम०एल० ए० हैं और ये माइनज के चेयरमैन भी हैं। उनका व्यान आया था कि अगर सारी माईनज का ठेका हमें दे दिया जाए तो हम बुढ़ापा पैन्शन तो देंगे ही और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड में भी पैसा दे देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब इधर–उधर से दे दिया और कहा कि हाई कोर्ट से स्टे आ चुका

है। हाई कोर्ट ने तो प्रोसीजर पर स्टे दिया था तो ये उसको पूरा कर देते। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के स्टे के बाद प्राईवेट लोगों को खाने क्यों दे दी गई? अगर ये उनको न देते तो इनका सवा करोड़ रुपए या दो करोड़ रुपये का नुक्सान हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फ्रीडम फाईटर की रिजर्वेशन हम 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि तामिलनाडू सरकार ने यह रिजर्वेशन 75 प्रतिशत कर दी और केस भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार ने इसको कांस्टीच्यूट कर दिया। उसके बाद कर्नाटक वालों ने भी 82 प्रतिशत कर दिया है और भारत सरकार को यह केस भेजा हुआ है तथा भारत सरकार उसको भी कांस्टीच्यूट करने जा रही है। तो हरियाणा मे यह क्यों नही हो रहा है, ये दो प्रतिशत ही बढ़ा दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि बंसी लाल लोगों का खून पीता है, मैं तो यह कहता हूं कि चौधरी भजन लाल सारे हरियाणा के लोगों का खून पीता है। दूसरे इन्होंने कर्मचारियों की बात कही मैंने कर्मचारियो के साथ क्या किया है? उपाध्यक्ष महोदय, 50 हजार के करीब कर्मचारी मेरे घर के पास मीटिंग करके गए और मैंने एक भी कर्मचारी को सस्पैड नही किया। इन्हाने तो लाटिया चलाई हैं। कर्मचारियों को रेलों और बसों में से पकड़—पकड कर उतारा है और अगर कोई

कर्मचारी नहीं मिला तो उसके घर से उसके बीबी– बच्चों को ही पकड़ लाए थे। मेरा फातिया तो पिछली बार कर्मचारियों ने पढ़ दिया था, अब की बार इनका फातिया कर्मचारी पढ़ देंगे। जब यह बात हुई थी तो कांग्रेस के एक माननीय सदस्य पण्डित चिरंजी लाल हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भजन लाल कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर गया है और मरा हुआ सांप बंसी लाल के गले में डाल गया है। कांग्रेस की हार तो भजन लाल के कारण हुई लेकिन वह मरा हुआ सांप बनी' लाल के गले भी दिया। यह –सब तो भजन लाल ने किया है, मैं तो ऐसे काम नही करता है।

एक और जवाब में मुख्यमंत्री ने कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया का हिसार के बारे में हवाला दिया। इन्होंने यह कह दिया कि हम आपके पास कागज भेज देगे लेकिन वह कागज आज तक मेरे पास नही पहुंचा है। कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया ने जुलाई 1991 में यह प्वायंट आउट किया था और 1993 में भी किया था कि इसमें 1 करोड़ 43 लाख 46 हजार का घाटा हिसार डिस्टिलरी की वजह से हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यें कहते हैं कि उसकी बात बिल्कुल सही है तो ये' उसका जवाब क्यों नही दे पाए? कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया कोई पोलीटीकल आदमी नही है जिसका ये कह देंगे कि यह पार्शियल रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें बेबुनियाद हैं और हकीकत मे तो यह टैक्स की चोरी है। इसी तरह से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन तो है ही कहां? क्योंकि

डिप्टी कमिश्नर जिला काग्रेस का प्रधान है, पुलिस कप्तान जनरल सैक्रेटरी है, तहसीलदार खजांची है और बाकी जितने मुलाजिम हैं.. .... (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप इनसे कहें कि ये मुझे बीच में न टोके, वरना फिर आपको मेरा टाईम बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ–साथ और भी जो अकसर हैं, वे इनके कार्यकर्ता हैं। सरकार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। सरकार अगर कहीं पर हो तो मैं आपको बताऊं। यह मैं नही कह रहा हूं, यह तो लोग कहते हैं मैं तो कभी–कभी ही कहता हूं। पंडित चिरंजी लाल ने जो कहा है मैं उसको कोट करता हूं। उन्होंने प्रधान मन्त्री को चिट्ठी लिखी है। मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी उन्होंने यह भी लिखा है कि तीन जनवरी को मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ने उनके लड़के कुलदीप को एक सरकारी मुलाजिम के दफ्तर में बुलाकर उसको धमकी दी और उससे कहा कि अपने पिता को समझा कि प्रधानमंत्री के आवास पर उन्होने जो मेरे सम्बन्ध में कहा है, वह टक नही है। मेरा नाम भजन लाल है। मैं रगड़कर रख दूंगा तेरे बाप जैसे सौ सांसद मेरी जेब में हैं। इस बात की न तो पंडित चिरंजी लाल ने कट्राडिक्शन की है और न ही मुख्यमंत्री जी ने कट्राडिक्शन की है। मेरे पास यह नौ मार्च का अखबार है। आज का नहीं है, आज तो कोई कंट्राडिक्शन नही आयी। उपाध्यक्ष महोदय, पंडित चिरंजी लाल ने यह भी कहा कि हम तो कहते ही रहे है कि महाजन नेतृत्व के सफाये के लिये हविपा विधायक ओ०पी० जिन्दल पर इन्होंने जो अत्याचार किए वह सबके सामने

हैं। उनको टाडा के तहत जेल तक पहुंचाने की साजिश मुख्यमंत्री ने की थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इनके सांसद कहते है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैंने एक बात बीजों के बारे में कही' थी लेकिन मुख्यमत्री जी ने बीज के केस का जवाब गोलमोल कर दिया। करनाल मे जिस कम्पनी ने नकली बीज बेचा था उसके बारे मे मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि उस कम्पनी के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया और दो आदमी को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उन दो आदमि यों को गिरफ्तार करने का क्या नतीजा निकला क्या इंक्वायरी हुई? मुख्य मंत्री जी ने बीज की अरली वैरायटी और लेट वैरायटी बताये थी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कैथल गया था तो मैंने वहां पर इस बारे में कसानों मै बात की थी तो उन्होंने बताया कि यह जो पी०आर० 103 वैरायटी हैं इसमे अरली और लेट वैरायटी का कोई सवाल ही नही पैदा होता बल्कि इसमें तो एक ही वैरायटी होती है। जिसने यह बीज बेचा है? उसके पास तो सीड बेचने का लाईसेसं ही नहीं है। उसके पास तो फर्टिलाइजर बेचने का लाईसेंस है। जिसने इसका बिल काटकर दिया है? मैं नहीं समझता कि उस आदमी को बीग बेचने का अधिकार था। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि केवल 19 एकड़ में ही बीज खराब था लेकिन वहां तो 600 क्विंटल से भी ज्यादा बीज बिका है। क्या 600 क्विंटल बीज 19 एकड में ही बोया जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय इन चीजों में घपला बहुत बढ़ा है लेकिन सरकार इस बारे में कोई ऐक्शन नही ले रहीं है। कानून

कायदे के तहत तो कोई आदमी खुला बीज नही बेचा सकता लेकिन इसमें खुला बीज बेचा गया है और 12 रुपये या 20 रुपये देकर उनसे कट्टा वापस ले लिया गया। 31 किलोग्राम बीज बेचा गया जबकि 31 किलग्राम का फर्टिलाइजर का कोई कट्टा नहीं होता है, कोई पैकेज नही होता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी ऐसी बाते है जिन पर इनकी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही है क्योंकि इस सरकार के आगे पीछे कोई नहीं है। इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि पंजाब में गन्ने को ले जाने में कोई रुकावट न ही है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैंने कल ही जब कैथल में लोगे से यह कहा कि मैंने विधान सभा में मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई पाबन्दी नही है। वहां पर सैकड़ों किसानों ने हाथ, खड़े करके आवाज लगायी कि गन्ना प्रदेश से बाहर जाने के लिये रोक रखा है। उपाध्यक्ष महोदय इसके बाद अब किसान खुद ही समझ लेगें, कि क्या हो रहा है या फिर मुख्यमंत्री जी इस बारे में खुद जवाब दे देंगे।

इसके अलावा, आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने मौलेसिस का रेट प्रति क्विंटल 180 के बजाए 200 रुपये कर दया और 50 परसैन्ट कोटा रिजर्व कर दिया क्यों 200 रुपये का झगड़ा रख दिया, 100 का 100 परसैट खुला रख दो। उसमें किसान के गन्ने की कीमत बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय जे यमुना नदी के जल वितरण का मामला है उससे अभी तक मुख्यमंत्री जी तसल्ली बख्श

जवाब नहीं दे पाए कि राजस्थान के माथ जो बांध बने है, उन बांधों का पानी लिए बगैर, उसके बदले में पानी लिए बगैर आपने दस्तखत क्यों कर दिए? मुख्यमंत्री जी अभी तक इसको अच्छी तरह से क्लेरीफाई नहीं कर पाए है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ इसको मुख्य मंत्री जो ने कहा कि किसान को हम जो बिजली देते हैं, उस पर एक डेढ़ रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से मुखयमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमको हाइडल पावर प्रोजैक्ट मे कितनी बिजली मिलती हैमेरे हिसाब से करीब 1/3 मिलती है। क्या वह भी डेढ़ या अढाई रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलती है? किसान के०पर रेट ऐसा लगा दिया कि किसान चाहे दो एकड़ धरती का मालिक हो, उसे कम से कम इतना तो देना पड़ेगा, 300 या 350 रुपये कुछ रखे है। मैं यह नही समझता कि किसान को बिजली देने सै हरियाणा सरकार को नुकसान होता है। सरकार को कोई नुकसान नही होता है। किसान जो देश के लिये कमाई करता है जिससे सेल टैक्स मिलता है, उससे आगे काम बढ़ता है, उससे आमदनी होती है, वह सरकार को याद ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, किसानो की मोटरे जल जातो हैं। कल भी मुझे कैथल में लोगों ने कहा कि कई–कई दिन बिजली नही आती। दो दिन से पहले कभी आती ही नही, एक दिन आती है तो दूसरे दिन नही आती। कई जगह हफ्ते–हफ्ते बिजली चली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहूंगा होम तो एक ही होम है, मुख्यमंत्री जी का होम है, बाकी तो हरियाणा मे कही होम रहा ही नही। जितनी आज ला एण्ड आर्डर की सिचुण्शन हरियाणा में खराब है, मेरे ख्याल में उतनी किसी अड़ोस–पड़ोस के प्रदेश में नही है। कल्प होते हैं, रेप होते हैं और पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाते हैं। फिर जो केस ठीक हों, सही केस हों बेवर्ज नहीं होते। उपाध्यक्ष महोदय, हो भी कैसे, जब पुलिस वालो को रिश्वत लेकर भर्ती किया जाता है तो क्या होगा, वे तो कमाई पूरी करेगे। इसलिये होम–डिपार्टमेट का जहां तक सवाल है, होम डिपार्टमैट की बहुत खसता हालत है, चाहे जिसको अपर क्लास के लिये भेज दिया, चाहे जिसकी तरक्की कर दी, चाहे जिसको साल में छह जगह तबदील कर दिया, चाहे जिसकी ए०सी०आर० खराब करवा दी, चाहे जिसको सजा करवा दी। छोटे कर्मचारियों को जब तक एसोसिएशन्स बनाने का अधिकार नही दिया जाएगा, वे अपने हकों के लिये लड़ नही सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू की बात आ गई। प्रदेश के टूर करते वक्त मुझे बहुत सी जगह लोग मिलते हैं, वे कहते है कि हमारे इंतकाल दर्ज नहीं होते। रजिस्ट्रियों पर इतने परसैटं मांगते है, वह परसैटेज न देतो रजिस्ट्री नही होती। अगर०पर किसी के पास शिकायत करें तो कोई सुनवाई नही करता। क्या कहें इसका?

उपाध्यक्ष महोदय, एजूकेशन में इन्ही के मैम्बर का एक प्रस्ताव भी आज के लिए का हुआ था। दो साल से ज्यादा, हो गए, कौपिग के बारे में चल जा था कि कौपिग न हो। कौपिग रोकने के लिए सुशीला कुमारी की हत्या की गई और जिस द्वारा हत्या की गई, वह आदमी कभी मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी में था। (विघ्न) जवाब देते समय बता देना। एजूकेशन की हालत तो यह है कि कहीं मास्टर नही है। एजूकेशन बोर्ड ने ऐसा कर दिया कि 5–5, 7– 7 साल पहले लोग फेल हो गए थे, वे भी पास कर दिए। इसी एजूकेशन के सिलसिले में स्कैण्डल आउट करने के लिए यूनिवर्सिटी के श्री रणबीर सुहाग का भी कत्ल हो गया, उसने पुलिस कप्तान को लिखकर दिया कि मुझे सिक्योरिटी दो, उसको सिक्योरिटी नही मिली। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): कितनी बार दोहराआगे?

चौधरी बसी लालः जितनी बार आप सही जवाब नही देंगे, मैं दोहराऊंगा, मेरा काम यही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के बहुत से सीनियर प्रोफेसर हथियारो का लाइसैस मांग रहे है। कई प्रोफेसर्ज जो 60, 70 हजार रुपये के सैलरिड परसन हैं इसीलिए, वे रिवाल्वर या बदूंक खरीदना ऐफोर्ड नही कर सकते लेकिन इसके बावजूद भी वे लाइसैन्स मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। यह इनकी ऐजूकेशन की हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 10 पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैडीकल कालेज मैं कोई स्थान पूरे नही हैं। केवल गिनती के ही स्थान पूरे होंगे। मेरे विचार से गवर्नमैंट आफ हरियाणा को मैडीकल काऊंसिल आफ इंडिया ने यह लिखा है कि अगर आप, जो कंडीशज हैं, उनको पूरा नही कर सकोगे तो इस मैडीकल कालेज को डी–रिकगनाइज कर दिया जाएगा। उसी दिन से मैंने यह कहा था लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। मैं तो यह कहता हूं कि इसके लिये कानून रिलैक्स कीजिए, जो मर्जी चाहे कर लीजिएगा, लेकिन रोहतक मैडीकल कालिज की हालत सुधारें, क्योंकि यह मामला लोगो की सेहत से जुड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश के सैन्टर में वह एक मैडीकल कालेज है, दूसरा भी चाहे बना लो, अच्छी बात है। लेकिन इस के साथ–साथ मैं यह भी कहूंगा कि मैडीकल कालेज के प्रोफेसर, चाहे वे कितनी भीं तनख्वाह क्यो न मांगे, वहां अच्छे से अच्छे प्रोफेसर भर्ती करिएगा, चाहे बाहर से ही एन्गेज क्यों न करने पड़े लेकिन मैडीकल कालेज रोहतक की हालत सुधरे। एक वह भी जमाना था कि जब एक स्टूडेन्ट रोहतक मैडीकल कालेज से एम०बी० बी०एस० या एम०डी० करके निकलता था, अगर वह किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने चला गया तो जाते ही वह सिलेक्ट हो जाता था लेकिन आज हालत यह है कि वे रोहतक मैडीकल कालेज का नाम सुनते ही स्टूडैन्ट रिजेक्ट हो जाता है। मुख्यमत्री जी आप इसको सुधारों, इसकी वर्किग को आप सुधारें। वहां के इक्विपमैंट का सुधार करिए। कई सालों से इक्विपमैंट

खराब पड़े हैं। आपके पास, कोई अच्छे–अच्छे प्रोफेसर्ज नहीं है आपके पास, कोई अच्छे–अच्छे डाक्टर्ज नहीं हैं। जैसे पीछे डाक्टर मडिया रिटायर हुए। वे बड़े अच्छे सर्जन थे। बम्बई से, कलकत्ता से खास करके किडनी आपरेशन के लिए लोग उनके पास आते थे, उनको ऐक्सटैन्शन देनी चाहिए थी। इसी तरह से डाक्टर श्रीवास्तव थे, वे भी रिटायर हुए, उन्को भी ऐक्सटैन्शन देना चाहिए थी। अच्छे डाक्टर्ज को रखना चाहिए था। ऐज की रिलैक्शसेशन दो, कोई भी किसी तरह की रिलैक्शसेशन दो, लेकिन मैडीकल कालेज में डाक्टर्ज अच्छे होने चाहिए। लेकिन आज हस्पतालों की हालत यह है कि अच्छी दवाई नहीं मिलतीं, अच्छे डाक्टर्ज नहीं मिलते। यहां तक कि डंगरों के डाक्टर्ज भी नहीं मिल रहे हैं। इन बातों पर मुख्य मन्त्री ध्यान देवे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इरीगेशन में भी मुख्य मन्त्री महोदय क्लेम करते हैं, सिंचाई व इरीगेशन मन्त्री क्लेम करते है कि इतने दिनों तक या इस मौनसून से पहले नहरों की गाद निकलवा देंगे, नहरों की डी–सिल्टिग करवा देंगे। आज तक डी–सिल्टिग कही हुई, हमने देखी नहीं है। हमने नहरों के किनारों पर खड़े होकर देखा भी है कि जो छोटी–छोटी नहरें हैं, उनके दोनों तरफ छोटे–छोटे पौधे व सरकण्डे खड़े हैं। अगर उसमें कहीं गाय भैस भी चलती जाए तो वह नजर नहीं आएगी। इतनी बुरी हालत है, वहां की। इसी तरह से इरीगेशन में जो एन०बी०के० लिंक्स हैं, उसकी 2700 क्यूसिक्स पानी चलने की कैपेसिटी है और

उसमें पानी केवल चल रहा है 1700 क्यूसिक्स, बाकी एस०वाई०एल० में चलाना पड़ता है। उस एन०बी०के० के लिक को भी ठीक करवाना चाहिए ताकि उसमें पानी. ज्यादा जा सके और पंजाब से भी पूरा पानी आ सके। पंजाब वाले बहुत बार यह कहते हैं कि हरियाणा को पानी हम इसलिए नही देते क्योंकि उनके पास ज्यादा पानी लेने की कैपेसिटी नहीं है। क्या यह. कोई अच्छी बात है? इरीगेशन के०पर हमारी सरकार जितना खर्च करे, हम खुशी से उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इरीगेशन से जितना पानी जाएगा उतना ही। किसानों के खेतों को ज्यादा पानी मिलेगा और नैशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। नैशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इससे नेशन का फायदा होगा, नेशन का फायदा होगा तो उससे किसान, मजदूर और प्रदेश का भी फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तक से मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री महोदय ने उस दिन जवाब नहीं दिया था। मैंने एक बात कही थी कि टूरिज्म वालों के जो टूरिस्ट स्थान हैं, उनका स्टैण्डर्ड बहुत खराब है। बहुत से टूरिस्ट बाहर से आते हैं। पंजाब से जाने वाले, आगरा जाने वाले और जयपुर वगैरह जाने वाले भी हरियाणा से होकर गुजरते हैं। मैंने इस बारे में एक दिन एक बात कही थी कि चाहे आप 10 रुपए कमरे का किराया और बढ़ा दो, मगर उनकी सफाई रखो, कपड़े साफ रखो। मैं क्या बताऊं, वहां पर जो तकिए इन लोगों ने रख रखे हैं, उनको जब आप लगाओगे तो उनमें से छोटे छोटे दाने वहां पर

बिखरते जाएंगे। यह हालत इनके तकियों की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाहर से जब टूरिस्ट आता है और ये उससे 480 रुपए किराए के लेते हैं तो कम से कम वह आराम से तो ठहर सके। उस रोज आपने फरमाया, डिप्टी स्पीकर साहब, कि अम्बाला में पीने का पानी नहर का है। वहां पर एक बार मैं थोड़ा पानी दे गया था। मैंने अम्बाला के लोगों से मुलाकात की और खास तौर से पत्रकार भाइयों से बात की तो वे कहने लगे कि आप अम्बाला की बात भी कहते है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका नाम नही लिया। मैंने असैम्बली में कह दिया कि अम्बाला, कैथल, रिवाड़ी, होडल वगैरह जगहो का पानी खराब है। यानी बड़े–बड़े शहरो का कई जिलों मे पानी खराब है और वह पीने के काबिल नहीं है लेकिन सरकार के कानों तक जूं नही रेंगती। जब तक इन सब का प्रबन्ध नही हो जाता, कस वक्त तक पार नहीं पड़ेगी। मैं खास तौर से मुख्य मन्त्री जी से दो बातों का जबाब चाहूंगा। एक तो बैकवर्ड और हरिजनो का कोटा कितना पूरा किया और दूसरे वर्ल्ड बैक से किस–किस महकमे के लिए कितना कितना लोन जिया, उसका सालाना ब्याज क्या होगा, आगे कितना लोन ले रहे है जिसके लिए आपने एग्रीमैंट किया होगा और उसका टोटल ब्याज कितना होगा, उसे स्टेट दे सकेगी या नही?

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने जो बातें कही है, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। बंसी लाल जी कल सदन मे नही थे, कही सैर करने गए थे। उपाध्यक्ष

महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहा और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। सरकार का भी यह फर्ज बनता है कि अगर माननीय सदस्य कोई बात हाउस मे उठाए, उसका जवाब सरकार को तसल्लीबक्श देना चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी ने सब से पहले तो हरिजन और बैकवर्ड के कोटे की बात की। शुक्र है परमात्मा का कि इन्होने हरिजनों के बारे में कुछ हमदर्दी दिखाई। वरना तो उनके सब से ज्यादा खिलाफ थे तो ये थे।

व्यैक्तिक स्पष्टीकरण

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष 'महोदय, आन–ए–प्वायट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मैं हरिजनों या बैकवर्ड क्लासिज के. खिलाफ कभी नहीं रहा। (शोर)

चौधरी भजन लालः तोशाम और भिवानी में हरिजन, चमार, एक भी आपको वोट नही डालता। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल तो हरिजनों को चीचड़ कहते है। (शोर)

चौधरी बंसी लालः आन–ए–प्वायंट आफ ' पर्सनल एक्कलेनेशन अगेन। मैंने यह कहा था कि चौधरी देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि अगर भैस खरीद लें तो चीचड़

तो साथ ही आ –जाएगे। अगर ये जाटों को साथ ले लें तो चीचड़ तो साथ आ लेगे। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष. महोदय, इन्होने बाबू जगजीवन राम को झोटा कहा था। (शोर)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। ये बाबू जगजीवन राम को कहने लगे कि ये दो कौडी का आदमी नहीं है। बाबू जी ने भिवानी की मीटिंग, मे खुद कहा था कि आदमी कौड़ी का नही होता। अगर ये रुपए का कह देते यानी 15 हजार रुपए या एक लाख रुपए का कह देते तो समझ में आता क्योंकि कौड़ी की तो कोई कीमत ही नही होती। (शोर)

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम जैसे भले. आदमी के बारे में मुख्य मन्त्री जी ऐसी बात कह रहे हैं। मैंने उनकी शान के खिलाफ भी कभी नहीं कहा।

चौधरी भजन लालः जब ये मुख्य मन्त्री थे तो मैं इनकी कैबिनिट मे मन्त्री था। इन्होंने रिवाड़ी में बाबू जगजीवन राम की स्टेज पर जूते फेंककर थे। (शोर) और भद्दी से भद्दी बात इन्होंने कही। यह रिकार्ड की बात है। यह बात मैं नहीं कहता।

चौधरी बंसी लालः डिप्टी स्पीकर साहब, आन–ए–प्यायंट औफ पर्सनल एक्सप्लैनेशन।

चौधरी भजन लाल: किन बात का पर्सनल एक्सप्लेनेशन है?

चौधरी बंसी लाल: आप जरा सुनने की शक्ति रखिए। आपने हाउस का दो दिन का सैशन घटा दिया। वह, इसलिए घटा दिया क्योंकि, आपमें हमारी बातें सुनने की हिम्मत नही है, इसलिए भाग रहे हो। आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जगरीवन राम मेरे मंत्रित्व काल में भी नारनौल नहीं आए। दूसरी बात यह कि बाबू जनजीवन राम के स्टैचू पर एका आदमी ने रिवाड़ी मे जूता फैका था।

चौधरी भजन लाल: चलो वह रिवाड़ी की बात होगी।

चौधरी बंसी लाल: जब रिवाड़ी में जूता फेंका तो हमने उस आदमी को गिरफ्तार किया और उसको मजा कराई। उस आदमी के बारे में मैंने खुद क्य–कार से रिकार्ड ले कर बाबू जी को बताया कि यह डिफैसं के महकमे से मैंटली रिटार्डिड, डिसचार्जड किया गया है, यह इसका सर्टिफिकेट है। आप यह चौक कर लें और बाबू जी ने मान लिया कि हां है।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुभाष बतरा): स्पीकर साहब, मुझे इस बात का इल्म है कि बाबू जगजीवन राम रोहतक में आए थे उसके बाद उनका जलसा भिवानी में था। उन्होंने रोहतक में यह बात कही थी जिसको मैंने अपने कानों से सुना था। बाबू जी

ने उस समय यह कहा था कि बंसी लाल ने मुझे दो कौड़ी का कहा है, अब मैं भिवानी में दो करोड़ आदमियों को देखने जा रहा हूं।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने कान से सुना था या अपनी आख से देखा यह इनकी जड़ी हुई कहानी. है। इनके पल्ले और कुछ नही है, यह यही कहेंगे।

श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा): स्पीकर साहब, मैं उस सभा में मौजूद था। जो बातें बतरा साहब ने कही है, मैं उसकी ताईद करता हूं। यह सच्ची बात है। ये सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नही है।

वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरिजन भाईयों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों के रिजर्व कोटे के बारे में कहा। जब मैं छोड़ कर गया था उस समय सभी पोस्टों पर लगभग पूरा कोटा करके गया था यानि 20 परसैटं कोटा हरिजन भाईयों का पूर। करके गया था और 10 परसैटं कोटा बैकवर्ड क्लासिज भाईयों का पूरा करके गया था और यह बैकवर्ड क्लासिज का रिजर्व कोटा मैने ही दो परसैट से बढ़ा कर 10 परसैटं किया था। रोस्टर सिस्टम मैंने ही बनाया था। रोस्टर सिस्टम होना चाहिए ताकि तीन के बाद हरिजन लगे और बैकवर्ड

क्लास का भाई भी लगे। इन्हेंने उस रोस्टर सिस्टम को खत्म कर दिया। मैंने जो रोस्टर सिस्टम बनाया था, इन्होंने उसको तोड़ दिया। मैं रिजर्व कोटे को लगभग पूरा करके गया था, जब मैंने दोबारा आ करके देखा तो हरिजनों का 20 परसैटं से घट कर 12 परसैंट पर आ गया। अब हमने उसको 17 परसैटं के लगभग वापिस पहुंचा दिया है। जो मैंने बैकवर्ड क्लासिज का कोटा 10 परसैटं पूरा किया था, उसको इन्होंने घटा कर 6 परसैंट ला दिया, उसको हम 9 परसैंट के करीब वापिस ले आए हैं।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हू कि आपने अपने साढ़े तीन साल के अर्से में टोटल कितनी भर्तियां की? जितनी भर्तियां की, उनमें कितने हरिजन और कितने बैकवर्ड– क्लासिज के भाई भर्ती किए? आपने जो 30 एच०सी०एस० भर्ती किए, उनमे हरिजन कितने और बैकवर्ड क्लासिज के कितने भर्ती किए?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास टोटल आकड़े नही हैं। वह क्लब–अलग महकमे से लेने पडते हैं। आपको टोटल आकडे चाहिए तो आप को लिखकर भेज देंगे।

चौधरी बंसी लालः आप उन 30 एच०सीं०एस० का बता दें।

चौधरी भजन लालः उसमें रिजर्वेशन नहीं होती। उनकी रिकार्ड के आधार पर नोमिनेशन होती है। उसमे रिजर्वेशन नहीं

है। अध्यक्ष महोदय इन्होंने एक्ट बात यह कहा कि वर्ल्ड बैक से कितना लोन लिया। इस बारे में हमारे पास पूरे आकडे हैं और वह आपको वित्त मंत्री बताएगे। महकमे वाइज अलग अलग स्कीम्ज के लिए कितना–कितना पैसा लिया अगर मैं आपको, पूरी डिटेल बताऊं तो उसमें बहुत ज्यादा सभव लग जाएगा। किस किस महकमों ने कितना–कितना पैसा किस किस प्रयोजना के लिए लिया है, यह वित्त मंत्री जी बता देंगे।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माईनर्ज, के बारे में कह दिया। एच०एम०एल० चेयरमैन ने भी कहा कि इसका कन्ट्रोल एच०एम०एल० को देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन मैंने इसके बारे में आपको कहा था शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। (विघन) अध्यक्ष महोदया जहां तक–खानों का ताल्लुक है, फरीदाबाद में आनन्दपुर बड़खल पाली प्राईवेट पार्टियों को सिलिका सैड की माइन्जूरी दी गई हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करके अक्तूकबर 1986 में समय से पूर्व लीक समाप्त करके हरियाणा मिनरल्ज लिमिटिड को चौधरी बंसी लाल जी ने दे दी। (विघन) यह बात बिलकुल ठीक हो लेकिन उसके बाद में इन आदेशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4–12–86 को, माइनिग की लीज के आदेश को अवैध घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10–12–86 को राज्य सरकार ने जब अपील की सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कह दिया कि नहीं, यह गलत है और

फिर चौथरी बंसी लाल जी ने ही 18– 12–86 को, जिनके पास पहले लीज पर थी, उनको वापस ली। इन्होंने अपने हाथ से उनको वापस की, यह रिकार्ड की बात है।

चौधरी बंसी लालः मैंने तो हरियाणा मिनरल्ज लिमिल्डि को दी, थी। हाई कोर्ट ने भी इस प्यायंट पर स्टे दिया था कि प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया है क्योंकि नई अमैंड मैंड हुई थी पार्लियामैंट में, उसका हरियाणा को आफिसर्ज करे पता नहीं था। अब वह कानूनी कार्यवाही पूरी करके छुट्टी करो।

चौधरी भजन लालः ये वापस आपने 12वें महीने सन् 1986 में दी थी और मई तक आप चीफ मिनिस्टर रहे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जनवरी, 1994 को मिनरल्ज एक्ट 1957 में संशोधन करके भी उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र देने के लिए छूट दे दी कि दे सकते हैं। दूसरे अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कह दि या और भारत सरकार ने भी कह दिया, भारत सरकार ने स्टे दे दी कि नहीं डनके पास रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व जिला फरीदाबाद में 1989 में महत्वपूर्ण खानें आनन्दपुर, पाली, बड़खल आदि नीलामी द्वारा दी जाती थी। 1989 मे हरियाणा मिनरल्ज लिमिटिड को 5 साल के लिए पट्टे पर दी गई। इन्हीं क्षेत्रों में सिलिका सैड मेजर मिनरल्ज 1 983– 84 के लिए प्राईवेट पार्टियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई। फिर जो इनसे इंकम हुई, वह मैं बताना चाहता हूं। वर्ष 1986– 87 में 5 करोड 12 लाख रुपए आए, वर्ष 1991– 92 में 9 करोड़ 91 लाख

रुपए, 1 993– 94 में 18 करोड़ 27 लाख रुपए और 1994– 95 में 22 करोड़ रुपए होने जा रही है। कहां इनके वक्त मे 5 करोड़ थी और कहां अब 22 करोड़ होने जा रही है, यानि 4 गुना ज्यादा इन्कम आज इससे होने जा रही है।

चौधरी बंसी लालः जब के भाव और अब के भावों की तुलना करके देखो तो पता चलेगा।

चौधरी भजन लालः दूसरे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात स्वतन्त्रता सेनानियो के लिए कह दी कि उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से देश आजाद हुआ। उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं और आजादी में सुख का सांस ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि फलां जगह पर 81 प्रतिशत और फलां जगह पर 69 प्रतिशत रिजर्वेशन है। स्पीकर साहब, ये वकील तो हैं लेकिन अखबार जरा कम पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि अखबार दोपहर के बाद 8 आने रद्दी में बिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि रिजर्वेशन 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। (विघ्न)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, क्या तामिलनाडू में रिजर्वेशन 69 प्रतिशत नहीं है और क्या इसके लिए हिन्दुस्तान के विधान में तरमीम नहीं की गई? (विघ्न)

चौधरी भजन लालः उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा (विघ्न)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, विधान के उस प्रोविजन को अल्ट्रावायरस कान्स्टीच्यूट कर दिया।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर किसी को मानना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, 20 प्रतिशत रिजर्वेशन हरिजन भाईयों के लिए, 10 प्रतिशत बैकवर्ड भाईयों के लिए, 17 प्रतिशत एक्स सर्विसमैन और दूसरे लोगों को तथा 3 प्रतिशत हैंडिकैप्ट की रिजर्वेशन है। इस प्रकार यह 50 प्रतिशत रिजर्वेशन हो गई। इनमें मे किसकी रिजर्वेशन कम की जा सकती है। किसी के कोटे को हम कम नहीं कर सकते, इसलिए हम ने यह फैसला किया है कि जो कोटा पूरा नहीं होगा, उसमें सबसे पहले जो स्वाधीनता सेनानी हैं, जिन्होंने जंगे–आजादी मैं भाग लिया, उनके आश्रितों को उनके बेटे–बेटियों, पोते पोतियों, दोहते–दोहतियो को दिया जाएं। (विघ्न) दूसरे इन्होंने सरकारी कर्मचारियो के बारे मे कह दिया। खुदा का शुक्र है कि इनको भी कर्मचारियों की याद आई। चौधरी बंसी लाल जी ने कर्मचारियों की क्या हालत की थी। अध्यक्ष महोदय, एक लाख कर्मचारी दिल्ली

में गए थे। उनके नुमाइंदे मुझे भी मिले थे, तब मैं केन्द्र में मन्की था, उन्होंने कहा था कि ये कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मैने भी इनसे कहा कि कम से कम इनकी बात तो सुन लें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मैं इनकी कोई बात नही सुनता। इनका इलाज मैं जानता हूं। ये बड़े बदमाश हैं, डण्डों से इनको लम्बा बना दूंगा, इनके सीधा कर दूंगा। मेरे हाथ में जूता है। (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बसी लालः अध्यक्ष महोदय, ओन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी की यह आदत है कि वे गलत बात को 100 बार कह कर सच्ची बनाना चाहते हैं लेकिन वह सच्ची बनती नहीं है सरकारी कर्मचारियों के साथ इन्होंने जो किया है वे ही अगली बार इनका फातिया पढ़ कर बता देगें कि ये कहां पर खड़े हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जब ये बोल रहे थे तो मैंने इनको बीच में नही रोका लेकिन ये बार–बार बोल कर मेरी स्पीड तोड़ देते हैं।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि बाद में पूछ लेना और जब मैं पूछने के लिए खड़ा हुआ तो हाउस

ऐडजर्न कर के भाग गए, इसलिए मुझे बचि–बीच मे इतना पड़ रहा है, वरना बीच में बोल कर मैं राजी नहीं हुं।

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी हाउस का टाईम बढ़ाने के बाद भी अगर 10– 12 मैम्बर्ज खड़े हो जाए तो किस–किस को टाईम देंगे और फिर हाउस को अन–लिमिडिट समय के लिए तो बढ़ा नही सकते, इसलिए ऐडजर्न करना पड़ा था।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, शायद सदन 2 दिन इसी लिए चटाया गया है ताकि सभी अच्छी तरह से बोल लें।

वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

(पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः क्या कोई मैम्बर बोलने के? लिए खड़ा था, क्या किसी मैम्बर को बोलने में कोई रूचि थी। अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के सभी लोग बोल चुके थे, कोई बाकी नहीं, था। इधर के भी सभी बोल लिये थे। अध्यक्ष महोदय, यें लोग तो रैलियों में लगे हुए थे। कोई 22 और कोई 23 प्रतिशत हैं, तक को मिला कर 45 प्रतिशत हो गए, बाकी बचे 55 प्रतिशत अकेली काग्रेंस पार्टी के। (विघ्न) मैंने तो 22 और 23 मिलाकर 45 प्रतिशत. बताया था। 45 परसैटं में दोनों पार्टियों के, 55 परसेंट कांग्रेस के हो गये। दोनों को मिलाओ तो 100 ही होता है। (विघ्न) अब कर्मचारियों की हालत इन्होंने दिल्ली में जा कर क्या

करो, यह भी. सब जानते हैं। वहां पर ये हरियाणा की पुलिस ले गए और ये जमुना का पानी भर कर ले गए और इन्होंने उन कर्मचारियों के०पर पानी छुड़वाया था, उन्हें पानी में डूबो–डूबो कर बाहर निकाला। उन कर्मचारियों ने यह प्रण किया कि जब तक जिन्दा हैं बंसी लाल को नहीं आने देंगे। यह कस्म उन्होंने जमुना का पानी हाथ में लेकर खाई और साढ़े तीन लाख कर्मचारियों ने अपने अपने रिश्तेदारों के वोट दूसरे बक्से में डाल दिए और इनका फातिया पढ़ा गया।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, दें ने तो इस बात को मान लिया है और अब की. बार तो इनका फातिया पढ़ा जाना है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने कर्मचारियों के लिए जो कुछ किया है, वह किसी ने भी नही किया है। कर्मचारियों का हमारे०पर विश्वास है, वे हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। कर्मचारी तो प्रदेश की रीढ की हड्डी हैं। हम इनकी तरह जालिम नही हैं। हमने कर्मचारियों की हर बात का ध्यान रखा है। अध्यक्ष सहोदय, मुझे मैम्बर्ज ने बताया कि बंसी लाल लोबी में कह रहे थे कि पं० चिरंजी लाल ने जो भजन लाल के खिलाफ दिया है उस सें वह कोई न कोई फायदा उठाना सहता है। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी ने तो हाउस में माना है कि इन्होंने कर्मचारियों को धमकी भी दी है। इस बारे में इन्होने तीन बार माना है और यह रिकार्ड की बात है। आपने राजबीर के मामले में कहा किं आपने उसको धमकी दी। बंसी लाल जी धमकी देना तो कानूनी जुर्म है।

(विघ्न) मैं तो उनसे अपनी बात कहता हूं। मैंने चिर जी लाल के लडके को नही धमकाया है। चिरजी लाल जी चुने हुए नुमायंदे है, एम० पी० है। (विघ्न) वे हमारे साथी हैं।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आज तक मुख्य मन्त्री जी की कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई है। पंडित चिरंजीलाल ने प्रैस कान्फ्रैस में यह क्हा है कि 3 जनवरी को मुख्य मन्त्री ने स्वयं करनाल कचेहरी से एक सरकारी अधिकारी के टेलीफोन पर उनके पुत कूलदीप शमी, एडवोकेट को बुलाकर यह कहा और धमकी दी कि अपने पिता को समझा दें कि इन्होने 'प्रधान मंत्री आवास पर मेरे सम्बन्ध में जो अपशब्द कहें हैं, वह ठीक बात नहीं है। मेरा नाम भजन लाल है और मैं रगड़ कर रख दूंगा। तेरे बाप जैसे 100 एम० पी० मैं अपनी जेब में रखता? हूं। इस बारे में ,आज तक मुख्यमन्त्री की कोई कट्राडिक्शन नही आई है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह लगता है कि यह ध्यान इनका ही छपवाया हुआ है। चिरंजी लाल तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते। अगर मैं इनका जवाब दूं तो मुझे अखबार में जवाब देने की क्या जरूरत है? अगर कोई गलत बात कहेगा तो उसके लिए वह अनुशासनहीनता करेगा और अनुशासनहीनता के लिए कमेटी बनी हुई है इसलिए वह कमेटी ही इस बारे में ऐक्शन लेगी। हमें इस बात से कोई लेना देना नही है। हमने किसी को भीं नहीं धमकाया और न ही हमारी धमकाने की कोई आदत है।

अध्यक्ष महोदय, गहोने हिसार डिस्टीलरी के बारे में भी कह दिया तथा कम्पट्रोलर एड ओडीटर जनरल की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि पहले एक नियम था कि जब शीरा किसी को अलौट करते हैं तो उसमें कितनी परसैट स्प्रिट बनेगी, इसका एक नार्म बना हुआ है। जैसे भट्ठे में बीस टन कोयले में एक लाख ईटें बनेगी। इसी तरह से जो कोयला बिजली के प्रौजेक्टस में जाता है, पावर स्टेशन में जाता है तो उसमें से कितनी परसैन्ट कोल जलनी चाहिए कितनी बिजली बननी चाहिये इसका एक नार्म है। यह नार्म बहुत पहले का यानि चालीस साल का मुकर्रर किया हुआ है कि इसमें से इतने परसैन्ट स्प्रिट बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद लगभग सारी फैक्ट्रियों का मोडर्नाजेशन किया गया। इसलिए शीरे में जो चीनी जाती है वह चीनी उसमें जानी कम हो गयी और चीनी की मिकदार बढ़ गयी। पहले जहां यह मिकदार 55 परसैट थी, वही अब यह 40–42 परसैंट हो गयी। 1990–91 में जब इनका राज था जो सामने बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हिसार डिस्टीलरी की बाकायदा चौकिंग करवायी थी और इन्हेने एम० शंकर सहित तीन आदमियों की एक कमेटी भी बनायी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उसके मुताबिक अब जो नार्म्ज हैं, वह कम होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने उसको बदलकर 30.5 परसैन्ट किया रहै। इसी तरह से उत्तर प्रदेश एवं हमारी पानीपत की कोआप्रेटिव शूगर मिल ने भी यह कम किया है। 1991–92 मैं हमारी पानीपत की कोआप्रेटिव फैक्ट्री में 31.04 परसैन्ट शीरा बनी जबकि हिसार डिस्टीलरी में 31.77

परसैन्ट बनी। (इसी तरह से 1992– 93 में पानीपत की कोआपरेटिव फैक्ट्री में 30.26 परसैट शीरा बनी जबकि हिसार डिस्टीलरी में 32.24 परसैन्ट। इसी प्रकार से 1993–94 में पानीपत की कोआपरेटिव फैक्ट्री में 26.14 और हिसार डिस्टलरी में 29.50 परसैट शीरा बनी। अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है। इन्हेंने आडी–टर जनरल की रिपोर्ट उठायी और कहा कि 36. 64 परसैन्ट बना दी और इसमें इतनी स्पिरिट बनती और इतनी शीरा बनती एवं इतनी शराब बनती। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक क्वालिटी की बात है। जो कमेटी ब नी हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट दी. है और बताया है कि यह परसेंट क्या होनी चाहिए। अगर उस परसैन्ट से ज्यादा बने या कोई आदमी गड़बड़ करने को बात करे तब तो यह कह सकते हैं लेकिन इनको तो हिसार डिस्टलरी का बहुत फोबिया हो गया है। चाहे आपका राज रहा हो या हमारे सामने बैठने वालों का राज रहा हो, तो इन्होंने भी एक एक चीज को चौक करके देख लिया।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, हिसार डिस्टीलरी से हमें कोई ऐलर्जी नही है। मैं तो एक बात मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सी० ए० जी० तो कोई पोलिटिकल आदमी नहीं है, उनकी रिपोर्ट में हिसार डिस्टीलरी का ही क्यों पैरा आया है, बाकी दोनों डिस्टलरी का पैरा क्यों नही आया?

चौधरी भजन लालः क्योंकि एक ही डिस्टीलरी का आडिट हुआ है, दूसरी डिस्टीलरीज का आडिट नहीं हुआ है। जब

आडिट होगा तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सी० ए० जी.० की. रिपोर्ट क्या कहती है, वह मैं आपको बताता हूं।

श्री अध्यक्षः बंसी लाल जी, सी० ए० जी० की रिपोर्ट. तो आती रहती है, पहले भी आती रही है,।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आडीटर जनरल की रिपोर्ट किसको कहते हैं, यह उसको कहते हैं जैसे इन्होंने बिजली' के सामान की परचेज की थी और उसका आडिट हुआ था। मैं आपको बताता हूं कि देश का आडीटर जनरल क्या कहता है? 1972 में इन्होंने बिजली के तारों में एक करोड़ पचास लाख रुपये का घपला किया था, ट्रांसफार्मर्ज में इन्होंने दो करोड़ पचास लाख रुपये का घपला किया था, मीटर्ज में 85 लाख रुपये का घपला किया था, केवल्य में तीस लाख रुपये का घपला किया था, फिर 15 लाख रुपये का घपला किया और उसके बाद फिर पोल्ज में 20 लाख रुपये का घपला किया है। पोल्ज के बारे मे तो चौटाला साहब ने भी कहा है कि पंजाब के रिजैक्टिड हुए पुराने पोल्ज इन्होंने लिए। इसके अतिरिक्त दूसरे आईटम पर पचास लाख रुपये का घपला किया है, यानी कुल मिलाकर इन्होने 6 करोड़ रुपये का घपला किया है। अध्यक्ष महोदय, आडीटर जनरल की रिपोर्ट इसको कहते हैं क्योंकि आडीटर जनरल की रिपोर्ट यह कहती है। रिपोर्ट उसको नही कहते हैं 'आडीटर जनरल ने कहा कि बंसी लाल ने परचेज में इतना कमीशन खाया है।'

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लालः ऑन ए प्याइंट ऑफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन सर, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने चार कैबिनेट के मंत्रियों की कमेटी बनाई थी उसमें सरदार स्वर्ण सिंह, बी० आर० कुमारमंगलम, लॉ मिनिस्टर श्री गोखले और फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसमें उन्होंने मुझे पूरी तरह से एग्जोनरेट किया था। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। यह रिकार्ड की बात है। बेमतलब की गलत बात कहकर अपने आपको क्लीन पुट करने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर तीन साल तक पार्लियामैंट नहीं चलने दी लोगों ने। (व्यवधान)

वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शीरे के बारे में कह दिया। 50 परसैट हम लेते हैं। यू० पी० में 65 परसैन्ट लेते हैं। फ्री करने के बारे में भी सोचेंगे। आदमी को सिर–पैर की बात कहनी चाहिए। इन्होंने कह दिया कि डी० सी०, एस० पी० आज एक जिले का प्रधान है कांग्रेस का, एक जनरल सैक्रेटरी बना हुआ है। चौधरी बंसी लाल जी, मैंने भी आपके साथ

काम किया है। खुदा के वास्ते कुछ तो सच बोलो, नहीं तो यह छत गिर जाएगी और बहुत लोग दब जाएंगे। पहले लोग झूठ बोलते हुए डरते थे, आज तो आख भी नहीं दुखती। (विघ्न)

चौधरी बसी लालः दो तारीख को जींद में क्या होने जा रहा है, वह भी बता दें?

चौधरी भजन लालः मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह 'प्रथा डी० सी० को सारा काम सिपाही से लेकर एस० पी० तक, सारे काम पटवारी से लेकर डी'० सी० तक यह प्रथा आपकी डाली. हुई है, हमने उसको खत्म किया है, कम किया है। चाहे पार्टी का फंक्शन हो, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, एम० एल० ए० करेंगे, मंत्री करेंगे लेकिन डी० सी० और एस० पी० नहीं करेंगे। (विघ्न)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह तो इनकी अपनी पार्टी का जिम्मेदार आदमी कह रहा है। पंडित चिर 'जी लाल शर्मा कहते हैं कि हरियाणा में सरकारी अधिकारी ही काग्रेस पार्टी जगह लिए हुए हैं। डी० सी० प्रैजिडैण्ट हैं, पुलिस अधीक्षक वाइस प्रैजिडैण्ट हैं, तहसीलदार कोषाध्यक्ष और बी० डी० ओ० संगठन कार्यकर्ता का स्थान लिंए हुए हैं। ये इनकी पार्टी के लोग कहते हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने कहा किं मुकद्मा दर्ज हो गया, तीन आदमी गिरफ्तार हो गए.। पूरी

कार्यवाही' करने मे लगे हैं। किसानों और बी० के० यू० वालों से मिलकर उनको पूरा मुआवजा दिलाएंगे'। खाद के बारे में कह दिया कि कटटे का बजन कम है। हो सकता है कोई न कोई गड़बड़ करता हो। हम नही कहते कि सारे ईमानदार लोग हैं?। लेकिन जहां कहीं भी बाल सरकार के ध्यान में आती है, सरकार फौरन उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही करती है। यह भी कहा दिया कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत ठीक नही है, फिर कह दिया कि डी० सी० और एस० पी० की रिपोर्ट खराब कर देते हैं। आप जैसा आदमी भी यू – कहे, वैसे आजकल आपको हरिजनों से हमदर्दी हो गई है, उस वक्त जिनकी आपने रिपोर्ट लाल स्याही से खराब ही नहीं करी बल्कि सारी फाइल को पूरा हनुमान बना रखा था। उनकी सबकी फाइलें मंगाकर मैंने रिपोर्ट ठीक करके उनको प्रमोशन दी है। (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लालः ऑन ए प्यायंट आफ पसर्नल ऐक्सप्लेनेशन स्पीकर सर, अगर किसी का कसूर होगा तो मैंने उनकी ए० सी० आर० में उनके खिलाफ लिखा होगा। अच्छा काम करने वाले अक्सरों को मैंने पदम श्री दिलाए चार–चार इंक्रीमैंट दिलाई अच्छी से अच्छी ऐप्रीसिएशन की। गलत काम किया होगा तो ए० सी० आर० मै भी लिखा होगा। हम किसी की गल्त रिपोर्ट

नहीं लिखेंगे। आप ने तो बदले की भावना से रिपोर्टस लिखी हैं (शोर) मैने तो आफिसर का काम देखा है? चाहे वह किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो। (शोर)

चौधरी भजन लालः आपने इसलिये रिपोर्टस खराब लिखीं कि वह आदमी०पर न आ जाए, उसकी प्रोमोश्ल न हो आएं। आपने तो सौगंध खा रखी थी कि किसी के साथ किसी प्रकार का, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आपने इसी भेदाव कई वजह से उन लोगों के साथ ज्यादती की है। (शोर)

चौधरी भजन लालः इसी तरह से यमुना वाटर के बारे में, मैंने काफी तकशील के साथ बताया शै क्योंकि वह प्रदेश के हित में था। आपने हाईडल पावर के बारे में भो बताया है कि 173 बिजली बनती होगी। आप भी मुख्य मली रहे हो, क्या 1/3 बुनती है? मैं कहता हूं कि बहुत थोड़ी बनती है और वह भी 70 पैसे यूनिट आज घर में पड़ती है। **चौधरी बंसी लालः** कितने मेगावाट बनती है, यह तो बता दो। (शोर)

13.00 बजे

चौधरी भजन लालः यह तो भाखड़ा के पानी पर डिपैडं करता है। अगर पानी ज्यादा होगा तो बिजली ज्यादा बनेगी। वेरीऐशन होता रहता है। कभी नीचे 45 मेगावाट तक आ जाती है। केवल 20 परसैंट से ज्यादा है। (शोर)

चौधरी बंसी लालः भाखड़ा की बिजली मिलाकर आप कल जीरो–आवर में हाउस में यह बता देना कि एक साल में कितने परसैटं मेगावाट आती है?

चौधरी भजन लालः 20 परसैटं से ज्यादा कभी कभी आती है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कह दिया कि होम मिनिस्ट्री का बुरा हाल है। बुरी हालत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ में इन्होंने सुशीला हत्याकांड की बात भी यहां पर कर दी, हमें ज्यों ही पता चला तो हमने सी० बी० आई० से जांच के आदेश दे दिये लेकिन जांच में कुछ मिला नहीं। उनकी जमानत हो गई है। मैं कहता हुं कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसकी जमानत नहीं होनी चाहिये, उभको सजा अवश्य मिलनी चाहिये। (शोर) अगर बंसी लाल जी, वह जिंदा मिल गई तो फिर आपका क्या होगा? फिर क्या इस्तीफा दे दोगे आप? (शोर) इसी तरह से रणबीर सिंह सुहाग की बात भी इन्होंने कर दी। ज्यों ही हमें पता चला, हमने यह मामला सी० बी० आई० के हवाले कर दिया। जांच के आदेश कर दिये, जिसका दोष होगा, उसे अवश्य सजा मिलेगी।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह हुआ कि मुख्य मंत्री जानते हैं कि सुशीला कहां है, इसलिये वे बता दें।

चौधरी भजन लालः उसकी कोई बाडी थोड़ा मिली है। हम इस बात के लिये पीछे हैं, सी० बी० आई० भी पीछे लगी हुई है। जब पता चल जायेगा तो हम आपको बता देंगे। इसी तरह से नहरों के बारे में भी बता देता हू कि नहरों की सफाई के लिये पैसा हम ने दिया ताकि टेल तक पानी जा सके और किसानों को उससे फायदा हो सके।

इसी तरह से टूरिजम की बात है। इस समय हमारा टूरिजम सारे हिदुस्तान में वेहतरीन है, नम्बर वन पर है। जो सुझाव इनकी और से आए हैं, हम उनको चौक कर लेंगे, अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा लेकिन मेहरबानी करके बंसी लाल जी आप ठीक बोला करें, सच्ची बात किया करें, बहुत उम्र हो गई है आपकी। इस उम्र में तो आदमी को सही बोलना चाहिये क्योंकि आगे जाकर भगवान को भी जवाब देना है। वह भी आपसे हिसाब किताब मागेंगा।

श्री अध्यक्षः गन्ने का भाव जो साढ़े तीन सौ, चार सौ बताया है, उस बारे में भी बता दें।

चौधरी भजन लालः ऐसा नहीं कहा होगा स्पीकर साहब। खुले पता नही कि इन्होंने क्या कहा गन्ने के बारे में और ये कह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि इनको गन्ने का तो पता ही नही है। जिस इलाके के ये लोग रहने वाले है, ख्य इलाके में तो लोग यह कहा करते हैं कि गुड़ की भेली जो है, वह पेड को लगती है।

(हंसी) इनको क्या पता है कि गन्ना किस को कहते हैं? (शोर) एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी ने दो अप्रैल की रैली के बारे में कहा कि वह पोस्टपोन क्यों कर दी? मैं प्रैस के भाइयों को भी बताना कहता हूं और सदन को भी बताना चाहता हूं कि तीन अप्रैल को प्रधान मंत्री जी ने मेवात में माइनोरिटीज के बजट के बारे में अपना प्रोग्राम रख दिया इसलिए हमें दो अप्रैल की रैली पोस्टपोन करनी पड़ी?। बाकी अध्यक्ष महोदय, इन्होने जो प्वांयट उठाए थे उनका जवाब मैंने दे दिया है, धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश बेरी (बेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 3, 5, 9, 10, 17, 18, 22 तथा 23 के बारे में बोलूंगा क्योंकि इन पर मैंने कट मोशंज दिए हुए हैं। सब से पहले जैसे मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि उन्हेने फ्रीडम फाइटर्ज को दो परसैंट रिजर्वेशन दी हुई है। वह भी एक्स सर्विसमैन के कोटे में से काट कर दी हुई है। इस बारे में मैं क्य क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आपने इसमें लिखा है कि अगर 17 परसैटं एक्स सर्विमैन के डिपैडेंण्ट मिल गए तो फ्रीडम फाइटर्ज को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यह रिजर्वेशन भी केवल क्लास थ्री में है। जिस तरह से पंजाब और हिमाचल में यह रिजर्वेशन क्लास बन तक है उसी तरह से –हरियाणा में भी होनी चाहिए। इसमें अगर किसी अमैंडमैंट की जरूरत हो तो उस बारे में सरकार को हिदुस्तान की सरकार को लिखना चाहिए ताकि वह कांस्टीच्यूशन में अमैंडमैंट करें। अब मैं

डिमांड नं० 3 के बारे में कहना चाहता हूं। आज चौधरी भजन लारव क्लेम करते हैं कि पूरे हिदुस्तान के अन्दर सब से अच्छी कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में है। अब मैं इस बारे में क्या कह क्योकि इनको असत्य बोलते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है। पूरे हिदुस्तान में अगर कहीं पर व्यवस्था खराब है तो वह हरियाणा में है। यह सस्कार 1991 में बनी थी। उन वक्त मुख्य मंत्री जी ने बड़ी शेखी मे कहा था कि अगर हमारे राज्य में रात को गहने पहन कर औरत निकल जाए तो उसको कोई कुछ कहने वाला नही है। आज आप रात की बात छोड़ दें, कोई औरत दिन में भी चले, तो भी उसकी सुरक्षा की गारन्टी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण सुशीला कुमारी का अपहरण काड है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। क्योकि इस केस में अपराधी मुख्य मन्त्री जी से सबंधित थे, इस कारण से हरियाणा की पुलिस ने इस केस मे दिलचस्पी नही ली। उसके बाद सी० बी० आई० ने दूध का दूध और पानी का पानी निकाल कर रख दिया।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। एक ही बात को रोज रोज उठाने का क्या मतलब है। अगर ये ऐसा करेगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश बेरीः ठीक है सारी बातें आ चुकी। स्पीकर साहब, सुशीला का कसूर यह था कि उसने नकल नहीं' करने. दी। (शोर)

चौधरी भजन लालः उस केस के बारे में जांच करने के लिए हमने खुद सी० बी० आई० को लिखा था।

श्री अध्यक्षः बेरी साहब, इसके बारे में बार बार जिक्र करने की कोई आवश्यकता नही है। पहले भी इसके बारे में काफी कुछ स्कूल जा चुका है'। उसकी ईनवैस्टीगेश्न चल रही है।

श्री ओम प्रकाश बेरीः स्पीकर साहब, अकेले सुशीला कांड की ही बात नही है। सिखों हत्या कांड हुआ। उसकी जांच सी० बी० आई० ने की। उस केस में हरियाणा पुलिस नाकामयाब रही। इसी तरह से रणबीर सिंह सुहाग की हत्या की गई। (शोर)

श्री अध्यक्षः इनके बारे में आप कुछ न कहें। ये सारे मामले सबजुडिश है।

श्री ओम प्रकाश बेरीः स्पीकर साहब, मैं अब तक ला एण्ड आर्डर के बारे में कुछ नहीं बोला हूं। क्या आप मुझे बोलने के लिए टाईम नहीं देना चाहते ला एण्ड आर्डर के बारे में डिमांड है उसके चरे में मैने कट मोशन दी हुई है। आप मुझे मेरी बात कहने दें। स्पीकर अद्य जितनी भी हत्याओं के बड़े बड़े कांड हुए हैं, उनके बारे में हर दफा अग्रिब्द पार्टीज सी० बी० आई० से इंवैस्टीगेशन की मांग करती है। इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा की पुलिस पर आम आदमी का यकीन नहीं रहा है और हरियाणा की पुलिस कतई तौर पर लोगों को हास करने के लिए है। लोगों की हैल्थ करने के लिए कतई तौर पर नहीं है। पूरे

हरियाणा प्रदेश में जंगल का राज कायम हैं और प्रदेश में कानून का राज नहीं है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी है वे छोटे अधिकारियों पर दबाव डाल कर नाजायज काम करवाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार पुलिस की यूनियन क्यों नहीं बनाती। पुलिस की यूनियन बने ताकि वे अपनी बात सही तंग से सरकार तक पहुंचा सके और किसी दबाव में काम न करे। ला एण्ड आर्डर मे सुधार होना बहुत जरूरी है। यदि उनकी यूनियन होगी तो वे अपनी ग्रिवैसिज सरकार के सामने रख सकेंगे।

स्पीकर साहब, चौधरी बसी लाल जी ने टैक्सेशन के बारे मे अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य मंत्री जी आप मेरी बात को ध्यान से सुने। यह कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल औफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक मैं एक बात खास तौर से कहना चाहूंगा। जिस तरह से आपने वध है कि नार्म्ज बदल गए है। इस रिपोर्ट में एक बात यह लिखी हुई है:—

" The case was referred to Government in 1991. The reply has not been received....."

श्री अध्यक्षः यह रिपोर्ट तो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी और पी० ए० सी० के सामने जतिा है। यह रिपोर्ट हाउस मे डिस्कस नही हो सकती।

श्री ओम प्रकार बेरीः स्पीकर साहब, मैं यह डिस्कस नही कर रहा हूं। इन्होने कहा है कि नार्म्ज बदल गए हैं, अगर नार्म्ज बदल गए. हैं, उस बात को सही माना है। यह केस 1991 मैं

रैफर किया गया था, इसका अक्तूबर 1994 तक कोई जवाब नही दिया। इसका जवाब दिया जा सकता था ताकि यह चीज क्लीयर हो जाती।

इसी प्रकार से मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी ने 1995–96 के जो बजट अनुमान पेश किए हैं उसमें उन्होने कहा है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 110 प्राइमरी स्कूल, 102 मिडल स्कूल और 40 हाई स्कूल अपग्रेड करने का काम किया है। सिर्फ स्कूलों को अपग्रेड करने से शिक्षा के स्तर में सुधार होने वाला नही है। स्पीकर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं और सरकार अच्छी तज से जानती है कि जो 10 जमा 2 प्रणाली के स्कूल हैं उनमें अध्यापको के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। अंग्रेजी, हिसाब और साईस सब्जैक्टों के पद अब तक नही भरे जा सके है। स्पीकर साहब, अजमत खां जा का सवाल नम्बर 1144 जो 14–3–95 को फिक्स था उसके जवाब में एजूकेशन के बारे में बड़ी गलेरिग फिग्गर्ज दी गई हैं। मेवात के एरिया में हैडमास्टर्ज के 49 पद खाली पड़े है। अब आप ही बताएं कि शिक्षा के स्तर मैं कैसे सुधार होगा। जो सरकारी' स्कूल है उनका हाल इस कद्र है कि ये स्कूल गरीब किसानों और मजदूरो के बच्चों को रोकने के लिये बाड़े बने हुए है। मेरा ख्याल है यह गलत बात नही है। आजकल जो पडाने वाले अध्यापक है वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये पब्लिक स्कूलों मे दाखिल करवाते है। जो मिनिस्टर और एम०एल०एज० है वे भी अयने बच्चो कने

पब्लिक स्कूलो में भेज रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने वह मान लिया है कि जहां तक सरकारी, स्कूलों की शिक्षा के स्तर का ताल्लुक है वह कतई तौर पर अच्छा नहीं है। अगर शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं करेंगे तो इस प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। शिक्षा के स्तर में सुधार करना बहुत आवश्यक है। अकेले स्कूलों को अपग्रेड करने से बात नही बनेगी। मूल रूप से शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिये। जो प्राइवेट स्कूल दुकानों के रूप में चल रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिये ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो।

अब मैं डिमांड नं० 10 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे मेरा कहना यह है जो रूरल एरियाज में डिस्पेंसरीज और पी०एच० सीज० है उनमें कोई भी डाक्टर जाना पसंद नही करते। पोस्टिंग तो कर दी जाती है लेकिन वे वहां पर 15 दिन बाद एक दिन जाकर हाजिरी लगा देते हैं। उनका आम आदमियों को कोई फायदा नहीं है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जो नए नए डाक्टर्ज लगाएं उनके लिये यह कंडीशन रख दें कि पहले पांच साल उन्हें रूरल एरियाज में सर्विस करनी पड़ेगी। यदि सरकार ऐसा कर देती है तो फिर आम आदमी जो गांव में रह रहा है, उसको फायदा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 17 के बारे में कहना चाहता हूं। दक्षिण हरियाणा में स्प्रिंक्लर सैटस काफी माता में लगाये जाते हैं। उन पर वित्त मंत्री जी ने सेल्ज टैक्स में छूट दी

इसके लिये मैं वित्त मती जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो नकली खाद, पेस्टीसाइड और बीज बेचा जा रहा है यह सब अधिकारियों दारा डीलर के साथ मिलकर बेचा जा रहा है। इस बारे में मेरा सुझाव णै कि इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिये और जिस तरह से पंजाब में ए०डी० ओज० को सैम्पल लेने की पावर्ज हैं हमारे यहां पर भी ऐसा ही किया जाना चाहिये ताकि इस पर रोक लग सके और किसानों को उसका फायदा हो सके। अब तक यहां पर केवल क्वालिटी कन्ट्रोल इन्सपैक्टर को ही पावर है जो जिले में एक होता है। अतः मैं चाहूगा कि ए०डी०ओज० को सैम्पल लेने की पावर्ज दी जाएं। जो इनसैक्टीसाइडज हैं उसका हर बैच का सैम्पल लिया जाना चाहिये। इस पद्वति को अपनाया जाता है तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

अब मैं डिमांड न० 18 पर बोलना चाहता हूं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के लागू होने के बाद जो वी०एल०डी०एज० हैं उनको इलाज करने का अधिकार नही रहा। अब इस अधिनियम के जरिए क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी गई है। यह इण्डियन वैटरनरी एक्ट 10 साल से बना हुआ है। इसका जो सैक्शन 15 है उसमें क्वालिफिकेशन है। यदि इसमें अमैंडमैंट कर दी जाये और भारत सरकार को हरियाणा सरकार लिख दे तो ऐसा सम्भव हो सकता है।

वाक आउट

श्री अध्यक्षः बेरी साहब, आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, मैं' ठीक सुझाव दे रहा' हूं। कृपया मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश बेरीः यदि आप मुझे बोलने देना नही चाहते तो मैं विरोध स्वरूप वाक आउट करता हूं।

(इस समथ माननीय सदस्य श्री ओम फ्लश बेरी सदन से वा आउट कर गए।)

वर्ष 1995–96 के बजट– अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री राम भजन अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 5 पर बोलना चहता हूं। वित्त मंत्री जो ने जो फार्म न० 15 पर व्यापारियों को छूट दी, इसके लिये मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार बैरियर्ज हटा कर व्यापारियों को राहत दी है, उसी प्रकार ओक्ट्राय भी अबौलिश कर देना चाहिये। 17 स्टेटों में औक्ट्राय नहीं है। इस काम के लिये जो अधिकारी, मुनशी, चपडासी आदि लगे हुए हैं, उनका खर्चा ज्यादा होता है और इनकम कम होती है। आक्ट्राय जितना वसूल करते हैं उस को वसूल करने पर उतना ही खर्च हो. जाता है, इसलिये उसका कोई फायदा नही होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चुंगी जैसी

बीमारी को इस प्रदेश से समाप्त करे। जिस प्रकार बैरियर्ज हटाने से सरकार को लाभ हुआ है, वैसे ही चुगी हट जाने से सरकार को लाभ होगा। (विघ्न)

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (चौधरी धर्मबीर गाबा): अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास चुगी से 19 करोड़ 70 लाख रुपये की प्राप्ति होती है। माननीय स्वस्थ चुंगी हटाने की बात तो कर रहे है इसके साथ ही यह कोई आल्टर– नेटिव तो बताएं जिससे कि हम यह राशि प्राप्त कर सकें। लोग यह चाहते है कि शहरों के अन्दर उनको हर फैसिलिटी प्राप्त हो। लोगों को यह फैसिलिटीज तभी दिलवाई जा सकती है जब हमारे पास सफिशियेट पैसा हो। इसके लिये ये कोई सोर्स बताए कि पैसा कहां से इकट्ठा 'किया जा सकता है। इन्होंने गलत बात कही है कि जितनी चुंगी वसूल होंती है उतना तो उसको कलैक्ट करने पर ही लग जाता है। स्पीकर सर, ऐसी बात नही है हमारा एक्सपैडीचर चुंगी वसूल करने पर 60 प्रतिशत खर्च होता है और 40 प्रतिशत हमें बचता है।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने खुद माना है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा पैसा तो इनको चुंगी वसूल करने में ही खर्च हो जाता है। जो पैसा बचता है उस बारे में सरकार पूरी तरह से विचार करे कि कैसे इस पैसे को जुटाया जा सकता है। सरकार के लिये इतना पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे पहले बैरियर्ज पर टैक्स के लिये रुकना

पड़ता था चुंगी के लिये गाड़ियां, ट्रैक्टर और ट्रकों आदि को रोकते हैं उससे समय भी वैस्ट होता है और उसके लिये सरकार कोभी खर्च करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि मिलावट की टौस्टिग के लिये डिस्ट्रिक्ट लैवल पर लैबोरेटरीज होनी चाहियें ताकि वहां पर व्यापारी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर माल बेचने से पहले उसको टैस्ट करवा लें और क्वालिटी के बारें में सुनिश्चित कर लें। मिलावट के केस न्ये चालान हो कर क्या का भी प्राबधान है इसलिये डिस्ट्रिक्ट लैवल पर लेबोरेटरीज का होना बहुत ही जरूरी है। व्यापारी तो मैन्यूफैक्चरर मे माल खरीदते है उनको यह पता नही होता कि उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नही है। इमके साथ ही एक और प्रावधान भी होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि छोटे व्यापारियो को सुविधाएं दे रहे है। मिलावट को रोकने के लिये कानून बना हुआ है जिसके अन्दर इन्स्पैक्टर्ज नमूने लेने के लिये जाते है। आजकल इसमें काफी करप्शन हो रही है। इन्स्पैक्टर दुकानों पर जा कर उनके साथ सोदेबाजी करते है कि या तो इतने रुपये दो नहीं तो सैम्पल भरेगे। मजबूर हो कर दुकानदारों को उनकी बात माननी पड़ता है। इसी तरह से आक्ट्राय में भी करप्शन है। ट्रकों के ट्रक निकल जाते है। 200/— रुपये दे कर वह बिना चुंगी के अपना माल निकाल ले जाते है। लेकिन जौ छोटा दुकानदार है या छोटा जमीदार है जो 5 किलों घी लाता है या कोई और छोटी चीज लाता है उसको टैक्स देना पडता है और बड़े लोग उसकी चोरी कर लेते हैं

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि 50 प्रतिशत तो इस पर सरकार को वैसे ही खर्च करना पडता बाकी का जो पैसा है वह किन्ही दूसरे साधनों से जुटाया जा सकता है इसके लिये सोचा जा सकता है किसी और मद में इस को बढ़ा कर पूरा किया जा सकता है। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार स्ट्रीट लाईट की बिजली का खर्च लोगों पर 2 पैसे प्रति यूनिट लगा कर बिल भरा जाता है उसी प्रकार चुंगी के बारे में भी कर सकते है या फिर इस बारे में कोई और जरिया भी ढूढा जा सकता है और यह पैसा व्यापारियों से तथा दूसरे लोगों से इकट्ठा किया जा सकता है।

चौधरी धर्मबीर गाबाः अध्यक्ष महोदय, यह जो आक्ट्राय के बारे में इन्होंने दोबारा बात उठाई है। मैं आदरणीय सदस्य के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि आज हम ने जो म्युनिसिपल कमेटीज के इलैक्शन करवाए हैं, यह कांग्रेस पार्टी ने ही करवाए हैं। उसके बावजूद हमने यह फैसला किया है कि डनका प्राईवेटाईजेशन किया जाए। जो भी म्युनिसिपल कमेटी हमें अपना रैजोल्यूशन भेजेगी कि हम कंट्रैक्ट बेसिज पर देना चाहते है तो हम आक्ट्राय को कंट्रैक्ट बेसिज पर देंगे। इससे एक फायदा यह जरूर होगा कि जो हमारी इन्कम है वह तीन गुणा होगा। इस प्रकार हम यह करने जा रहे है जिससे किमी को कोई दिक्कत न हो।

श्री राम भजन अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, आक्ट्राय को कंट्रैक्ट बेसिज पर सरकर देगी उससे आमदनी जरूर वढेगी क्योंकि जो सरकार के अधिकारी है वे चोरिया नही रोक पाने है लेकिन कंट्रैक्टर से अपने स्वार्थ के लिये रोक देगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा वाटर रेट के बारे में सरकार को एक सुझाव है। सरकार ने इस साल में रेट तीन दफा बढ़ा दिए हैं लेकिन पानी नही है। एक रेट तो ऐसा है कि एक टूटी पर 24 रुपए लगेंगे और एक से अधिक पर 40 रुपए के करीब लगेगे। वैसे तो टूटियो में पानी आता ही नही है, अगर आता है तो एक में भी उतना ही आता है और तीन में भी उतना ही आता है। एक से अधिक टूटियों में इन्होंने ज्यादा टैक्स का प्रावधान रखा है, यह कोई न्याय संगत बात नहीं है। अगर प्रैशर ज्यादा होता है तो पानी आ जाता है। आज तो स्टेट में नल ही बहुत ज्यादा लग गए हैं। 200 कनैक्शनों के लिये 3 इंच लाईन बिछाई गई थी और आज 1000 के करीब कनैक्शन दे दिए गए हैं जिस कारण से पानी का प्रैशर बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिये मैं बहन जी से कहूंगा कि इस टैक्स वाली बात पर ये पुनः विचार करें। आज एक आदमी मकान का महीने का किराया तो 50 रुपये देता है और पानी का बिल 100 रुपए महीना आ जाएगा। इसीलिये आप सस्ते पानी का प्रावधान करें। आदमी शराब, तथा दूसरी चीजें तो छोड़ सकता है लेकिन पानी नही छोड़ सकता है। इसलिये आप पानी को मंहगा न करें। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो छतर सिंह चौहान (मुंढालखुर्द): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं डिमांड नं० 6 पर बोलूंगा जो वित्त मंत्री जी के विभाग से सम्बन्धित है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनको दों–तीन सुझाव देना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी जब आप जवाब दें तो उसमें यह बता देना कि हरियाणा प्रदेश पर हरियाणा के बोर्ड और कारपोरेशंज का 1986–87 में, 1991– 92 में और 1994–95 में कितना कर्जा था। (विघ्न) दूसरी बात यह है कि ये कोई भी डिपार्टमैंट ले लें, इनका 80 प्रतिशत आफ–दि–बजट साल के आखिर में खर्च होता है। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि सारे साल का जितना बजट है उसको क्वार्टर में बांटा जाए। यह बात जो साल के आखिर में पैसा खर्च करने वाली बात है, यह हमें एस्टीमेट कमेटी में डिपार्टमैंट वालों ने बताई थी। क्या जरूरत है कि 31 मार्च को ट्रेजरी और बैक 12 बजे तक खुलें। 80 प्रतिशत बिल आखिरी तीन दिनों में ही बन जाते हैं। यह पब्लिक की मनी है इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। कमेटी मीटिंग में डिपार्टमैंट ने बताया कि बजट तो अलाट हो जाता है लेकिन हमें फाईनेंशियल सैक्शन नहीं मिलती है। इसलिये वित्त मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें। इसके अलावा मैं तीसरी बात वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। इन्होने खुद एक महाजन परिवार में जन्म लिया है इसलिये महाजन तो उसे कहते हैं जो किफायतदार हो। इनको तो गवर्नमैंट की कुछ इकोनोमी को ठीक करना चाहिये। यह ठीक है कि ये मन्त्रियों को कम नहीं कर सकते।

स्पीकर सर मैं कुछ सुझाव इनको देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से हर डिपार्टमैंट में चाहे कोई जीप हो या कोई गाड़ी हो, उनमें डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी और सब डिबिजन लैवल पर पैट्रोल या डीजल बिना बात के खर्च किया जाता है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः वित्त मंत्री जी आप जवाब देने के लिये कितना समय लेंगे?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गप्ता): सर, आप मुझे जितना भी समय देंगे मैं उतने समय में ही बोल लूंगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1995– 96 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर सर, इनको एक बिल बनाना चाहिये कि जिस किसी ओफिसर का भी गाड़ी चाहिये, वह अपनी रिक्वीजिशन भेजे क्योकि आज देखा जाता है कि मूली खरीदने के लिये भी अफसरों की गाड़ी जा रही है, बच्चे स्कूल भेजने के लिये भी गाड़ी जा रही है, रिश्तेदार को छोड़ने के लिये भी गाड़ी जा रही है इसलिये हम तो यह सोचते हैं कि यह सब पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि नहीं होना

चाहिये। वित्त मन्त्री जी, आपने तो एक ऐसी कम्युनिटी में जन्म ले रखा है जिसमें economy must be in your blood,

स्पीकर सर, अब मैं डिमांड नं० आठ पर जो कि सड्कों से संबंध रखती है और जिसके अमर सिह जी मंत्री हैं के बारे में बोलना चाहूंगा। सर, आपने भी इस हाउस को दस दिन से देखा है कि इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के मैम्बर्ज की तरफ से सिर्फ दो ही बातों पर जोर दिया जा रहा है। एक तो यह कि नहर टूटी पड़ी हैं और दूसरे सड़कें टूटी पड़ी हैं। (विघ्न)सर, मैं इनको सुझाव दे रहा हूं। एक बात तो आप भी मानेंगे कि आज सारे प्रदेश के लोग इस बात से चिंतित हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं और उनकी चिंता ठीक भी है। इसलिये मैं कहूंगा कि इनको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिये ताकि सड्कों की मरम्मत हो सके। एक बार मैं और लाला रामभजन अग्रवाल चौधरी अमर सिंह जी से मिलने गए तो इन्होंने हमसे कहा था कि मैं सड्कों को नया कोट पहना द्गा। सर, लेकिन अब(विघ्न) तो नया कोट पहन लिया किन्तु सड्कों की कोई मरम्मत नहीं

स्पीकर सर, अब मैं डिमांड नं०9 जो कि ऐजूकेशन के संबंध रखती है, पर बोलना चाहूंगा। आज सरकार नकल रोकने के लिये मानसिक रूप से प्रयास कर रही है जिसमें इनको सफलता भी मिली है जिसके लिये मैं इनको बधाई भी देना चाहूंगा। लेकिन नकल क्यों होती है इसकी गहराई में ये नही गए त् नकल इसलिये होता है क्योकि स्कूलों मैं अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाते

हैं इनका जो स्टाफ है जैसे डी० पी०आई० या दूसरा चौकिंग स्टाफ है वह कभी भी स्कूलों मे इंसपैक्ट करने नहीं जाता। मैली जी भी कभी चौक करने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको समय ही नहीं है। स्पीकर सर, आप तो एक महान शिक्षाविद रहे हैं, आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश और प्रदेश में आज दो तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है। एक तो पब्लिक स्कूल की प्रणाली है जिसमें मांगे राम जैसों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी प्रणाली है गवर्नमैंट स्कूल। एक गवर्नमैंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा पब्लिक स्कूल वाले पढ़े हुए बच्चे को कम्पीट नहीं कर सकता। इसलिये सरकार को इस प्रकार की दोहरी प्रणालियों को समाप्त करना चाहिये और अपने शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई की ठीक व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः चौहान साहब, जब तक प्राईवेट प्रोपर्टी रहेगी, तब तक ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।

प्रो० छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर सर, अब मैं डिमांड नं० 22 पर जो कि को– आप्रेटिव डिपार्टमैंट से संबंधित है, पर बोलना चाहूंगा। आज हरियाणा के लोग इस डिपार्टमैंट को डिपार्टमैंट आफ करप्शन भी कहते हैं क्योंकि इस डिपार्टमैंट में आज करप्शन है। (विघ्न)

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, परिचन्द, अमर सिंह जी और धर्मपाल, ये सभी पहले एक साथ थे, इनकी आपस में घनी मोहब्बत थी। इसलिये वह इन को इंट्रप्ट कर रहे हैं। (विघ्न)

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि वे या तो सदन में यह बात साबित करें कि करप्शन कहां है अन्यथा यहां इस तरह की बात न करें। (विघ्न)

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले करप्शन वाली बात बता देता हूं। कैथल के ए०आर० आफिस में जगदीश नारायण नाम का एक क्लर्क 13–2– 1976 से 9–8–1989 तक रहा। इन तेरह सालों में वह एक सीट पर ही रहा, उसके पते आठ असिसटैट रजिस्ट्रार आए। इस आदमी ने सबसे पहले 9 लाख 79 हजार का गबन किया, उसके पश्चात् वह हर साल इसी तरह करता रहा। यह ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है जिसके पेज 52 से 54 तक सारा विवरण दिया है। इसने टोटल 19 लाख 58 हजार 405 रुपये सत्तर पैसे का गबन किया और इसके खिलाफ कार्यवाही यह की कि इसको वहीं रखा। न ए०आर० के खिलाफ कार्यवाही की, न किसी और के खिलाफ कार्यवाही की। (विघ्न)

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस विधान सभा में बैठते बैठते तीन वर्ष के लगभग हो

गए। क्या इनका इतना भी कर्त्तव्य नही बनता कि इनकी नौलेज मैं भ्रष्ट व्यक्ति आ गया तो चिट्ठी ही लिख देते।

प्रो० छतर सिंह चौहानः बहिन जी, ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है।

श्री अध्यक्षः चौहान साहब, आपको पहले भी बताया है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है, यह हाउस में डिसकस नही होती।

प्रो० छतर सिंह चौहानः ठीक है जी मैं वह डिसकस नही करता, दूसरी बातों पर आ जाता हूं। मैं डिमांड नंबर 15 पर बोलना चाहता हुं। आज जिस प्रकार से टूटी सड्कों को लेकर सारे हरियाणा की जनता और विधान सभा के सदस्य चिंतित हैं, इसी प्रकार सारी नहरें मिट्टी से भरी पड़ी हैं। दक्षिणी हरियाणा का पानी नेहरा साहब हिसार और सिरसा ले गए। एस०वाई०एल० बनाने का नाम नहीं ले रहे। अध्यक्ष महोदय, ये एस०वाई०एल० नहीं बना सकते क्योकि इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। यमुना जल समझौता इसलिये करना पड़ा क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी थी। ये हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहरों की सफाई के लिये सारी जनता चितित है। कल चौधरी सूरज मल भी इसी बारे बोल रहे थे। चौधरी सूरज मल ने किसान के घर में जन्म लिया है। वैसे किसान के यहां तो नेहरा साहब ने भी जन्म लिया है लेकिन उन्हें मन्दी पद ने सारा कुछ भुला दिया। मेरी

आपसे प्रार्थना है कि हरियाणा की सारी नहरें सिल्ट से भरी पड़ा हैं उनकी सफाई की वारफुटिग पर जरूरत है।

स्पीकर साहब, मुख्यमन्त्री महोदय ने चौधरी बंसीलाल जी के बारे में यह कह दिया कि वे हरिजनों के बहुत खिलाफ थे, उन्होंने जगजीवन राम जी का भी नाम ले दिया कि चौधरी बंसी लाल जी ने इनके बारे में भी बहुत कुछ कहा। स्पीकर साहब, शायद चौधरी भजन लाल जी की यादाश्त कमजोर है। वे तो खुद बड़े लीडर्ज के बारे में कहते रहे हैं, नाम दूसरों का लेते हैं। उनको याद होगा 2 अक्तूबर, 1979 को मुख्यमन्त्री भिवानी मे किसी हस्पताल का उद्घाटन करने के लिये गए थे और उस वक्त इन्होंने कहा था कि यह कांग्रेस का चुनाव निशान तो खूनी पंजा है और श्रीमती इन्दिरा गांधी जो उस वक्त देश की प्रधानमन्त्री थी, के बारे में भी यह कहा कि यह देश की सब से ज्यादा भ्रष्ट औरत है, और उसके तीन दिनों के बाद ही ये कांग्रेस में आ गये'। वह आदमी चौधरी बंसी लाल जी जैसे कर्मठ व्यक्ति के बारे गल्त कहे तो यह कितनी शर्म की बात है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि? कोई आदमी किसी के दामन पर दाग लगाने से पहले अपना दामन तो देख ले। धन्यवाद।

श्री सतबीर सिंह कादियान (नौलथा): स्पीकर सर मैं एक दो सुझाव ही देना चाहता हूं। इस विधान सभा की अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं उनकी मीटिंग भी होती रहती है और उनकी रिपोर्टस भी समय समय पर आती रहती हैं। कमेटी उन रिपोर्टस

की स्क्टूनी करती है। कमेटीज के जो स्कोप एंड फंकशंज हैं को आप सब लोग जानते ही हैं। कमेटीज की रिकमैडेशंज/औब्जर्वेशज को इम्पलीमैंट करने के लिये आफिसर्ज की ड्यूटी लगायी जाती है और उनको यह कहा जाता है कि आप इनके बारे में 5–6 महीनों में एक्शन लेकर हमें सूचित करें। एक्शन इनीशीयेट करें। परन्तु कमेटीज उनकी रिपोर्टस के लिये इन्तजार करती रहती है ताकि रिपोर्टस को फाइनल किया जा सके। लेकिन सरकार के वे बेलगाम ओफिसर अपनी रिपोर्ट' सही टाईम पर नही देते जोकि इस प्रदेश के हित में नहीं है। अगर उनकी रिपोर्ट समय पर न आये तो फिर इन विधान सभा की कमेटियों का औचित्य ही क्या रह क्या। इन सब बातो को हम सभी मैम्बर्ज रियालाडज करते हैं चाहें कोई रुलिग पार्टी से सम्बन्धित हो, चाहे कोई किसी दूसरी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि मुख्य मती महोदया या चीफ सैक्रेटरी के लैवल पर इस मामले को टेक अप किया जाना चाहिये और सभी बड़े आफिसर्ज को इस तरह की हिदायतें जारी होनी चाहिये ताकि वे समय पर कमेटियों के पास अपनी रिपोर्टस भेजें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जहां दूसरे प्रदेशो में हमने देखा है कि अपोजीशन के लीडर के लिये, कमेटियों के चेयरमैन के लिये बैठने के लिये अलग से कमरा होता है, उसी तरह से यहां पर भी सरकार को विधानसभा के अन्दर इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि मैम्बर्ज, चेयरमैन आपस मे बैठकर

आपसी विचार विमर्श कर सके और साथ में उनके काम काज के लिये स्टाफ का प्रोवीजन भी होना चाहिये, टेलीफन की व्यवस्था भी होनी चाहिये ताकि वे अपने सरकारी काम काज को ऐफीशीऐन्टली निपटा सकें, इस ओर सरकार ध्यान दे।

इससे आगे मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे मे भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों 26 जनवरी को जो वाक्या करनाल रैस्ट हाउस में हुआ उस बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि यह तय है कि उस रैस्ट हाउस में चीफ मिनिस्टर व राज्यपाल महोदय की गाड़ी ही प्रवेश कर सकती है, दूसरी किसी की नही लेकिन हमारे मुख्य सचिव महोदय उस दिन वहां पर गये, उनकी गाडी को एक एस० पी० रैक के आदमी ने दरवाजे पर रोका तो उन्होंने आगे से उस अधिकारी को स्टुपिड फेलो कहा। उनको ऐसा नही करना चाहिये था। वे कोई चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी से०पर नही है। हम मैम्बर्ज से भी उनका रुतबा०ंचा नशे है। ब्यूरोक्रेसी में इतना गरूर नही होना चाहिये। वे इतने बेलगाम क्यों हो रहे है। उनका यह कहना उनके लिये ठीक बात नही थी। एक सीनियर आई०पी०एस० अधिकारी को उन्होने इस तरह टूटि किया, यह उनके लिये शोभा नहीं देता था। इससे यह लगता है जैसे पंडित चिरंजी लाल शर्मा ने कहा था और शायद इसी बात से एक्सपोज हो कर कहा था कि डी० सी० इनके प्रधान हैं.....

श्री अध्यक्षः इस बात का इससे कोई ताल्लुक नही है, आप अपनी बात कहें।

श्री सतबीर सिंह कादियानः ठीक है जी, दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जितने छोटे छोटे अफसर हैं उनके पास भी गाड़ियां हैं और वे सारी पैट्रोल की हैं। मेरा सुझाव है कि डीजल की कारें खरीदी जाएं। मेरे पास भी डीजल की कार है। उसमें कोई अन्तर नहीं है। अन्तर है तो पैट्रोल और डीजल की कीमत में। पैट्रोल बहुत मंहगा है और डीजल सस्ता है। इसके अलावा अफसरों को गाड़ी खरीदने के लिये लोन भी दिया जाता है। अगर उन्होंने कही टूर पर जाना है तो वे अपनी गाड़ी ले कर जाएं और उसका उनको टी०ए० डी०ए० दिया जाए। अब उनको ड्राइवर भी देना पड़ता है। आप देखते है कि आम को सारी कारें सरकार की सब्जी मंडी में या शौपिंग सैटर्ज में मिलेगी।

श्री अध्यक्षः ये तो आपके टाइम में भी जाती होंगी।

श्री सतबीर सिंह कादियानः सर, मैं तो हमेशा एम०एल०ए० ही रहा हूं, मझे ऐसा मौका नही मिला। वैसे मैं ऐंमें करता भी नही हूं। मैं इफ्को का चेयरमैन था ते बस में आया करता था, कार मैं नहीं आया करता था। जब कार में कभी आता था तो उसका खर्चा इफ्को वालों को देना पड़ता था। तो ऐसे कदम उठा कर उन अक्सरों के खर्च कम किए जा सकते हैं। लेकिन वित्त मन्त्री जी ने ऐसा कोई कदम नही उठाया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये पास बुक बनाने की बात यहां हुई थी और उस बारे में कानून भी पास हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूं कि पास बुकस बनाने के लिये सरकार कब

ध्यान देगी। मैं चाहता हूं कि इसको टाइम बाउंड बना कर तीन महीने में किसानों को पास बुर्के मिलनी चाहियें। अब मैं कोआप्रेशन के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे शूगर मिल एक जिले में दो दो हैं। जैसे रोहतक में है तो उसका चेयरमैन डी०सी० होता है। डी०सी० के पास पहले इतने काम होते हैं कि वह इसके काम को अच्छी तरह से देख नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी जो बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज है उनमें से किसी को इसका चेयरमैन लगाया जाए। इसका चेयरमैन कोई व्यूरोक्टे नही होना चाहिये। जितनी भी सहकारी संस्थाएं होती हैं उनमें शेयर होते हैं। चाहे वह मिनि बैकस हो, चाहे कोआप्रेटिव लैड डिवैल्पमैट बैक हो, कोआप्रेटिव बैक हो या कोआप्रेटिव सो– साइटीज हो। इनके लिये कानून की मान्यता यह है कि हर साल इनकी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जानी चाहिये। परन्तु बहिन जी आपके नेतृत्व में इनकी मीटिंग कभी भी नहीं हुई। यदि इनकी मींटिंग नहीं होगी तो उन शेयर होल्डर्ज का क्या होगा जिनके शेयर हरियाणा सरकार के पास पड़े हैं। जब आप मीटिंग ही नही बुलाएंगे तो इसका क्या औचित्य रह मया इस सहकारिता क्षेत्र में। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप एक बिल ले कर आएं जो जनता के चुने हुए प्रतनिधि है उन्हीं को कानूनी अधिकार होंगे। इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जहां देश मे हरित क्रांति आई है वहां दूध की क्रान्ति भी अनि। चाहिये। इसलिये पशु पालन विभाग के तहत ज्यादा से ज्यादा पशु हस्पताल खोले जाने चाहियें ताकि

पशु धन के लिये' उचित व्यवस्था हो सके। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा साइटिस्टस होने चाहिएं। अब मिल्क फार्म के आफिशियल्ज ही दवाइयां प्रैसका इब कर सकते हैं जबकि इनके अपने वी०एल०डी०ए० हैं। उनको दवाइयां प्रैसक्राइब करने का अख्तयार नही है

पशु पालन राज्य मन्त्री (राव धर्म पाल): स्पीकर साहब, जहां तक दूध का सवाल है। हरियाणा प्रदेश में फी आदमी 602 ग्राम दूध हर रोज मलता है। वह बनावटी दूध नही है, असली दूध है। हरियाणा प्रांत में 3715 लाख टन दूध हर रोज उपलब्ध होता है और मेरे मंत्री बनने के बाद दो लाख टन की पैदावार बढ़ी है। सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा दूध पंजाब में होता है और दूसरे नम्बर पर हरियाणा प्रदेश में होता है।

श्री सतबीर सिंह कादियानः मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे मंत्री है। पशु पालन विभाग को प्रोत्साहन देना चाहिये। जो वी०एल०डी०ए० हैं उनको प्रैस्क्रिप्शन के अधिकार दिए जाएं।

इसके अलावा अब मैं परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। जिन प्राइवेट आप्रेटर्ज को सरकार ने जिन जिन सड्कों के रूट परमिट दिए हैं उन सड्कों पर उनकी बसें चल नही सकती। इसके अलावा आपने उन पर जो 10 किलोमीटर तक रूट परमिट देने की शर्त लगाई है उसको हटा लेना चाहिये। जैसे

आपने पानीपत से गोहाना, पानीपत से सफीदों के रूट परमिट दिए हुए है वे. सवारियों को ला करके नैशनल हाई वे पर उतार देते हैं उन सवारियों को रोडवेज की बसें बैठाती नही हैं। वहां पर न कोई बस अड्डा है और न कोई अड्डा इंचार्ज है। फिर लोग थी व्हीलर या फोर व्हीलर किराए पर करके जाते है तो सरकार उन पर अंकुश लगाती है और उनके चालान किए जाते हैं। सरकार इस व्यवस्था में सुधार करे और ज्यादा से ज्यादा बस अड्डे बनवाए।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमाड न० 15 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि इरीगेशन से संबंधित है। सरकार दारा प्रस्तुत किया हुआ बजट और गवर्नर ऐड्रेस दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण डाकुमैंट्स है। गवर्नर ऐड्रेस में तो सरकार ने एस०वाई० एल० नहर के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है लेकिन बजट में एक सैटेंस में यह कहा गया है कि एस०वाई०एल० नहर बनाने के लिये पंजाब से अनुरोध कर रहे हैं। हमारे मुख्य मती जी कई बार कह चुके हैं कि हमारी इस बारे में पूरी कोशिश चल रही है। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिये एस०वाई०एल० नहर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई दूसरा नही है। किसी सरकार के लिये चार साल का समय कोई कम समय नहीं है। यह सरकार आज तक यह नहीं बता सकी कि एस०वाई०एल० नहर पर कितना काम किया है। इन्होंने उस नहर पर कुछ काम किया हो तो ये बताए। इन्होने वहां पर कुछ किया ही नही है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह

जी जो पहले इनकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने गांव गाँव मे यह कहा है कि एस०वाई० एल० नहर का कोई भी काम नही किया गया है। दो दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने हमारे बारे में यह कहा था कि आप इस एस०वाई०एल० नहर के मुद्दे को उलझा रहे हैं। एक ही छत के नीचे हमारा और पंजाब का अधिवेशन चल रहा है, वे भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं। हम इनकी बात सुन कर चुप हो गए। लेकिन स्पीकर साहब, उस नहर को कम्पलीट करवाने की इनकी नीयत नहीं है। इन्होंने उसके बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया। यह इनकी बड़ी भारी विफलता है। इसके अलावा मैं डिमांड नम्बर, 1 पर बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः डिमांड नम्बर 1 विधान सभा की है उसके बारे में यहां पर डिस्कशन नही हो सकती।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब, मैं तो सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः डिमांड नम्बर 1 पर डिस्कशन नहीं की जा सकती। आप और बात कर लें।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर साहब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। शिक्षा मन्त्री मुलाना साहब ने नकल को रोकने का प्रयास किया उनको इस बारे में कितनी सफलता मिली कितनी नहीं मिली इस बारे में वे खुद जाने। स्पीकर साहब शिक्षा एक ऐसा अदायरा है जो पीढ़ियों का निर्माण करता है। प्रौढ़ शिक्षा के

जो उम्मीदवार हैं उनको आप जहां पर वैकेंसीज है उनको उन बैकेंसीज पर एडजैस्ट करने के लिये विचार करें। जो संस्कृत के अध्यापक हैं आप उनको भी प्रोत्साहन दें, उनको भी लगाएं और उनको पूरे वेतनमान दें। सरकार ने जिस प्रकार कालेज अध्यापकों को यानि अनुदान प्राप्त कालेजिज के अध्यापकों को जो वेतनमान दिए हैं, उसी प्रकार से स्कूल जो अनुदान प्राप्त हैं, उनके कर्मचारियों को पूरा वेतनमान दे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं भवन तथा सड्कों की डिमांड के बारे में बोलना चाहता हूं। चौधरी अमर सिंह जी वहां पर ग्रिवेंसिज कमेटी में जाते हैं। इनके सामने कई बार सवाल उठाया है और ये मानते भी हैं किं जो नेशनल हाई वे जयपुर से दिल्ली का है, उस पर ट्रैफिक का लोड है। इसको चौड़ा करके फोर लेन बनाया जाना चाहिए।

अब मैं जन–स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। पीने के पानी के जो वाटर वर्कस बने हुए हैं, उनमें बिजली के कनैक्शन्ज नहीं है, कनैक्शन्ज दिए जाने चाहिएं। आगे आने वाली गर्मी की कल्पना करें तो क्या हालत उन लोगों की होगी, जरा सोचिए। मैंने एक सवाल के दौरान भी कहा था कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी तीन जगहों से टूटी हुई है। इस पर 45 गांव पड़ते हैं। वहां पर 8– 10 गांवों में डेढ़ साल से पानी नहीं जा रहा। मेरी प्रार्थना है कि प्राथमिकता के आधार पर उनको पानी दें।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहते हुए बहन जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारे हस्पताल हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है।

हमारा हरियाणा छने था है। चल करतार देवी जी से मेरा अनुरोध है है कि एक सप्ताह में सारे डिस्ट्रिक्ट हैड क्र्वाटर पर जाया जा सकता है और अच्छी प्रकार से चौक किया जा सकता है। हैल्थ के 'बारे में चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं जो हमारा मैडिकल कालेज है, उसकी भी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तीन मंजिला एक इमारत जिस पर 1 करोड़ रुपये लागत आई थी। उद्घाटन से पहले ही उसमें क्रैक आ गया। वहां वार्डज में बहुत अधिक अंधेरा रहता है। इतना अधिक अंधेरा रहता है कि कोई टी० बी० का मरीज हो तो वह अंधेरे का खौफ देखकर वैसे ही मर जाए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और सब–डिवीजन लैवल पर जितने भी हास्पिटल हैं, उन सब में एमरजेसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडैटं होता है तो वहां पर इतना तो प्रबन्ध हो कि उस को औपचारिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इन हस्पतालों की न तो लैटरिंग्ज ठीक मिलेगी, न चदरे ठीक मिलेंगी और न ही बैड ठीक मिलेंगे। इसलिये इन सब बातों पर मन्त्री महोदय पूरी तरह से ध्यान दें। इसके साथ साथ एक बात कह कर मैं बैठता हूं कि मेरे हल्के में पीने के पानी

की 9 योजनाएं अधूरी पड़ा हैं, कृपया इनका प्राथमिकता के आधार पर जन स्वास्थ्य मन्त्री प्रा करवाएं। धन्यवाद।

14.00 बजे

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, कल आपकी इजाजत से मैंने इन द्वारा उठाई गई सारी बातों का जवाब दे दिया था। आपने मेरे को उस समय बोलने का समय दिया जब विरोधी पक्ष और ट्रेजरी बैचिज की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं रहा था। जो जवाब मैंने दिया था उससे सारे विपक्ष के भाई भी प्रसन्न हो कर गए थे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट तक और बढ़ा लिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी कल नहीं थे, कोई जरूरी काम होगा इसलिये कल

हाउस में नहीं आए, कोई रैली वगैरा करने गए होंगे। चौधरी बंसी लाल जी जब भी बोलते हैं वे मुख्य मन्त्री जी से जवाब मांगते हैं और उनकी बातों का जवाब माननीय मुख्य मक्की जी 2–3 बार दे भी चुके हैं और शायद इनकी सेहत का राज भी यही है कि जब तक चौधरी भजन लाल जी से दो–चार कड़कदार बातें न सुन लें इनको चौन नहीं पड़ता। शायद इससे इनका खून बढ़ता है (हंसी) उनकी बातों से शायद इनकी तबीयत फडक उठती है। अध्यक्ष– महोदय, इनकी बातों का जवाब तो वैसे मुख्य मन्द्री जी ने भी दे दिया है लेकिन मैं इनको फिर से एक बात बता देना चाहता हूं ये नोट कर लें। पिछले 4 साल के दौरान इस सरकार ने जो लोन लिया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है। 1991– 92 में 23.25 करोड़ रुपये का लोन लिया, 1992– 93 में 44.95 करोड़ रुपये, 1993– 94 में 55.79 करोड़ रुपये 1994– 95 मे 54.31 करोड़ रुपये का लोन लिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इनको एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोन 'यू ही नहीं लेते बल्कि लोन के साथ हमें कुछ राशि अनुदान के रूप में भी मिलती है। हम लोन वेस्ट करने के लिये नहीं लेते हैं। जब कोई स्कीम बना कर कोई वायबल प्रोजैक्ट वर्ल्ड बैक को भेजते हैं और वे उस प्रोजैक्ट को जस्टिफाईड समझते हैं तभी लोन देने के लिये वे सहमत होते हैं। जब उन को यह पूरा यकीन होता है कि स्कीम वायबल है और लोगों के हित में है केवल तनख्वाह या दूसरे एक्सपैंडिचर के लिये नहीं है बल्कि सालों साल उससे लोगों का भला होगा, जनता का हित होगा तभी प्रोजैक्ट वे सैक्शन करते हैं लोन कें साथ सबसिडी

भी होती है। इस लोन में 70 प्रतिशत हमें वापिस करना है और बाकी 30 प्रतिशत की ग्रांट मिलती है। अध्यक्ष महोदय 1991– 92 के लिये 23.76 करोड़ का जो लोन था उसमें 10.18 करोड़ रुपये की ग्रान्ट मिली है। इसकी अलग अलग स्कीम्ज हैं। कैटेगरीवाईज लोन मिलता है। जिन स्कीमों पर लोन मिला है वह भी मैं इनको बता देता हूं। पहली हरियाणा इरिगेशन सैकण्ड प्रोजैक्ट है, दूसरी नैशनल एग्रीकल्चर एक्सटैंशन प्रोजैक्ट है, तीसरी इन्टैग्रेटिड वाटर शैड कण्डी ऐरिया प्रोजैक्ट है, चौथी कोमन लैण्ड इन अरावली हिल्स, पांचवी नेशनल वाटर मैनेजमैंट प्रोजैक्ट, छठी हरियाणा टैक्नीकल एजुकेशन प्रोजैक्ट, सातवी ई० ई० सी० तथा 8वीं हरियाणा हयूमन इम्प्रूवमेंट प्रोजैक्ट, इन आठ प्रोजेक्टस के तहत हमने लोन लिया है जिसके फिगर्ज मैंने पहले बता दिये हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इमसे एक मात जानना चाहता हूं कि जो वाटर शैड मैनेजमेट प्रोग्राम हैं, उसको कौन सा डिपाटैमैंट करेगा? (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ताः इस स्कीम इरिगेशन, एग्रीकल्चर और फोरेस्ट यानि इसमें 2– 3 डिपार्टमैंट इन्वाल्वड हैं।

श्री अध्यक्षः क्या शिवालिक बोर्ड भी इसमें शामिल है?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, शिवालिक बोर्ड वर्ल्ड बैक के अधीन नहीं है। (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको फिर एक मिनट के लिये इन्ट्रप्ट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, घग्गर टांगरी मारकण्डा पर बांध बनाने के लिये जो प्रोग्राम था, उसके बारे एक्सपर्ट इन्जीनियर्ज ने यह कह दिया था कि इसमें सिल्ट इतनी ज्यादा आएगी कि अगले साल दो साल में वह बराबर हो जाएगी इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होगा और यह बायेवल नहीं है। इस प्रोजैक्ट से अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों के एरियाज को बैनिफिट हो सकता है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले तो यह प्रोजैक्ट वायेबल नहीं था, क्या कण्डी ऐरिया वाटर शैड प्रोग्राम के तहत यह बामेबल हो जाएगा? मैं मुख्य मन्त्री जी से भी कहना चाहूंगा कि वाटर शैड प्रोग्राम पूरी होने पर क्या ऐसी टैक्नोलोजी सर्वे करवाई जा सकती है?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है हरियाणा इतने महंगे लोन ले रहा हे। (विघ्न)

Ch. Birender Singh : Speaker, Sir do you think that my question is irrelevant as the Minister is not replying to my question. This is a vital information and the Minister should come out with this information as to how much loan has been taken from the World Bank ?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के अपने रिसोर्सिज हैं, और हरियाणा का लोन एक दिन भी लेट नही हुआ है, हमने पूरा इन्ट्रस्ट दिया है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर

देखें तो हमारी बाकियों से बहुत ही बेहतर पोजीशन है। हम किसी प्रकार का ऐसा लोन नहीं लेते हैं जिसे हरियाणा सरकार नहीं दे सके। यह तो वायेबल प्रैक्टीस है और वर्ल्ड बैक ऐसे ही लोन नही दे देता है। अध्यक्ष महोदय इस बारे में इन्हें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मन्त्री जी ने बताया कि हमने फलां फलां साल मे इतना इतना लोन लिया। मैंने जो सवाल पूछा है वह यह है कि वर्ल्ड बैक से हमने किस काम के लिये कितना कर्जा लिया है और कितना लेने जा रहे हैं। इन्होंने तो दो तीन साल का बता दिया। जो एग्रीमैन्ट आगे का और पीछे का कर रखा है उसका टोटल मिला कर कितना होता है। उसका सालाना ब्याज कितना बनेगा और इन्होंने जिन स्कीमों का नाम लिया है कि हम वर्ल्ड बैक से इन स्कीमों के लिये पैसा ले रहे हैं। ये बातें जानने का अधिकार सदन को भी है कि वे क्या क्या स्कीम्ज है, इनकी डिटेल सदन के मैम्बरों को भी भेजी जानी चाहिए ये सदन के पटल पर रख दें।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह औफिशियल रिकार्ड है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये इस तरह से मांग सकते हैं यह हम इनको दे भी सकते हैं हम इनकॉ सदन की पटल पर भी रख सकते है। अध्यक्ष महोदय, एक बात चौधरी बंसी लाल जी ने कही वैसे तो मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया था और मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ कहने की भी जरुरत नही

है। जब बसी लाल जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त हरियाणा के किसी भी टीचर का तबादला नहीं किया जाता था और कहते थे कि कोई भी मास्टर अपने गांव के 20 किलोमीटर नजदीक नही रह सकता। तो मास्टर जब स्कूल अपनी साईकल पर जाते थे तो वे अपनी साईकल पर थपकी लगाते थे कि चल बेटा बंसी 20 मील की रफतार से। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जितनी सुविधा जितने पे–स्केल के रिवीजन जितने ए० जी० एस० के केस थे और जितने बोनस के केस थे, वे जितने इस सरकार ने दिए है, मैं समझता हूं उतने तो पिछली सरकार ने दिए ही नही है। कोई भी ज्यादती आज कर्मचारियो के साथ नहीं है। इसी तरह से चौहान साहब ने अधिकारियों की बात कह दी। (विघ्न) में तो इनके बारे में नहीं कहना चाहता था लेकिन मुख्य मन्त्री ने जैसा कल कहा था कि बिटोड़े में से गोस्से ही निकलेगे और कुछ नहीं निकलेगा। जब बिटोडे में गोस्से रखते है तो गिनती नहीं होती और जब उसमें रखते हैं तब भी गिनती नही होती लेकिन खजाने में तो एक एक रुपया गिनकर रखा जाता है और गिनकर ही निकाला जाता है। (विघ्न) खजाने मे गिनती का पूरे हिसाब से पैसा होता है यही कारण है जैसे मैंने कल भी अपने जवाब में बताया था कि कोई भी टैक्स हरियाणा सरकार ने नही लगाया है। आज आप हरियाणा के किसी भी वर्ग, से पूछो चाहे वह किसान हौ, व्यापारी हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो कर्मचारी हो यानी सब को ही सरकार ने कोई न कोई रिलीफ दी है और सब इस

बात को मानते भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है।

प्रो० छतर सिंह चौहानः जो महिला कें प्लाट पर कब्जा हुआ है या जो पजांबी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बारे में भी बता दो।

श्री मांगे राम गुप्ताः पंजाबी महिला से आपका क्या लेना देना है? (विध्न) जींद में से हो कर निकल जाना सारा पता लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज यह कहना कि हरियाणा सरकार की– इकोनोमी नही है, खर्चे पर कंट्रोल नहीं है, और सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, ठीक नहीं है क्योंकि आज तक भी हरियाणा की इकोनोमी का इससे अच्छा कंट्रोल नहीं हुआ है। हमने 6 करोड़ रुपये के बजट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया है और सभी वगों को सुविधा देने के बाद सिर्फ 15 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। इसके अलावा इन्होने अधिकारियों के बारे में कहा कि वे गाडियों का मिसयूज करते हैं। सर, बाकायदा कायदे कानून इस बारे में बने हुए है जिस अधिकारी को कायदे कानून से गाड़ी मिलती है, दो सौ रुपये महीने के हिसाब से उसकी तनख्वाह में से काटे जाते हैं और अगर कोई अधिकारी एक महने में चार सौ कि० मी० से ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल करता है तो उससे दो रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे चार्ज' किए जाते हैं और वह तनख्वाह में से कट जाते हैं। (विघ्न) मैं आपके द्वारा सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव हैं जैसा कि मैंने

कल भी कहा था कि यह सरकार सदन को पूरे विश्वास के साथ कहती है कि हम कोई भी पक्षपात नहीं करेगे। (विघ्न) हमने किसानों को जो भी सुविधाएं दी हैं, उसके लिए तो आपने सरकार का धन्यवाद किया नही है। अब आप इस तरह की बात करते हो। पास बुक भी हमने बना रखी है। अध्यक्ष महोदय बहुत सी बातों पर यहां पर चर्चा हुई और उन सभी बातों का मुख्यमन्त्री जी द्वारा और जो मेरे विभाग से संबंधित थी का मेरे द्वारा उत्तर दिया गया और हर प्रकार की तसल्ली करने की कोशिश की गयी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप डिमांडवाइज इन डिमांड पर मत करा लीजिए और इनको पास करा दीजिए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट कें लिए बटाया आता है।

वर्ष 1995–96 के बजट अनुदानों कीं मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble members now voting on demands on the Budget for the year 1995-96 will take place.

First, I will put the cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demands to the vote of the House.

Demand No. 1

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,94,3300t) for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Demand No. 2

Mr. Speaker : Now I put the cut motion on Demand No. 2 given by Sarvshri Bansi Lal and Chhattar Singh Chauhan M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 2 of Rs.61,94,94,000 on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 61,9494,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come In the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 2—General

Administration.

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr. Speaker : Now I put the cut motion on Demand No. 3 given by Sarvshri Bansi Lal and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 3 of Rs. 1,2,39,12,000 on account of Home be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,87,44,12,000 for revenue expenditure and Rs. 4.95,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No . 3—Home.

The motion was carried.

Demand No. 4

Mr. Speaker : Question is

That a sum not exceeding Rs.26,24,83,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 9—Revenue .

The motion was carried.

Demand No. 5

Mr. Speaker : Now I put the cut motion on Demand No. 5, given by Sarvshri Ram Bhajan and Om Parkash Beri M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 5 of Rs. 16,81,11,000 on account of Excise Taxation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 16,81,11,10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course, of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 5—Excise & Taxation.

The motion was carried.

Demand No. 6

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 6, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 6 of Rs.1,57,85,85,000 on account of Finance be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,57,85,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

The motion was carried.

Demand No. 7

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 16,68,78,70,000 for revenue expenditure and Rs. 6,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 7—Other Administrative Service .

The motion was' carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 8. given by Sarvshri Bansi Lal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 8 of Rs. 1,90,81,92,000 on account of Buildings & Roads be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 97,85,59,000 for revenue expenditure and Rs. 92,96,33,000 for capital

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker : Now, I put cut motion on Demand No. 9 given by Sarvshri Chhattar Singh Chauhan and Om Parkash Beni, M.L.As. to the vote of the House. Question is—

That Demand No. 9 of Rs. 5,45,56,03,000 on account of Education be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,45,56,03,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 10, given by Sarvshri Bansi Lal and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 10 of Rs. 3,30,02,06,000 on

account of Medical and Public Health be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is-

Th at a sum not exceeding Rs. 2,53,96,31,000 for revenue expenditure and Rs. 76,05,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 10—Medical & Public Heatlh.

The motion was carried.

Demand No' 11

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 11, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 11 of Rs. 17,39,91,000 on account of Urban Development be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 11,39,91,000 for revenne expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Develo pment.

The motion was carried.

Demand No. 12

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 35,47,51,000 for revenue experdiure. lc granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 12—Labour & Employment.

The motion was carried.

Demand No. 13

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 13 given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

That Demand No. 13 of Rs. 2,39,41,12,000 on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Rs. II-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a -sum not exceeding Rs. 2,36,83,-85,000 for revenue expenditure and Rs. 2,57,27,000 for capital - expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come In the course of payment_ for the year -1995-96 in - respect -of charges under Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Demand No. 14

Mr: Speaker : Now I put cut motion on Demand No: 14 given by Shri Bansi Lal, M.L.A. to the vote of the House:

That Demand No. 14 of Rs. 3,75,76,54,000 on account of Foed & Supplies be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 8,76,38,000 for revenue expenditure and Rs: '3,67,00;16,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 14—Food & Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15.

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand. No- 15 given by Sarvshri Bansi Lal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. to the vote of the House.

That Demand No. 15 of Rs. 6,37,09,20,000 on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is-

That a sum not exceeding Rs. 4,55,82,20,000 for revenue expenditure and 1,81,27,00,000 for Capital expenditure be granted- to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 16 given by Shri Bansi Lal, M.L.A., to the vote of the House.

That Demand No. 16 of R. 69,61 06,000 on account of Industries reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 33,31449,000 tor revenue expenditure and Rs. 36,29,57,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that -will come- in the course of payment -for the Year 1995-96 in respect of charges under -Demand- No: 16—Industries.

The motion was carried.

Demand No. 17

Mr. Speaker : I Now I put cut motion on Demand No. 17 given by Sarvshri Bansi Lal, Chhattar Singh Chauhan and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

That Demand No. 17 of Rs, 1,41,39,11,000 on account of -Agriculture be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,41,39,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year .1995-96 in respect of charges under Demand No. 11— Agriculture.

The motion was carried.

Demand No 18

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No 18. given by Shri Om Parkash Beni, M.L.A. to the vote of the House.

That Demand No. 18 of Rs. 42,61,30,000 on account of Animal Husbandry be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 42,61,19,000 for revenue expenditure and Rs. 11,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect. of charges under Demand No. 18 -Animal Husbandry.

The motion was carried.

Demand Nos. 19 to 21

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 10,68,50,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 19—Fisheries, That a sum not exceeding Rs. 56,39,52,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come In the course of payment for the year 199-5-96 in respect of under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 69,35,16,000 for revenue expenditure be granted to the- Governor to 'defray charges that will come in the course of payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

The motion was carried.

Demand No. 22

Mr. Speaker : Now **I** put cut motion on Demand No. 22 given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A., to the vote of the House.

That Demand No. 22 of Rs. 33,13,38,000 on account of Cooperation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is

That a sum not exceeding Rs. 18,63,29,000 for revenue expenditure and Rs. 14,50,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the Year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operation.

The motion was carried.

Demand No. 23

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 23 given by Shri Om Parkash Beri and Shri Bansi Lal, M.L.As, the vote of the House.

That Demand No. 23 of Rs. 3,35,23,26,000 on amount of Transport be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr: Speaker : Question is—

That a SUM not exceeding Rs. 2,93,89,56,000 for revenue expenditure and Rs. 42,33,70,000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of" payment for the year 1995-96 in respect of charges under Demand No. 23—Transport.

The motion was carried.

Demand No. 24

Mr. Speaker : Now I put cut emotion on Demand No. 24 given by Shri Bansi Lal, M.L.A. to the vote of the House.

That Demand No. 24 of Rs. 3,79,00,000 on account of Toursim be reduced by Rs. 1/-.

The Motion was lost.

Mr. Speaker : Question is-

That a sum not exceeding Rs. 27,00,000 for revenue expenditure and Rs. 3,52,00,000 for capital expenditure be granted to the Governo r to defray charges that will come in, the course of payment for the year, 1995-96 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

The motion was carried.

Demand No. 25

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs, 3,63,53,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 199 5-96 in respect of charges under Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.

The motion was carried.

बिल्ज–

(1) पंडित भगवत दयाल शर्मा आयुर्विज्ञान महाबिद्यालय, रोहतक (अध्यापक सेवा शर्ते) संशोधन विधेयक, 1995

Mr. Speaker : Now, the Technical Education Minister will introduce the Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, 1995 and move the motion for its consideration.

Technical Education Minister (Rao Inderjit Singh) : Sir, 1 _beg to introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma

Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Technical Education Minister will move that the Bill be passed.

Technical Education Minister (Rao Inderjit Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पैशन) संशोधन विधेयक, 1995

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will introduce the Haryana Legislative, Assembly and pension of Members) Amendment Bill, 1995 and also move the motion for its consideration.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir I, beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1995.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting -Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill..

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move.

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved--

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was. carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 10 minutes, ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by 10 minutes.

बिल्ज (पुनरारम्भ) (3) हरियाणा मगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1995

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for

its consideration.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1995.

I also move—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved--

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting- Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the' Bill:

The motion was carried.

Mr. Speaker Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government Ch. Dharambir Gauba) :

Sir, I beg to move—

That the Bill be passed

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो हरियाणा में एक नगर निगम बनी है उसके चौयरमेन के चुनाव का मामला

भी हाई कोर्ट तक गया और इलैक्शन के तीन महीने बाद तक चेयरमैन का चुनाव नहीं करा सके। इसलिये यह बिल बिना चर्चा के जल्द बाजी में पास न करवाएं। जो पंचायती राज विधेयक है, उसके अन्दर नगरपालिका के प्रैजीडैट की टैन्योर एक साल रखी थी, अब इस बिल में 5 साल की रखी है। चेयरमैन के लिये और वाइस चेयरमैन के लिए, इस बारे में मेरा कहना है कि बाकी जगह ऐसा है कि वाईस चेयरमैन का चुनाव एक साल के लिए होता है अतः मेरा सुझाव है कि हमारे यहां पर भी वाईस चेयरमैन का चुनाव एक साल के लिए होना चाहिए।

चौधरी धर्मवीर गाबाः पांच साल का इसलिए किया है ताकि हर साल चुनाव के चक्कर में न पड़ कर, काम समूथली चलता रहे और दूसरे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पंचायती राज एक्ट में भी यही प्रोवीजन है, इसलिये हम यह अमैंडमैंट लाये हैं।

श्री अध्यक्षः म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान के लिए बैकवर्ड क्लास की औरतों का कोटा बाद में तय किया, अगर पहले करते तो ठीक रहता, यह आपकी गलती रही. है।

Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995

Mr. Speaker : Now the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, **I** beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) B.11, 1995.

Sir, **I** also beg to move —

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill. The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill. The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill. The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill. The motion was carried.

Mr Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(5) पजांब भू–दान यज्ञ (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1995

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will introduce the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

Irrigaton Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to introduce the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill betaken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment)Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Bhutan Yagna(Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill,

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Eill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is--

That the Bill be passed.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended by 5 minutes.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Time is extended by 5 minutes.

बिल्ज–

(पुनरारम्भ)

(6) हरियाणा साधारण विक्रय कर (संसोधन) विधेयक, 1995

. **Mr. Speaker :** Now, the Irrigation Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1995 and he will also move the motion for its consideration.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Bill. be Passed

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

प्रो० राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जो उद्वेश्य बताए गए हैं, उसकी लैग्वेज पर मुझे ऐतराज है। इसमें लिखा है ''बेईमान व्यापारी'' यह ''कर की चोरी'' या ''अनियमितता'' लिखें। दूसरे इसमें इन्होने 10 की जगह 15 प्रतिशत किया है इससे टैक्स इवेजन नहीं रुकेगा, इसमें यूनिफोरमिटी लाएं। जैसे डी नेचरड सिपरिट हैय उसका टैक्स चंडीगढ़ में 50 पैसे है और कालका में 6 रुपये प्रति लिटर है। एडजेसैटं स्टेट्स के साथ टैक्स में यूनिफोरमिटी लाएं और

व्यापारियों के लिये जो ''बेईमान'' शब्द लिखा है, उसको बदला जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stand's adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

***2.14 hrs,**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 24th March, 1995.)